

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1980

खंड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भानिवार, 15 मार्च, 1980

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)23
अतांरांकित प्र न एवं उत्तर	(11)28
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग:— उपाध्यक्ष द्वारा 14-3-1980 को दी गई रूलिंग पर पुनः विचार सम्बन्धी	(11)48
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट	(11)49
वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)54
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— चौधरी राम लाल वधवा द्वारा	(11)64
वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)64
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	

डा. मंगल सैन द्वारा	(11)73
वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)73
औचित्य प्रश्न:- बजट पर आम चर्चा के समय वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री की सदन में उपस्थिति सम्बन्धी	(11)77
वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)78

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 15 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे।

Hotels and Motels in the State

***1503. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the names of places where hotels and motels are being run by the Tourism Department in the State together with the details of income earned and expenditure incurred by them during the year 1978-79?

Food & Supplies Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar): No. Hotels and Motels are being run by the Tourism Department in the State. The Haryana Tourism Corporation, however, is running a number of Tourist Complexes in different parts of the State. Some of these complexes have motels also. The income and expenditure statement (un-

audited) in respect of the Tourist Complexes for 1978-79 is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the income earned and expenditure incurred on the various units during the year 1978-79.

(Figures in Laks)

Sr.No.	Name of the Places	Income earned	Expenditure incurred
1	Badkhal	25.21	23.59
2	Surajkund	8.32	7.38
3	Faridabad	4.29	3.88
4	Hodel	8.02	7.21
5	Hissar	5.95	5.66
6	Rohtak (Muna)	4.59	4.26
7	Rohtak (Tilyar)	12.02	11.81
8	Bhiwani	1.94	1.99
9	Jind	0.70	0.78
10	Panipat	30.30	29.61
11	Smalkha	3.72	3.40

12	Sonepat	3.35	3.14
13	Pinjore	7.69	8.41
14	Panchkula (Red-Bishop)	3.06	3.11
15	Panchkula (Youth Hostel)	0.44	0.33
16	Karna Lake (Uchana)	14.39	13.34
17	Oasis (Uchana)	18.88	18.18
18	Pipli	6.12	5.75
19	Gharounda	0.62	0.75
20	Sohna	4.29	3.53
21	Gurgaon	3.87	2.92
22	Dharuhera	5.92	4.63
23	Sultanpur	1.81	1.48
24	Narnual	2.00	2.06
25	Taoru	0.30	0.45
	Total	179.80	167.65

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने होटल और मॉटल पर जो खर्चा बताया है, क्या इसमें इनके किराये, भाड़े और रख-रखाव का खर्चा भी शामिल है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: वैसे तो इस सप्लीमेंटरी क्वै चन की मूल प्र न से कोई रैलेवैंसी नहीं है लेकिन फिर भी मैं मॅबर साहिब की जानकारी के लिए बता देता हूँ उन्होंने क्वै चन में खर्च के बारे में जिक्र किया है, वह स्टेटमेंट में दिया हुआ है.....

श्री अध्यक्ष: डा० साहिब, मैं आपका सवाल समझ नहीं सका, किराये भाड़े और रख-रखाव से आपका क्या मतलब है?

डा० मंगल सैन: मेरा मतलब है पी०डब्ल्यू०डी इनकी मैन्टेनॅंस पर जो खर्च करती है, क्या वह खर्चा भी इसमें शामिल है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: टोटल एकपैंडीचर जो हुआ है वह मैंने अन्वै चर में दे रखा है।

Mr. Speaker: You Can state that the expenditure on maintenance has been included in this expenditure or you have not got the information at present.

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मेरे पास अलग-2 इन्फर्मॅशन नहीं है, टोटल एक्सपैंडीचर जो इन्कर हुआ है, उसकी डिटेल् दे रखी है।

Mr. Speaker: Is the expenditure on maintenance been included in this expenditure?

Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar: Yes, Sir.

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट ले की हैं, उसमें जींद, पंचकुला(रैड बि 1प) नारनौल, ताउडू, धरोंडा और भिवानी में जो टूरिस्ट कम्पलैक्स है उनमें घाटा बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की तकलीफ गवारा करेंगे कि घाटे का क्या कारण है?

Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar: Speaker, Sir, our Tourism Corporation came into being in the year 1974. भारू में इनकी मैन्टेनेंस पर ज्यादा ऐक्सपेंडिचर होता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड जब नई-2 एस्टेबलि 1 की जाये तो खर्चा ज्यादा होता है। ये कम्पलैक्स डे-बाई-डे तरक्की कर रहे हैं और आस्ता आस्ता अपनी ठीक जगह पर आ रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म कारपोरे इन दोनों तरक्की कर रहे हैं। मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारी टूरिज्म कारपोरे इन के टूरिज्म कम्पलैक्स, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में बहुत अहम जगह रखते हैं, इससे जहां हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट का नाम आता है वहां हरियाणा का नाम भी उंचा हो जाता है।

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट में जिन टूरिज्म कम्पलैक्स के नाम गिनाये हैं, क्या इनके अलावा भी

कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जहां पर सरकार खोलना चाहती है, अगर खोलना चाहती है तो कहां-कहां?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: 25 कम्पलैक्स है जो इसवक्त रन कर रहे है। कुछ प्रोजेक्ट्स और है जो सरकार के अंडर कंसिडरेशन है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि हरियाणा टूरिज्म कारपोरेट्स का नाम हरियाणा में ही मंजूर नहीं बल्कि बाहर भी मंजूर है। क्या मंत्री महोदय हरियाणा स्टेट के बाहर मंसूरी, शिमला, कसौली वगैरा हिल स्टेशनों पर जहां पर बाहर से बहुत टूरिस्ट आते है, टूरिस्ट कम्पलैक्स खोलने के प्रयत्न करेंगे ताकि टूरिज्म कारपोरेट्स को भी बढ़ावा मिले और हरियाणा के नौजवानों को नौकरियां भी दी जा सके।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, नेचर ने हमें कोई हिल स्टेशन नहीं दिया। जिस तरह शिमला, जम्मू एण्ड कश्मीर वगैरा हिल स्टेशन है, ऐसे हिल स्टेशन हमारे पास नहीं है और न ही हमारे यहां कोई खास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जगह है। राजस्थान में ऐसी बहुत सी साइट्स है लेकिन हमारे यहां नहीं है।

डा० मंगल सैन: हरियाणा में टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिये नैचुरल रिसोर्सिज नहीं है, यह बात तो स्पष्ट है।

लेकिन इनका सवाल तो यह है कि दूसरे हिल स्टे ानों पर टूरिस्ट कम्पलैक्स खोलने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: हमारे यहां कोई हिल स्टे ान नहीं है, जो कुछ है उनको मैं हिल-रौक्स ही कहूंगा। (व्यवधान) हमारे यहां कंसल्टैंसी विंग है जो.....(व्यवधान एवं भाोर).....

श्री अध्यक्ष: इनका मतलब कंसल्टैंसी से नहीं है,, इनका मतलब यह है कि क्या हरियाणा गवर्नमेंट अपने कम्पलैक्स बाहर के हिल स्टे ानों पर खोलने का विचार कर रही है?

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय तैयार होकर ही नहीं आते। (व्यवधान)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैंबर साहब जरा भ्रान्ति से सुनेंगे तो जरूर बताउंगा। जहां तक दूसरी स्टेटों के हिल स्टे ानों पर टूरिस्ट कम्पलैक्स खोलने का सवाल है, हम पूरा प्रयत्न करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। अगर कोई स्टेट खोलने के लिये परमिट कर देती है तो हम खोलने के लिये बिल्कुल तैयार रहते हैं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन कम्पलैक्स में लौस हुआ

है, क्या यह लौस चौधरी भजन लाल के भासनकाल का है या पहली सरकार के भासनकाल का है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जो मैंने स्टेटमेंट दे रखी है, यह 1978-79 से ताल्लूक रखती है और पूरे ईयर को कवर करती है।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में लिखा है कि यह अन-आडिटिड एक्सपेंडिचर है। क्या आप बतायेंगे कि इसका आडिट कब तक हो जाएगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसके आडिटर ला कम्पनी बोर्ड से आते हैं, जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हम उनको रिपीटडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आडिटर भेजें। टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म कारपोरेट इन बार-बार एफर्ट्स करता रहा है और अभी पिछले दिनों मेरी एडवाइस पर चीफ सैक्रेटरी ने उनको एक लैटर भी लिखा था कि आडिटर भेजें जाएं अब उन्होंने हमारी बात मान ली है और जल्दी ही आडिट करवा लिया जायेगा।

चौधरी राम किान: जो कम्प्लैक्स घाटे में चल रहे हैं, क्या सरकारके विचारधीन कोई प्रोजेक्ट है कि उनको बन्द कर दिया जाये?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: बन्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप स्टेटमेंट को पढ़ें, पहले जो कम्प्लैक्स घाटे

में थे अब वे प्रोफिट में चल रहे हैं और डे-बाई-डे लौस कवर अप होता जा रहा है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, जो टूरिस्ट कम्पलैक्स बड़खल में बनाया हुआ है, वहां पर लडके और लडकियां भाराब पीकर गलत आचरण करते हैं। क्या सरकार के नोटिस में ऐसी कोई रिफ्लेक्शन है अगर है तो सरकार इस प्रकार के गलत आचरण को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही कर रही है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: ऐसी रिफ्लेक्शन न तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के नोटिस में है और न ही किसी आफिसर के नोटिस में है कि वहां पर लडके और लडकियां भाराब पीकर बदअमनी फैलाते हैं। हर कम्पलैक्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव और ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने के लिये पहले से ही इन्तजाम किया हुआ है।

श्री देवी दास: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सेनीपत में जो टूरिस्ट कम्पलैक्स है, उसको रिफ्लेक्शन करने का कोई विचार है, अगर है तो इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल इससके संबंधित नहीं है।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: इस सवाल का मुल सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूं। हम इस कम्पलैक्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं इसके लिये

कोई अच्छी साइट देख रहे हैं। अच्छी साइट मिल जाये तो रिफ्ट करेगें क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड बढ़ गई है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि इस तरह का होटल या मोटल कैथल में भी खोला जायेगा, यदि खोला जाएगा तो कब तक खोला जायेगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, कैथल में खोलने की तजवीज जेरे गौर है। वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने यह अन्डरटेकिंग दी थी कि वह जमीन देगी। उन्होंने एक साइट आफर भी की है। इसके बारे में बातचीत चल रही हैं अगर वह बातचीत सिरे चढ़ जाती है तो वहां हम अब य होटल या मोटल खोल देंगे।

स्वामी आदित्यवे तः अध्यक्ष महोदय, भिन्न-2 पर्यटन केन्द्रों में एक ही क्वालिटी के खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग है। क्या मंत्री जीउसको एक ही लेवल पर लाने की कोशिश करेगें? (विधान)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकरसाहब, एक सी चीज के रेट्स कम्प्लैक्सज में तकरीबन हर जगह एक ही है। फर्क जो है वह रहने की हट्स और कमरों आदि के रेट में है। वहां हट्स भी बनी हुई है और कमरे भी बने हुये हैं। कौमन मैन को दिक्कत न हो इस बात को ध्यान में रखते हुये बिस्तर के साथ हट हम पांच रूपये में देते हैं जबकि कमरों के चार्जिज कुछ ज्यादा है।

कामरेड भांकर लाल: क्या मंत्री जी बतायेगें कि चौटाला के नजदीक अबूब भाहर में जो टूरिस्ट होटल है उसमें नुकसान है या नफा है। क्या वह होटल जुआ खेलने या भाराब पीने के लिये है या लोगों ठहरने के लिये है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकरसाहब, अबूब भाहर के अन्दर जो रैस्टोरां और कम्पलैक्स बना है, वह उस वक्त का बना हुआ है, जब यह मिनिस्ट्री चौधरी देवी लाल जी के पास थी और वे चीफ मिनिस्टर थे। (विधन)

चौधरी उदय सिंह दलाल: क्या आप उस वक्त मिनिस्ट्री में नहीं थे?(विधन)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: उस दौरान मैंने इस्तीफा दे दिया था। (विधन)

चौधरी उदय सिंह दलाल: बाद में भी तो आपने औथ ली थी। (विधन)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: दोबारा जब मैंने औथ ली थी तो उस वक्त यह टूरिज्म डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिया गया था। कुछ महीने के बाद दिया गया था। पहले इसलिये नहीं दिया गया था क्योंकि उस समय अबूब भाहर में यह कम्पलैक्स बन रहा था और मेरी राय में यह गलत साईट थी।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन घाटों में इनकम्पलैक्सिज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे वेटर्ज हैं, कुकस है क्या उनका बोनस आदि भी शामिल है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मैंने स्पीकर साहब, अर्ज किया है कि यह कम्पलीट स्टेटमेंट है,, इनकम्पलीट नहीं है। इसमें सब चीजें शामिल है।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को दिया गया बोनस इसमें कितना शामिल है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, बोनस के बारे में अगर ये पूछना चाहते हैं तो सैपरेट नोटिस दें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या झज्जर, बहादुरगढ और गोहाना में भी इस तरह के कम्पलैक्स बनाने की बात सरकार के विचारधीन है? (विधान)

चौधरी गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, कोई भी मेंबर अगर हमें ठीक साईट बतायेगा, जहां पर टूरिजम कम्पलैक्स की आवकता हो जहां पर वायबिलिटी हो, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे।

Tourism Department's Restaurant at Jind

***1512. Chaudhri Satvir Singh Malik:** Will the minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) the total expenditure incurred on the construction of Tourism Departments' Restaurant building at Jind;

(b) the total number of persons employed in the above said restaurant alongwith their monthly salaries and the amount of TA/DA drawn by them during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 (up to 31-12-1979_;

(c) whether the restaurant referred to in part(a) above has been running on profit during the period mentioned in part (b); if so, the profit so earned separately; and

(d) if reply to part (c) be in the negative the amount of loss suffered during the period mentioned in part (b) together with the steps, if any, taken or proposed to be taken to make this restaurant a profitable venture?

Food and Supples Minister(Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) A sum of Rs. 2.07 Lakhs was incurred by Tourism Department on the construction of restaurant at Jind which now stands transferred to Haryana Tourism Corporation with effect from 1-9-1974.

(b) The requisite statement is placed on the Table of the House (Annexure"A").

(c) No.

(d) The operational loss suffered by the Haryana Tourism Corporation is given below which is subject to audit:-

1977-78 Rs. 12058/-

1978-79 Rs. 7995/-

1979-80 Rs. 78/-

(up to 31-12-79)

As a result of strict measures taken to control food/fuel cost and also to reduce over-head expenses the operational loss is decreasing considerably year after year as is evident from the above figures.

ANNEXURE 'A'

	Month	No. of persons employed	Amount of salary	Amount of TA/DA
1977-78	April, 77	8	2369-80	24-90
	May, 77	7	2101-10	50-10
	June, 77	7	1878-40	32-10
	July, 77	7	2259-90	67-00
	August, 77	7	2283-85	51-90
	September,	8	2383-65	44-85

	77			
	October, 77	8	2853-20	79-15
	November, 77	8	3661-40	28-55
	December, 77	8	2598-55	36-80
	January, 78	7	2324-30	84-35
	February, 78	7	2226-40	42-40
	March, 78	7	2216-45	287-00
Total			28157-00	829-10
1978-79	April, 78	7	2227-70	-
	May, 78	8	2466-90	172-65
	June, 78	8	2450-00	57-10
	July, 78	7	2322-85	79-90
	August, 78	8	2143-10	24-00
	September, 78	7	2501-95	49-60
	October,	7	2860-35	124-65

	78			
	November, 78	8	2300-05	9-60
	December, 78	7	2658-90	108-20
	January, 79	7	2479-65	11-95
	February, 79	7	2233-45	113-15
	March, 79	9	2669-10	80-00
Total			29314-00	830-80
1979-80	April, 79	7	2392-65	-
	May, 79	8	2308-70	58-30
	June, 79	8	2480-95	-
	July, 79	6	2492-35	49-70
	August, 79	6	2223-35	312-90
	September, 79	6	1822-70	5-30
	October, 79	6	1850-95	50-50
	November,	6	1794-65	10-60

	79			
	December, 79	5	1540-50	10-60
Total			18906-80	497-90

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के पार्ट(बी) के पवाब में बताया है “the requisite statement is placed on the Table (Annexure ‘A’).” But sir, we have not received this Annexure. I do not know whether that is placed on the Table of the Minister or anybody else because that is not placed on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष: होना तो चाहिये। (गोर)

विरोधी दल के बहुत से सदस्य: नहीं है। (गोर)

Mr. Speaker: I would request the Government to send the replies complete in all respects in future.

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, वैसे तो हमने रिप्लाइं पूरी भेजी है लेकिन अगर जनाब फरमाते हैं तो मैं इसको चैक कर लूंगा क्योंकि मेरेपास तो रिप्लाइं कम्पलीट है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे हाउस के सामने पढ कर सुना देता हूँ। (विधन)

श्री अध्यक्ष: मलिक साहिब को एक कापी दे दें क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है। (इस समय अनैक चर 'ए' की एक प्रति चौधरी सतबीर सिंह मलिक को दी गई)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, आपके आदेशानुसार क्वेंचंज का कम्पलीट जवाब मੈंबर्ज को आधा घन्टे पहले मिल जाना चाहिये परन्तु सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वह इन-कम्पलीट है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो दिया गया है परन्तु मੈंबर साहब ने कहा था कि इस जवाब के साथ अनैक चर नहीं लगा था। मैंने गवर्नमेंट को कह दिया है कि कम्पलीट जवाब भेजा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस अनैक चर को पढा जाये तो मिनिस्टर साहब पढ देते हैं। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनैक चर पढने में टाइम ही लगेगा। इसमें तोइतना ही होगा कि जनवरी में कितने आदमी थे और फरवरी में कितने थे। अगर आप को एम्पलाइज के बारे में कोई ग्रिवैन्सिज है या कोई कम्प्लैन्ट है तो उसके बारे में आप सवाल पूछ लें।

डा० मंगल सैन: मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास सारी स्टेट के एम्पलाइज की तरफ से कोई रिप्रेजैन्टेशन आयी थी, यदि आई थी तो क्या कदम उठाये गये हैं?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। पिछले दिनों कम्पलैक्स के कर्मचारियों ने गैर कानूनी तौर पर तालाबन्दी की, हडताल की। बिना किसी नोटिस के, बिना डिमान्ड के भेजे, हडताल की। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें मदद दी जिससे हडताल के बावजूद भी हमारे कम्पलैक्स चलते रहे।

जब कम्पलैक्स के एम्पलाइज ने बिना नोटिस के तालाबन्दी कर दी तो डा० मंगल सैन ने इन्टरवीन किया। इन्होंने मुझ से कहा कि आप उनसे बात कर लो। मैंने उनसे बात की। मैंने उनको यही कहा कि आप लोगों ने यह गलत कदम उठाया है। अगर आपकी कोई ग्रीवेंस थी तो हमारे नोटिस में लाते। आप के साथ कोई गैर-इंसाफी हो रही थी तो हम जरूर इन्साफ देते। आखिर में उन लोगों ने अनकन्डी नली हडताल वापिस ली। उसके बाद मैंने लेबर कमी नर को उनका केस रैफर कर दिया। उनसे यही कहा कि आपकी जो भी डिमान्ड है उनको बतायें और जो भी लेबर कमी नर निर्णय देगा उस पर मैं विचार करूंगा उसके बाद फैयला करेंगे।

डा० मंगल सैन: क्या लेबर कमी नर ने कोई रिपोर्ट दी है और अगर दी तो क्या उसे कन्सिडर किया गया है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मेरी इतलाह के मुताबिक कर्मचारियों ने कुछ फ़ैसलाजात किये हैं उनकी टोटल डिमान्डज 27 थी, उनमें से 17 डिमान्डज टूरिजम डिपार्टमेंट ने मान लीऔर बाकी की डिमान्डज वरकर्ज ने वापिस ले ली।

चौधरी राम लाल वधवा: मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या लेबर कमी नर की कोई रिपोर्ट आयी या नहीं?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: जब झगड़ा ही खत्म हो गया तो मुझे रिपोर्ट मांगने की जरूरत ही नहीं पडी।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि उनमें से कितने एमपलाइज परमानैन्ट थे और कितने टैम्परेरी थे?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मेरे पास अलग-2 रिपोर्ट नहीं है। वैसे आपके सप्लीमेंटरी का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है कि उनमें कितने रैगुलर हैऔर कितने एडहोक पर हैं। अगर हाउस चाहेगा तो मैं सारी इन्फर्मे अन इन-राइटिंग भिजवा दूंगा।

Mr. Speaker: Malik Sahib, your question was-

“(b) the total number of persons employed in the above said Restaurant alongwith their monthly salaries and

the amount of T.A./D.A. drawn by them during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 (up to 31-12-1979)",

This supplementary has no connection with this question.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, अगर इस सप्लीमेंटरी का भी जवाब नहीं दे सकते तो फिर यह सरकार किस बात का जवाब देगी?

श्री अध्यक्ष: नोट फार पैड पर अगर इनके पास जवाब है तो दे दें वरना जवाब आफ हैंड नहीं दिया जा सकता है।।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया कि लेबरकमी नर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मैं आपके जरिये यह जानना चाहता हूँ कि उनको यह कैसे पता लगा कि उनकी इतनी डिमान्डज मंजूर हो गई और इतनी डिमान्डज मंजूर नहीं हुई है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मेरा डिपार्टमेंट है। मेरा फर्ज है कि जो भी डिपार्टमेंट की बात हो उसको सैटल करूँ। मैं भुरु से ही यह देखता रहा हूँ कि उन वरकर्ज के साथ कोई बे-इन्साफी न हो जाये। इस नाते से मैंने एडिगल चीफ सैक्रेटरी की डियूटी लगायी। जब वरकर्ज नेमान लिया कि हमारी डिमान्डज पूरी हो गई है तो मं बाद में खुद वरकर्ज से मिला कि आपको कोई डिमांड तो नहीं है।

Terminated/Re-instated Drivers and Conductors of Haryana Roadways

***1469 Shri Hira Nanad Arya:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether the Transport Department imparts any refresher training course to the conductors;

(b) the number of drivers and conductors whose services were terminated due to the recent strike by Roadways Workers and what were their demands and action taken in this behalf;

(c) whether any of the employees referred to in part (b) above have been re-instated; if so, the number thereof?

परिवहन मंत्री(श्री जगननाथ):

(ए) हां

(बी) चालक – 80

परिचालक— 72

इस हड़ताल के लिये यूनियन की ओर से विभाग को कोई मांग पत्र नहीं दिया गया था।

(सी) स्पीकर साहब, मैं इसपार्ट के जवाब को जो हमने पहले आप को भेज दिया था उसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इन टरमिनेटिड में से 20 चालक हमने लगाये है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकरसाहब, वैसे तो मिनिस्टर साहब ने जवाब दूसरा दिया है कि हमने उनमे से और कुछ लगाये है। जिस वक्त यह हडताल हुई, उसमें 80 चालक और 72 कन्डक्टर्ज टरमिनेट किये गये थे लेकिन मैने तो इसके साथ ही दूसरे वरकर्ज का भी पूछा है कि वे कितने टरमिनेट किये गये। जब ये वरकर्ज चीफ मिनिस्टर साहब से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मिले तो यह आ वासन दिया गया था कि जितने भी एम्पलाइज है, सब को वापिस लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, दूसरे वरकर्ज के बारे में जो सवाल है वह आपके मेन क्वै चन में भामिल नहीं है। अगर आप इनके बारे में भी पुछना चाहते है तो अलग से नोटिस दे।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, जब यह हडताल री-कन्साईल हुई तो उस समय चीफ मिनिस्टर साहब से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से उन एम्पलाइज की बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान उन्हे यह आ वासन दिया गया था कि सभी एम्पलाईज को री-इनस्टेट कर दिया जायेगा। मैं आपके जरिये मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सभी मूलाजमों को री-इनस्टेट कर दिया जायेगा?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, ऐसा कोई आ वासन नहीं था। 7-9-1979 को हड़ताल भारु हुई और 15-9-1979 को खत्म हुई। 10-9-1979 को मैने स्टेटमैट दी कि 11-9-1979 तक

24 घन्टे के अन्दर अगरकोई मुलाजिम ड्युटी पर नहीं जाएगा तो उस के खिलाफ एकान लेगें। स्टेटमेंट देने के बाद कुछ आने भुरू हो गए, कुछ नहीं आए। उसके बाद हमने एकान हलया। जो 302 एम्पलाईज एडहाक पर थे उनकी सर्विस टरमिनेट कर दी और 808 को सस्पेन्ड किया, जिनको बाद में लगाया है। 302 एम्पलाईज के बारे में ऐसा हुआ कि सी.एम. साहब, मै, विभाग के अधिकारी और यूनियन के कर्मचारियों के बीचबातचीत हरियाणा भवन में हुई। उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जितने भी एम्पलाईज हडताल के दौरान लगे हैं उन सभी को लगाया जाये लेकिन उनकी योग्यता को जरूर देखा जाये कि कोई ऐसा ड्राइवर तो नहीं है जिसको दिखाई ही न देता हो, उसकी ऐज और क्वालीफिकेन तो ठीक है। जो 302 एडहाक एम्पलाईज थे जिनकी सर्विस टरमिनेट कर दी थी उनके बारे में यह फैसला लिया गया कि उनको भी लिया जाए लेकिन जो हडताल में लगे हैं उनको भी दो-एक की रेगो से लियाजाये। 302 एम्पलाईज में 80 चालक, 72 परिचालक, 92 वर्क टाप एम्पलाईज और 53 दूसरे एम्पलाईज थे इनमें से 20 चालक लग चुके हैं। ज्यो ज्यो जगह खाली होती जाएगी हम इनको लगाते जाएंगें। सब को लगा देगें। जब तक ये सारे नहीं लग जाते, बाहर से कोई आदमी नहीं लेगें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 302 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 2 और 1 की रेगो से लगाया जाएगा। मेरे पास ऐसी इंफर्मेन है कि 700

कर्मचारियों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करली गई है उसके हिसाब से वे सभी कर्मचारी अब तक लग जाने चाहिये थे? इन कर्मचारियों को अब तक क्यों नहीं लिया गया, इसका क्या कारण है?

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चालक हमने लगा दिये थे लेकिन कन्डक्टर के इतने स्थान नहीं हैं। ज्यों ज्यों बसे आती जाएगी, उसी हिसाब से उनको भी लगाते जायेंगे। जो कर्मचारी हडताल में हटाये गये थे उनको और हडताल के दौरान रखे गये कर्मचारियों को 2 और 1 की रे तो के हिसाब से लगाया जा रहा है। कोई पर्टीकुलर केस उनके नोटिस में हो तो बता दें।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूँ कि जो चालक या परिचालक हडताल में शामिल थे क्या उनमें से कुछ एक पर सरकार की ओर से मुकदमा भी चलाया जा रहा है?

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, ऐसे 18 केसिज हैजिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इन 18 केसिज में से 12 केसिज तो दिल्ली पुलिस के हैं जिनका हमारे से कोई संबंध नहीं है, बाकी 6 केसिज हरियाणा पुलिस के हैं उनका मुकदमा अदालत में चल रहा है। इन केसिज का फैसला अदालत ने ही करना है।

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिन चालको और कन्टक्टरों

को हडताल के दौरान हटाया गया था या वे बर्खास्त कर दिए गए थे और उनको जगह दूसरे रख लिये थे, उनके बारे में मुख्य मंत्री महोदय के साथ बैठ कर यह फैसला हुआ था कि इन कर्मचारियों को 2 और 1 की रे गो के हिसाब से दुबारा काम पर ले लिया जाये। उसके बाद 750 के करीब इन्होंने और नये कमचारी भर्ती कर लिए हैं। मंत्री महोदय ने अभी यह भी बताया है कि उनमें से 20 कर्मचारियों को दुबारा लगाया जा चुका है। जबकि अब तक सभी को दुबारा काम पर ले लिया जाना चाहिये था। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन बाकी के कर्मचारियों को दुबारा सर्विस में कब तक लेने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: इस का जवाब तो पहले ही आ चुका है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी परिवहन मंत्री ने अपने जवाब के दौरान बताया है कि हडताली कर्मचारियों को और हडताल के दौरान लगे कर्मचारियों को 2 और 1 के रे गो के हिसाब से लगा दिया जाएगा तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि हडताल के दौरान लगे कर्मचारियों को जब भर्ती किया गया था क्या उस समय उनको सर्विस में लेते वक्त उनको योग्यता को ध्यान में नहीं रखा गया था? अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनकी योग्यताओं की दोबारा जांच की जायेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी योग्यता की दोबारा जांच करने की क्या आवश्यकता है?

श्री जगननाथ: अध्यक्ष महोदय, जिस समय हडताल हुई उस समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक डिपो के जी.एम. और टी.एम. ने लोगों की सुविधा के लिए जल्दी में कुछ कर्मचारी लगालिये थे। उस समय उनकी योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया था। इस दौरान 1116 कर्मचारी हमने लगाये थे। भिन्न-2 कैटेगरीज के 778 कर्मचारियों के केसिज सकुटेनाइज किये गये थे। अब तक उन में से 606 लगाये जा चुके हैं और 172 लगाये जाने बाकी हैं। इनमें से भी जितने कर्मचारी योग्य पाये जायेंगे, उन सभी को लगा लिया जाएगा।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि रोहतक डिपो में 4 कर्मचारी लगाए जाने के लिए एस.टी.सी. साहब के आर्डर भी गये थे लेकिन उन आर्डरों को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इस का क्या कारण है?

श्री जगननाथ: मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जिन कर्मचारियों ने स्ट्राइक में भाग लिया था तथा उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो चुके हैं, उनके केस वापिस लेने की कोई बात सरकार के विचारधीन है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, स्ट्राइक इस काज के लिये की गई थी कि एक परिचालक को ह्यूमिलियेट किया गया था और उसे सर्विस से निकाल दिया गया था। क्या उसको सर्विस में वापस लेंगे?

श्री जगननाथ: अध्यक्ष महोदय काज यह था कि सी.एम. साहब की फ्लाइंग स्काड के अन्दर विजिलेंस डिपार्टमेंट के आदमी भी होते हैं। जब इस फ्लाइंग स्काड ने कन्डक्टर को पकड़ा तो वह जाली टिकटे पंचकर रहा था। वह कन्डक्टर वैसे भी मेरे हल्के से गुजर रहा था। उसको इस फ्लाइंग स्काड ने पकड़ लिया। उस पर केस बना कर अदालत में पे । किया गया। वहां पर उसकी जमानत नहीं हुई। उसके बाद वह सै । न कोर्ट में भी गया परन्तु वहां पर भी उसकी जमानत नहीं हुई। यह सारे का सारा झगडा वहां से भुरू हुआ। यह हुल्लडबाजी और नारेबाजी अदालत में जाने से ही भुरू हो गई थी। रोहतक के अन्दर यह खबर फैलाई गई कि 4 ड्राईवर्ज और 2 कन्डक्टर्ज को पुलिस ने मार दिया। करनाल डिपो में भी ऐसी ही अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह फैलाने में कुछ हमारे आपोजी न के भाइयों के भामिल होने की भी संभावना है। हडताल करने से पहले न उनकी कोई डिमान्ड थी और न ही कोई नोटिस दिया गया था।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की हडताल के पीछे किसी ग्रुप या किसी पोलीटीकल पार्टी का तो हाथ नहीं था?

श्री जगननाथ: ऐसा भी हो सकता है।

श्री मूल चन्द मंगला: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिन कन्डक्टरों को भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग देने की भी कोई व्यवस्था है?

श्री जगननाथ: स्पीकरसाहब, जिन कन्डक्टरों को भर्ती किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से व्यवस्था है। यह ट्रेनिंग उन कन्डक्टरों को दी जाती है, जो नए भर्ती किये जाते हैं। यह ट्रेनिंग एक महीने की दी जाती है। इस अवधि में उनको यह बताया जाता है कि कैसे टिकट काटनी है कैसे पंचिंग करनी है। ऐसी बातों का उन्हें ज्ञान दिया जाता है।

श्री गुलजार सिंह: सपीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 302 जो एडहाक कर्मचारी थे उनको और हडताल के दौरान लगे कर्मचारियों को 2 ओर 1 की रेगुलेशन के आधार पर दुबारा लिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हडताल के दौरान लगे कर्मचारियों की योग्यता की जांचके लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया हैं?

श्री अध्यक्ष: उनके लिए क्वालिफिकेिंज लेड डाउन है।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: स्पीकरसाहब, जब यह स्ट्राइक हुई तो बहुत से कन्डक्टरों स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहते थे और

उनके द्वारा स्ट्राइक में हिस्सा न लेना चाहने पर भी , उनको जबरदस्ती रोका गया, मैंने उस वक्त महकमें के मिनिस्टर की नालेज में यह बात ला दी थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एस.पी.,डी.सी. और जिले का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्पोरेशन कर रहा था कि वे लोग ड्यूटी पर आ जाएं। हरके कर्मचारी के पास जाकर यह कहा गया कि वे हडताल न करें और ड्यूटी पर आ जाएं लेकिन उन्होंने जानबूझ कर हडताल की और वे वापिस नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल पर यह आखिरी सप्लीमेंटरी है (व्यवधान) हमने इस सवाल पर पहले ही पन्द्रह मिनट ले लिये हैं। (व्यवधान)

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय पहले ही जनवादी विचारों के हैं। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ केस बने हुये हैं, उनको विदर्रा करने के लिए नये सिरे से पुनर्विचार किया जायेगा?

श्री जगननाथ: कोई विचार नहीं है। (व्यवधान)

कई आवाजें: स्पीकर साहब, इस पर आधे घन्टे का डिस्कशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल पर मैं पहले ही पन्द्रह मिनट दे चुका हूँ। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैंने तो एक भी सप्लीमेंटरी नहीं पूछी है, आपने मुझे कोई टाईम नहीं दिया है। हमारे यहां बैठने का क्या फायदा जब हमको सवाल ही नहीं पूछने दिया जाता।

श्री अध्यक्ष: आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकरसाहब, पौना घंटा हो गया है और मुझे एक सैकन्ड भी नहीं दिया गया है कमसे कम पौना घंटा में एक सैकन्ड तो मुझे भी मिल जाना चाहिये (व्यवधान)। हम भी चुने हुये प्रतिनिधि हे (व्यवधान) जब हमो बोलने ही नहीं दिया जाता, लोगों के बारे में सवाल ही नहीं पूछने दिया जाता है तो हम यहां किस लिये बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पूरे सेशन में आपने भायद सबसे ज्यादा समय लिया है। जो नये मँबर खडे होते है उनको सबसे पहले अपनचुनिटी देना मेरा फर्ज है। (व्यवधान) चौधरी गंगा राम
Please sit down (व्यवधान)

चौधरी गंगाराम: आप मुझे बोलने नहीं दे रहे है आप कहे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूँ। हमारे यहां पर बैठने का क्या फायदा है (व्यवधान)

Mr. Speaker: I Will name you, Mr. Ganga Ram, if you disturb the proceedings of the House another time. This sort of habitual interruptions and obstructionist tendencies will not be allowed in this House.

Persons Registered with the Employment Exchanges

***1488. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Public Works (Public Health) be pleased to state-

(a) the district-wise total number of M.A., B.Eds., B.A., B.Eds and J.B.Ts. registered with the Employment Exchanges in the State at present ; and

(b) the steps taken or proposed to be taken for providing employment to the persons referred to in part (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) शिक्षा विभाग राज्य की योजना स्कीमों तथा कार्यक्रमों के द्वारा उपरोक्त 'क' भाग के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के अवसर उत्पन्न (जनरेट) करता है।

विवरणी

जिलावार 31-12-1979 को राज्य के रोजगार कार्यालयों में रोजगार सहायताहेतू प्रतीक्षा कर रहे एम0ए0/बी0ए0/बी0एड0 व जे0बी0टी0 प्रार्थियों की संख्या निम्न है-

जिले का नाम	प्राथियों की संख्या एम.ए/बी.ए/बी.एड.	जे.बी.टी.
1	2	3
अम्बाला	1174	864
कुरुक्षेत्र	716	408
करनाल	664	534
रोहतक	1560	1360
सोनीपत	1050	1078
जीन्द	508	309
भिवानी	777	192
गुड़गांव	681	274
महेन्द्रगढ़	970	301
हिसार	1046	421

सिरसा	186	175
फरीदाबाद	757	412
कुल	10089	6328

नोट: एम.ए., बी.एड. की सूचना अलग से एकत्रित नहीं की जाती।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमेंट ने कोई डैफिनिट योजना बनाई है कि इतने समय के अन्दर इन सब रजिस्टर्ड लोगों को एबजार्ब कर लिया जायेगा?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब योजना बनाना हमारा काम नहीं है। हमारे महकमें का काम तो लोगों के नामरजिस्टर करना है और जहां से मांग आती है, वहां पर उनके नाम भेजना हैं एबजार्ब करने की योजना दूसरा महकमा बनाता है। वैसे मैं इनकी इन्फर्मेसन के लिए बता दूं कि यह सूचना मैंने उस डिपार्टमेंट से मंगवाई है। यह 1978-83 (पांच साल) की योजना है। इसमें हम जे०बी०टी० 10220 एबजार्ब करेंगे और बी०ए०, बी०एड० तथा एम०ए०,बी०एड० 3020 एबजार्ब करेंगे (व्यवधान)। इनको हमने पांच साल में एबजार्ब करना है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपाकरेंगे कि एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज में जो नाम दर्ज किये जाते हैं, उनमें हरिजनों के लिए अलग रोजर मेनटेन किया जाता है या जनरल में ही उनका नाम दर्ज किया जाता है? अगर जनरल में उनका नाम दर्ज किया जाता है तो उनका नाम कैसे छांटा जाता है?

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, नाम रजिस्टर करते वक्त हरिजनकानाम अलग से नहीं लिखा जाता है लेकिन जब सिलैव इन होता है तो वहां पूरा ध्यान रखा जाता है कि हरिजनो का कोटा पूरा किया जाये।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि एम.ए., बी.ए. बी.एड और जे.बी.टी. 10089 तथा 6328 अनएम्पलायड हैं इसके बावजूद भी इन क्लासिज की ट्रेनिंग जारी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतनी बेरेजगारी होते हुये भी इन क्लासिज की ट्रेनिंग पर कोई पाबन्दी लगाने का सरकारका विचार है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, हमार महकमे का काम नाम रजिस्टर करना है और इस बारे में पलिसी बनाना अलग विभाग का काम है। स्पीकर साहब, वैसे भी इस सप्लीमेंटरी का सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, जो एम्पलाएमेंट एक्सचेंजिज है, वे नार्मली बडे टाउन्ज में है इस कारण जो गांवों के लडके है वे या तो अपना नाम दर्ज करवाने के लिये नही आ पाते या उनको बहुत देर से पता लगता है इस चीज को देखते हुये क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जो बडे-2 गांव है वहां पर एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज खोलने पर सरकार विचार करेगी?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, श्री भाम ार सिंह कासवाल बिल्कुल ठीक हैं मैंने खुद भी महसूस किया है कि गांवों के लडकों को किसी भी पोस्ट का पता नहीं लगता है और भाहर से गांव काफी दूर होने के कारण वे लडके अपना नाम रजिस्टर नही करवा पाते है। इस बारे में एक स्कीम मेरे अन्डर कंस्ट्रिड्ग इन है जिसके अधीन गांव-गांव जाकर वहां के लडकों कानाम रजिस्टर किया जाएगा और फिर वे नाम एम्पलाएमेंट एक्सचेंज में दर्ज हो जायेगें। स्पीकर साहब, यह स्कीम मेरे नोटिस में एक महीने पहले आई थी और इस बारे में मैं सोच रहा हूं

श्री भागीराम: क्या चीफ मिनिस्टर साहब, बताने की कृपा करेगें। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: ऐसा कहना भाोभा नहीं देता कि इनको कुछ पता नही ह। ये भाब्द ऐक्संपज करदिये जायें (व्यवधान)

श्री भागी राम: जो लिस्ट सदन में रखी गई है उसमें सिरसा जिले में एम.ए., बी.एड. 186 बताये हैं और जे.बी.टी. 175 दिखाये हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले में इन कैटगरीज के सब से कम होने का क्या कारण है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: हमारे पास तो जो लोग नाम दर्ज कराने आते हैं, उनके नाम दर्ज कर लेते हैं और वही मैंने इन्फॉर्म न दे दी है। बाकी चौधरी देवी लाल से पूछी कि वहां पर पढ़े लिखे क्यों कम हैं?

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का सवाल से कोई संबंध नहीं है।

चौधरी रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे यहां इतने बेरोजगार हैं और इनके नाम एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजिज में दर्ज हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि एम्प्लायमेंट देने के बारे में योजना बनाना दूसरे विभाग का काम है, इनका काम तो राम रजिस्टर करना है क्या चीफ मिनिस्टर साहब, बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचारधीन कोई ऐसी तजवीज है कि योजना और एम्प्लायमेंट के महकमों को एक कर दिया जाए और मंत्री महोदय को इनका इंचार्ज बना दिया जाये जिससे कि ये ठीक तरह से काम कर सकें?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, योजना तो अपनी-अपनी अलग-अलग महकमों बनाते हैं। चौधरी रिजक राम

जी खुद भी मंत्री रहे है, इनको पता होगा कि यह काम किसी एक वजारत का नही होता।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नही है कि बहुत सारे पढ़े-लिखे नौजवान बेकार फिर रहे हैं इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है क्योंकि सभी को नौकरियां तो दी नहीं जा सकती। हमने गांवों में लघु उद्योग धन्धों की स्कीमें बनाई है और इन उद्योग-धन्धों को लगाने के लिए सरकार 10 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक उनको कर्जा भी देती है और भी कई तरह की सहूलियतें इस काम के लिए दी जाती है। इसके साथ-साथ एक लाख पर 15 परसेन्ट सबसिडी भी दी जाती है। अगर नौकरियों में जाने की बजाये पढ़े लिखे नौजवान इस तरफ ध्यान देंगे तो बेरोजगारी अपने आप ही समाप्त हो जायेगी। (तालियां)

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने मिनिस्टर साहब के जवाब में इंटरवीन करते हुये कहा कि सिलैव इन में रिजर्वे इन होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज द्वारा कोटे के सिहाब से हरिजनों, पिछड़ी जाति और एक्स सर्विसमैनो के नाम भी भेजे जाते है या कहीं ऐसा तो नही होता कि इनका कोटा काट कर, दूसरे कैन्डीडेटस के नाम भेजे जाते हो?

चौधरी भजन लाल: भेजे जाते हैं।

चौधरी भाग मल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे मालूम होता है कि जे.बी.टी टीचर्स जो रजिस्टर्ड है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हैं। प्रदेश में अन-एम्प्लायमेंट भी बहुत ज्यादा है, नार्मज की वजह से अब तक वे लोग सर्विस में नहीं आसके और वे ओवर एज होते जा रहे हैं क्या उनके लिए एज में कोई रिलैक्सेशन होगी ताकि उनको सर्विस मुहैया की जा सके?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्विस में भर्ती के लिये आयु सीमा 27 साल से बढ़ाकर 30 साल की कर दी गई है।

चौधरी गंगाराम: स्पीकर साहब, इन्होंने बताया है कि हरियाणा के अन्दर बी.ए. और बी.एड. 17-18 हजार के करीब अन-एम्प्लायड है। मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार, मार्क्सवादी सरकारों की तरह से इन बेरोजगारों को भत्ता देने का कोई विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीसुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को याद होगा कि जब वे चौधरी देवी लाल जी की सरकार में मंत्री थे तो इन्होंने अन-एम्प्लायमेंट के उपर अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले दस सालों के अन्दर देश भर से जनता पार्टी की

सरकार बेरोजगारी पूरी तरह से दूर कर देगी.....(गोर एव विधान)

Mr. Speaker: Ch. Surrender Singh Ji, please ask your supplementary pertaining to this question only.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकरसाहब, मैं इसी संबंध में ही क्वै चन पूछने जा रहा हूँ। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अन-एम्प्लायमेंट की रे गोर को देखते हुये वे बताएंगे कि 10 सालों में अनुपातक तौर पर जितना रोजगार नवयुवकों को मिलना चाहिये था, क्या इन्होंने अपने पिछले अढाई-तीन साल के राज में उतनी रे गोर दिलवा दी है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया कि पढे-लिखे नोजवानो के लिये सरकार ने गांवों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, ऐसी स्कीमें बनाई है जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिल सकें । जैसा कि इन्होंने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने यह घोशणा की थी कि हम 10 सालों में दे गोर से गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। यह उस वक्त के प्रधान मंत्री जी की नीति थी, पर हमें सारे दे गोर की बात नहीं करनी चाहिये, हम तो अपने हरियाणा प्रान्त की बात करते हैं। अब की जो प्रधानमंत्री महोदया है, उन्होंने तो यह कहा है कि हम 10 साल से पहले ही बेरोजगारी और गरीबी को इस दे गोर से दूर करना चाहते हैं।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या उनके नोटिस में ऐसे केसिज है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज से लडकों को जो इंटरव्यू लैटर भेजे जाते है, वह समय पर न भेज कर लेट भेजे जाते है, जिसके कारण वे लोग समय पर इंटरव्यू पर नहीं जा सकते और नोकरियों से इसी कारण से काफी लोग वंचित रह जाते हैं। क्या मिनिस्टर महोदय इस बात की व्यवस्था करेगें कि आगे से कैंडीडैटस को इंटरव्यू लैटर समय पर भिजवायें जाया करें?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकरसाहब, ऐसी कोइ कम्प्लैन्ट सरकार के नोटिस में नहीं हैं अगर माननीय सदस्या ऐसी कोई पर्टीकुलर कम्प्लेन्ट हमें बतायेंगी तो सरकार अव य ऐसे आदमियों के खिलाफ एक् टान लेगी जिनका ऐसी बातों में हाथ होगा। मैं खुद भी ऐसी कोई बात बर्दा त नहीं करूंगा। मैं इन बातों के खिलाफ हूँ और जिस किसी की भी ऐसे कामों में लापरवाही देखी जाएगी उसे बख्शा नहीं जायेगा।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, बहुत सारे एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में ऐसा है कि जहां पर पैसा ले ले कर गड़बड़ की जाती है। और लिस्टों में भी हेराफेरी की जाती है। इस तरह से कई बेचारे भारीफ लोग नोकरियों से वंचित रह जाते है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनके नोटिस में ऐसी कोई बात है क्या इसकी रोकथाम करने का सरकार विचार रखती है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां—जहां हमने चेंकिंग करवाई है हमें कोई ऐसी रिक्वायत नहीं मिली है कि इस तरह से नाम नीचे कर दिये जाते हैं या उपर कर दिये जाते हैं। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इस किसम की कार्यवाही करता है तो उसके संबंध में आनरेबल मੈबर कोई स्पैसिफिक इन्स्टान्स हमारे नोटिस में लाएं, हम उसके खिलाफ अवय सख्त एक्शन लेगें। यूं ही बगैर किसी अथैन्टिक इन्फर्मेसन के यह कह देना कि पैसे ले ले कर काम होते हैं, यह उचित नहीं है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकरसाहब, सोनीपत के अन्दर सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक में सारे ही लड़के आदमपुर के भर्ती करवा दिये गये हैं। वह कहां से आ रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ठीक बात हैं

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई जनरल एडवरटाइजमेंट अखबारों में आती है, पोस्टें निकलती हैं तो कहीं का भी कोई आदमी ऐप्लाई कर सकता है। इसमें आदमपुर का सवाल क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर आदमपुर का एक आदमी भी नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, चौधरी गंगा राम खुद चेयरमैन रहे हैं, ये खुद.....करते थे।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मुझे भी कुछ कहनेका समय दिया जाये, मेरे उपर इलजाम लगाया गया है। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, ये कहने वाले अगर साबित कर दें कि मैंने किसी से पैसा लिया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो ये इस्तीफा दे दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी आप तारीफ रखियें।

श्री भाम गोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में किस तरह से हेराफेरी होती है। उसका तरीका यह है कि अगर पांच पोस्टें होती हैं तो उनके तीन गुना चानि 15 नाम भेजे जाते हैं। जिन आदमियों को रखना होता है जब तक उनके नाम नहीं आ जाते तब तक इंटरव्यू पोस्टपोन कर दी जाती है तो क्या इस चीज को रोकने का इनतजाम किया जाएगा?

चौधरी भजन लाल: अगर कोई खस इंस्टांस इनके नोटिस में है तो वह हमारे नोटिस में लायें, हम कार्यवाही करेंगे।

Mr. Speaker: Hon'ble Member, Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Market Fee

***1655/ Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the recent judgement of the Supreme Court declaring the increase of market fee from Rs.2/- to Rs.3/- void in Haryana and also its observation regarding the spending of the amount of Market Fee; if so, the action taken or proposed to be taken in this behalf;

(b) whether any fresh instructions have been issued to the Market committees in the State in the light of the judgement referred to in part(a) above; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House; and

(c) whether it is also a fact that the Supreme Court has held that the funds of a Market Committee cannot be spent outside the area of the Committee; if so, the action taken by the Government in this behalf?

Agriculture Minister (Sardar Tara singh):

(a) Yes. Market Fee is being charged at the rate of Rs.2/- per hundred w.e.f. the date of judgement viz. 4.5.1979. In addition, in the light of the observation of the Supreme Court the Market Committees have stopped payment, out of the Market Fee collected, for the purposes declared invalid.

(b) A copy each of the instructions issued by the marketing Board to Market Committees is laid on the Table of the House (Annexure I, II)

(c) The Supreme Court has held that the funds of a Market Committee should be spent within the area of the concerned Committee. However, they have upheld 30% contribution to the Board. Even the said contribution should be spent as far as practicable for the purpose of the Market Committee which makes the contribution.

ANNEXURE-I

Telegram

Administrator

Market Committee

**IN THE LIGHT OF SUPREME COURT JUDGEMENT
CHARGE MARKET FEE AT TWO PERCENT FROM FOURTH
MAY, 1979.**

SAMBH

Not to be telegraphed

Sd/-

Secretary,

Haryana State Agricultural Marketing

Board, S.C.O. No. 1040-41, Sector-22

Chandigarh.

A copy for the confirmation of the above telegram is sent to all the Administrators, Market Committees in the State of Haryana for information and necessary action. They are requested to charge market fee at the rate 2% till further orders.

C.No.58

Sd/-

Secretary

Endst. No. RE-II-79/22875-22986 dated 7-5-1979.

A copy of the above is forwarded to:-

1. All S.E.E.O's
2. All M.E.O's
3. All the Heads of the Branches in the office of the Board for information and necessary action.

Sd/-

Secretary

ANNEXURE-II

From

The Secretary,

Haryana State Agri. Marketing Board

Chandigarh.

To

All the Executive Officers-cum-Secretaries,

Market Committees in Haryana.

Memo. No. RE-IV-79/33816-33902

Chandigarh, Dated the 23-7-1979 C.N. 81

Subject:- Copy of the judgement of the Supreme Court in the cases of enhancement of Market Fee from 2% to 3%.

Enclosed please find a copy of the judgement of the Supreme Court passed on 4-5-1979 in cases of enhancement of Market Fee from 2% to 3% for your information and necessary action.

Sd/-

Secretary

Encl. :- Copy of Judgement.

Endst. No. RE-IV-79/33903-33917
Chandigarh, dated the 23.7.79.

A copy is forwarded to all the Senior Marketing Enforcement Officers/Marketing Enforcement Officers in Haryana for information and necessary action.

Sd/-

Secretary

Prime Minister's Police Medal

***1584. Master Shiv Prashad:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the names and ranks of recipients of Prime Minister's Police Medal for saving lives during the period from April, 1973 to March, 1979, in the State; and

(b) whether other benefits like Ex-gratia payments, promotions, advance increments etc. have also been granted to each of the recipients referred to in part(a) above on uniform basis?

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल):

(ए) 1. सिपाही प्रेम चन्द नं.97/अम्बाला (अब प्रधान सिपाही) 1974

2. सिपाही राम कुमार नं0 1248/अम्बाला (अब प्रधान सिपाही) 1976

(बी) नियमानुसार और कोई लाभ देय नहीं है।

Creation of Sampla Sub-Tehsil

***1547. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to create Sampla Sub-Tehsil in District Rohtak; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

राजस्वमंत्री(चौधरी भोर सिंह):

(ए) नहीं ।

(बी) प्र न नही उठता ।

Creation of new Sub-Tehsil at Kalayat

***1532. Shri Preet Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether any recommendation was made by the District Re-organisation Committee during the year 1979 for the Creation of a new sub-tehsil at Kalayat in District Jind; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, the steps; if any, so far taken or proposed to be taken for the creation of the said sub-tehsil and; if not, thereasons therefor?

राजस्वमंत्री(चौधरी भोर सिंह):

(ए) हाँ ।

(बी) मामला सरकार के विचारधीन है ।

Barwala water supply scheme

***1634. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is in the notice of the Government that water supply scheme of Barwala Town is not working satisfactorily; if so, the steps; if any, taken or proposed to be taken to improve its working?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): यह स्कीम सन्तोशजनक ढंग से चल रही है, सिवाये इसके कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की सप्लाई कम है। इस स्कीम के अधीन जल वितरण बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचारधीन है।

Mandi At Chopta

***1521. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether the work for constructing a Mandi at Chopta in District Sirsa has been taken in hand; if not, the reason therefor?

कृषि मंत्री (सरदार तारा सिंह): जीं नहीं, चौपटा में मण्डी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Teaching of Sanskrit Language

***1482. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce teaching of Sanskrit language in the Schools from Sixth class in the State;

(b) if so, the time by which the teaching of Sanskrit language is likely to be started; and

(c) the steps if any, taken or proposed to be taken by the Government for the propagation of Sanskrit language in the state?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राज्य में संस्कृत भाशा के प्रचार के लिए सरकार द्वारा उठाये गए पगों, तथा प्रस्तावित पगों का विवरण सदन के समक्ष रखा जाता है।

विवरण

हरियाणा राज्य में संस्कृत भाशा के प्रचार के लिए निम्नलिखित पग उठाये गये—

1. प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित करना।
2. संस्कृत लेखक गोष्ठियों का आयोजन करना।

3. सर्वोत्तम साहित्यिक संस्कृत पुस्तकों / निबन्धों के लिए पुरस्कार देना।

4. हरियाणा राज्य की संस्कृत संस्थाओं को सहायता अनुदान देना।

5. संस्कृत भाषण तथा भलोकोच्चाण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

6. संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान देना।

7. संस्कृत दिवस का आयोजन करना।

8. अनुसंधान एवं लेखन कार्य के लिए सहायता अनुदान देना।

उक्त स्कीमों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए निम्नलिखित दो नई स्कीमें बनाई गई हैं—

1. साहित्यिक, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की संस्कृत पांडुलिपियों का संग्रह और संरक्षण करना।

2. संस्कृत भलोकों के भुद्ध उच्चारण को टेप रिकार्ड करना।

Rest House at Otoo

***1526. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to construct a rest house by the Tourism Department at Otoo in District Sirsa; if so, the time by which it is likely to be started?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): हां, परन्तु इसको सम्पन्न करने की बात धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Irrigated and unirrigated land

347. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the total acreage of irrigated and unirrigated land in the State at present, separately; and

(b) the total acreage of land proposed to be brought under irrigation during the period from 1-2-1980 to 31-3-1980 and 1-4-1980 to 31-3-1981, separately?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(ए) राज्य में सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र के आंकड़े निम्नलिखित हैं—

हैक्टरों में

1.	सिंचित निबल क्षेत्र	47.37 एकड़	लाख	19.17 लाख
2.	असिंचित क्षेत्र	42.81 एकड़	लाख	17.31 लाख
(बी) अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई करने का प्रस्ताव निम्नलिखित है:-				
1.	1-2-80 से 31-3-80	0.74 एकड़	लाख	0.30 लाख
2.	1-4-80 से 31-3-81	2.22 एकड़	लाख	0.90 लाख

L.I.G.H and M.I.G.H. Loan

348. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) the district-wise names of persons who have been granted LIG and MIG Housing loans during the years 1977-78 to 1979-80(to-date) together with the amount of LIGH and MIGH loans granted in each case, separately; and

(b) the district-wise total number of applications received for loans referred to in part (a) above category-wise and the number of applications disposed of during the period 1977-78 to 1979-80 (to-date) separately?

विकास मंत्री (राव राम नारायण): वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा, उसके मुकाबले लाभ कम होगा।

Aurvedic Dispensaries

350. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise number and names of Ayurvedic Dispensaries functioning in the State at present together with their number as on 31-3-1977 and 28-2-1980, separately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open dispensaries referred to in part (a) during the years 1980-81 and 1981-82 and, if so, the district-wide number of the dispensaries likely to be opened?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) सूचना विवरणी I से III पर संलग्न है।

(ख) जी हां, ब्यौरे इस प्रकार है:—

	1980—81	1981—82
कुरुक्षेत्र	1	1
महेन्द्रगढ़		

अम्बाला	3	3
रोहतक	3	3
हिसार	3	4
गुड़गांव	2	2
फरीदाबाद	1	1
जीन्द	2	2
सोनीपत	3	3
भिवानी		
सिरसा		
करनाल	2	2
कुल	20	20

विवरणी I

	Name of the District together with the name of Ayurvedic	No. of Ayurvedic Dispensaries functioning in the State at present
--	---	--

	Dispensaries.	
Sr. No.	1	2
	KARNAL	32
1.	Adyana	
2.	Dehra	
3.	Gagsina	
4.	Shekhupura Manchuri	
5.	Patti Kalyana	
6.	Sawant	
7.	Staundi	
8.	Garhi Birbal	
9.	Kurar	
10.	Seenk	
11.	Dabkoki	
12.	Bhadson	
13.	Kurlan	
14.	Kalsora	
15.	Kirmach	

16	Babail	
17.	Barsat	
18.	Darar	
19.	Israna	
20.	Gheer	
21.	Chigama	
22.	Randoli	
23.	Buana Lakhu	
24.	Hathwala	
25.	Joshi	
26.	Araipura	
27.	Barana	
28.	Goinder	
29.	Barthal	
30.	Kheri Sarfali	
31.	Kond	
32	Saga	
HISAR		36
1.	Lehrian	

2.	Rajli	
3.	Dharsul	
4.	Rawalwas Khurd	
5.	Kuleri	
6.	Ghirai	
7.	Kapro	
8.	Sultanpur	
9.	Kalirawan	
10.	Nehla	
11.	Gorakhpur	
12.	Sidhani	
13.	Ladwa	
14.	Burak	
15.	Nandori	
16.	Kharar Alipur	
17.	Kharak Punia	
18.	Jakhod Khera	
19.	Gilan Khera	
20.	Kinala	

21.	Ladwi	
22.	Kurari	
23.	Muklan	
24.	Sadalpur	
25.	Shahpur	
26.	Mangali Singhran	
27.	Tokas Patan	
28.	Gabar	
29.	Kalwas	
30.	Ghangar	
31.	Rakhi Shahpur	
32.	Gamra	
33.	Bhiwani Rohilla	
34.	Chaudhari Wali	
35.	Khajuri	
36.	Kharia	
SIRSA		16
1.	Gangwa	
2.	Kagdana	

3.	Kaluana	
4	Bahudin	
5.	Sherpura	
6.	Deeg	
7.	Jamal	
8.	Alika	
9.	Kutabad	
10.	Dharampura	
11.	Jodhka	
12.	Sahuwala-II	
13.	Bharokha	
14.	Kanwar Pura	
15.	Mitin Surera	
16.	Kewal	
JIND		22
1.	Uchana Kalan	
2.	Ram Rai	
3.	Lajwana Khurd	
4.	Dadwara	

5.	Shahpur	
6.	Dumerkha Kalan	
7.	Haat	
8.	DanodaKalan	
9.	Durjanpur	
10.	Karela	
11.	Bibipur	
12.	Dhamtan Sahib	
13.	Bhambewa	
14.	Alewa	
15.	Naguran	
16.	Malvi	
17.	Barsola	
18.	Patiala Chowk Jind	
19.	Poli	
20.	Simla	
21.	Morkhi	
22.	Budha Khera	
KURUKSHETRA		28

1.	Sherdha	
2.	Pai	
3.	Umri	
4.	Jotisar	
5.	Jathlana	
6.	Murtzapur	
7.	Seonsar	
8.	Deeg	
9.	Jadaula	
10.	Barsana	
11.	Songri Gulvana	
12.	Karora	
13.	Keorak	
14.	Kherka	
15.	Bhana	
16.	Gumthala Rao	
17.	Gumthla Garh	
18.	Peedal	
19.	Lukhi	

20.	Dharaula	
21.	Pharal	
22.	Saarsa	
23.	Kharkali	
24.	Kalalmajra	
25.	Fatehpur Pundri	
26.	Kangthali	
27.	Ratta Khera	
28.	Mathana	
MOHINDERGARH		29
1.	Dhakera	
2.	Nanqak Sirohi	
3.	Akoli	
4.	Raliawas	
5.	Niwajpur	
6.	Nimbi	
7.	Masnuta	
8.	Bainipur	
9.	Bassai	

10.	Kheri Kanit	
11.	Nandrampurwas	
12.	Saharanwas	
13.	Kheri Talwana	
14.	Ghatesar	
15.	Khatauli Jat	
16.	Pali	
17.	Pajri	
18.	Silarpur	
19.	Jakhani	
20.	Munid	
21.	Bikaner	
22.	Bhagot	
23.	Musapur	
24.	Hamidpur	
25.	Nizampur	
26.	Rajawas	
27.	Khori	
28.	Sangwari	

29.	Pranpura	
AMBALA		30
1.	Bara Gara	
2.	Naneora	
3.	Alipur Jahangir	
4.	Ghuran Pipli	
5.	Harnaul	
6.	Hongoli	
7.	Khajuri	
8.	Laharpur	
9.	Khadri	
10.	Devdhar	
11.	Korwakhurd	
12.	Lakhnaura	
13.	Leoli	
14.	Kajiyana	
15.	Natwal	
16.	Mandhna	
17.	Ramgarh	

18.	Thandog	
19.	Barwala	
20.	Punjupura	
21.	Machharuli	
22.	Babyal	
23.	Rehna	
24.	Ferozepur	
25.	R.H. Top-Khana Bazar Ambala	
26.	salimpur Kohi	
27.	Talheri Kujran	
28.	Rasidpur	
29.	Binjhlpur	
30.	Khera	
ROHTAK		30
1.	Ladhot Bhanpur	
2.	Samargopalpur	
3.	Pakisma	
4.	Bahaukabarpur	

5.	Dubaldhan	
6.	Mandhothi	
7.	Ladrawan	
8.	Dulhera	
9.	Khungai	
10.	Munimpur	
11.	Badsa	
12.	Ukhalchana	
13.	Khorra	
14.	Salawas	
15.	Bahu Jholri	
16.	Hassangarh	
17.	Ismaila	
18.	Kheri Jat	
19.	Nidana	
20.	Gataudm	
21.	Kharhar	
22.	Mattan	
23.	Luhari	

24.	Kehroli-prahladpur	
25.	Bopenia	
26.	Lakhan Mazra	
27.	Hassanpur	
28.	Assoda	
29.	Rohad	
30.	Lula Ahir	
BHIWANI		33
1.	Tigrana	
2.	Jhumpa	
3.	Leghan	
4.	Mandoli Kalan	
5.	Dabdhani	
6.	Barawas	
7.	Bamla	
8.	Mundhal	
9.	Tiwala	
10.	DokaHaria	
11.	Dudwa	

12.	Atelapaharwala	
13.	Chirya	
14.	Nimriwali	
15.	Jitpura	
16.	Dhareru	
17.	Berla	
18.	Kadma	
19.	Khudana	
20.	Bhandwa	
21.	Pur	
22.	Saharwa	
23.	Hetampura	
24.	Golagarh	
25.	Pokharwas	
26.	Morewala	
27.	Chhapar Rangran	
28.	Lad	
29.	Jhinjar	
30.	Rudrol	

31.	Roopgarh	
32.	Durjanpur	
33.	Kungar	
SONIPAT		11
1.	Saragthal	
2.	Baroda	
3.	Bahinswal Kalan	
4.	Dhanana	
5.	Rajlugarhi	
6.	Kahni	
7.	Harsana Kalan	
8.	Piplikhera	
9.	Khijar-Pur-Ahir	
10.	Bhainswan Khurd	
11.	Mandora	
FARIDABAD		14
1.	Gahlab	
2.	Bahin	
3.	Bigowali	

4.	Manjhawali	
5.	Dighot	
6.	Shajahanpur	
7.	Nangal Brahaman	
8.	Bhashola	
9.	Sondh	
10.	Sahrauli	
11.	Janauli	
12.	Sekhpur Khadar	
13.	Gharrot	
14.	Badoli	
GURGAON		28
1.	Bandwari	
2.	Karola	
3.	Bajohera	
4.	Sikohpur	
5.	Khandewala	
6.	Jehtana	
7.	Jamalpur	

8.	Nanukalan	
9.	Jamalgarh	
10.	Sakras	
11.	Umra	
12.	Bhadas	
13.	Bichhore	
14.	Dungeja	
15.	Gokalpur	
16.	Agon	
17.	Pathkheri	
18.	Akera	
19.	Jorasi	
20.	Kaoraka	
21.	Dhulawat	
22.	Malai	
23.	Jhanda	
24.	Kondalo	
25.	Vazirpur	
26.	Unglikhera	

27.	Gujjarnanaglan	
28.	Tigaon.	
Grand Total		309

विवरणी II

	Name of the District together with the name of Ayurvedic Dispensaries.	No. of Ayurvedic Dispensaries as on 31-3-1977
Sr. No.	1	2
	KARNAL	19
1.	Adyana	
2.	Dehra	
3.	Gagsina	
4.	Shekhupura Manchuri	
5.	Patti Kalyana	
6.	Sawant	
7.	Staundi	

8.	Garhi Birbal	
9.	Kurar	
10.	Seenk	
11.	Dabkoki	
12.	Bhadson	
13.	Kurlan	
14.	Kalsora	
15.	Kirmach	
16.	Babail	
17.	Barsat	
18.	Darar	
19.	Israna	
HISAR		21
1.	Lehrian	
2.	Rajli	
3.	Dharsul	
4.	Rawalwas Khurd	
5.	Kuleri	
6.	Ghirai	

7.	Kapro	
8.	Sultanpur	
9.	Kalirawan	
10.	Nehla	
11.	Gorakhpur	
12.	Sidhani	
13.	Ladwa	
14.	Burak	
15.	Nandori	
16.	Kharar Alipur	
17.	Kharak Punia	
18.	Jakhod Khera	
19.	Gilan Khera	
20.	Kinala	
21.	Ladwi	
SIRSA		16
1.	Gangwa	
2.	Kagdana	
3.	Kaluana	

4	Bahudin	
5.	Sherpura	
6.	Deeg	
7.	Jamal	
8.	Alika	
9.	Kutabad	
10.	Dharampura	
11.	Jodhka	
12.	Sahuwala-II	
JIND		16
1.	Uchana Kalan	
2.	Ram Rai	
3.	Lajwana Khurd	
4.	Dadwara	
5.	Shahpur	
6.	Dumerkha Kalan	
7.	Haat	
8.	DanodaKalan	
9.	Durjanpur	

10.	Karela	
11.	Bibipur	
12.	Dhamtan Sahib	
13.	Bhambewa	
14.	Alewa	
15.	Naguran	
16.	Malvi	
KURUKSHETRA		22
1.	Sherdha	
2.	Pai	
3.	Umri	
4.	Jotisar	
5.	Jathlana	
6.	Murtzapur	
7.	Seonsar	
8.	Deeg	
9.	Jadaula	
10.	Barsana	
11.	Songri Gulvana	

12.	Karora	
13.	Keorak	
14.	Kherka	
15.	Bhana	
16.	Gumthala Rao	
17.	Gumthla Garh	
18.	Peedal	
19.	Lukhi	
20.	Dharaula	
21.	Pharal	
22.	Saarsa	
MOHINDERGARH		23
1.	Dhakera	
2.	Nanqak Sirohi	
3.	Akoli	
4.	Raliawas	
5.	Niwajpur	
6.	Nimbi	
7.	Masnuta	

8.	Bainipur	
9.	Bassai	
10.	Kheri Kanit	
11.	Nandrampurwas	
12.	Saharanwas	
13.	Kheri Talwana	
14.	Ghatesar	
15.	Khatauli Jat	
16.	Pali	
17.	Pajri	
18.	Silarpur	
19.	Jakhani	
20.	Munid	
21.	Bikaner	
22.	Bhagot	
23.	Musapur	
AMBALA		19
1.	Bara Gara	
2.	Naneora	

3.	Alipur Jahangir	
4.	Ghuran Pipli	
5.	Harnaul	
6.	Hongoli	
7.	Khajuri	
8.	Laharpur	
9.	Khadri	
10.	Devdhar	
11.	Korwakhurd	
12.	Lakhnaura	
13.	Leoli	
14.	Kajiyana	
15.	Natwal	
16.	Mandhna	
17.	Ramgarh	
18.	Thandog	
19.	Barwala	
ROHTAK		19
1.	Ladhot Bhanpur	

2.	Samargopalpur	
3.	Pakisma	
4.	Bahaukabarpur	
5.	Dubaldhan	
6.	Mandhothi	
7.	Ladrawan	
8.	Dulhera	
9.	Khungai	
10.	Munimpur	
11.	Badsa	
12.	Ukhalchana	
13.	Khorra	
14.	Salawas	
15.	Bahu Jholri	
16.	Hassangarh	
17.	Ismaila	
18.	Kheri Jat	
19.	Nidana	
BHIWANI		25

1.	Tigrana	
2.	Jhumpa	
3.	Leghan	
4.	Mandoli Kalan	
5.	Dabdhani	
6.	Barawas	
7.	Bamla	
8.	Mundhal	
9.	Tiwala	
10.	DokaHaria	
11.	Dudwa	
12.	Atelapaharwala	
13.	Chirya	
14.	Nimriwali	
15.	Jitpura	
16.	Dhareru	
17.	Berla	
18.	Kadma	
19.	Khudana	

20.	Bhandwa	
21.	Pur	
22.	Saharwa	
23.	Hetampura	
24.	Golagarh	
25.	Pokharwas	
SONIPAT		5
1.	Saragthal	
2.	Baroda	
3.	Bahinswal Kalan	
4.	Dhanana	
5.	Mandora	
GURGAON		36
1.	Gahlab	
2.	Bahin	
3.	Bigowali	
4.	Manjhawali	
5.	Dighot	
6.	Shajahanpur	

7.	Nangal Brahaman	
8.	Bhashola	
9.	Sondh	
10.	Sahrauli	
11.	Janauli	
12.	Sekhpur Khadar	
13.	Bandwari	
14.	Karola	
15.	Bajohera	
16.	Sikohpur	
17.	Khandewala	
18.	Jehtana	
19.	Jamalpur	
20.	Nanukalan	
21.	Jamalgarh	
22.	Sakras	
23.	Umra	
24.	Bhadas	
25.	Bichhore	

26.	Dungeja	
27.	Gokalpur	
28.	Agon	
29.	Pathkheri	
30.	Akera	
31.	Jorasi	
32.	Kaoraka	
33.	Dhulawat	
34.	Malai	
35.	Jhanda	
36.	Kondalo	
Grand Total		217

विवरणी III

Total number of Ayurvedic dispensaries functioning in the State as on 28-2-80:

Same as given in Statement-I

Primary Health Centres

351. Chaudhri Ram Lal Wadha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise number and names of Primary Health Centres in the State at present together with the strength of staff provided in each Primary Health Centre, separately; and

(b) whether there in any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centres during the years 1980-81 and 1981-82; if so, the number of Primary Health Centres likely to be opened in each District?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) सूचना अनुबन्ध में सलग्न है।

(ख) निम्नलिखित खण्डों, जिनमें इससमय कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है:—

1. महेन्द्रगढ़—II खण्ड, जिला महेन्द्रगढ़।
2. रिवाड़ी खण्ड, जिला महेन्द्रगढ़।
3. कथूरा खण्ड, जिला सोनीपत।
4. बवानीखेड़ा खण्ड, जिला भिवानी।
5. जीन्द खण्ड, जिला जीन्द।

इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण का कार्य वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में किये जाने की सम्भावना

है। इन वर्षों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की सम्भावना नहीं है।

अनुबन्ध

क्रम संख्या	जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम	कुल अमला संख्या
1.	2	3	4	5
1.	अम्बाला	8	1. बिलासपुर	50
			2. चोडमस्तपुर	67
			3. खीजराबाद	55
			4. मुलाना	77
			5. मुस्ताबाद	66
			6. पिंजौर	55
			7. रायपुर रानी	77
			8. साढोरा	62
2	भिवानी	7	1. बोण्ड कलां	58

			2. गोपी	58
			3. झोजू कलां	52
			4. कैरू	51
			5. मीरन	58
			6. नवीपुर	37
			7. सतनाली	36
3.	फरीदाबाद	6	1. औरंगाबाद	56
			2. डुडोला	48
			3. हसनपुर	49
			4. कुराली	54
			5. खड़ी कलां	54
			6. मण्डकोला	45
4	गुड़गांव	7	1. भोडाकलां	34
			2. फरूखनगर	53
			3. घंगोला	39

			4. नगीना	48
			5. नूहं	48
			6. पुन्हाना	41
			7. पटौदी	64
5.	सिरसा	4	1. बडागुड़ा	42
			2. माथोसिंगाना	54
			3. ओढा	61
			4. रानियां	49
6.	हिसार	11	1. भट्टुकलां	47
			2. भूना	67
			3. बरवाला	52
			4. जाखल	45
			5. खांडा-खेडी	55
			6. मंगाली	45
			7. मिर्चपूर	21

			8. रतिया	42
			9. सीसवाल	48
			10. सोरखी	40
			11. सिसाएबोला	49
7.	जीन्द	7	1. गोगड़ियां	46
			2. जुलाना	55
			3. कालवा	54
			4. कलायत	64
			5. राजौन्द	55
			6. भामलो कलां	44
			7. उझाना	42
8.	करनाल	9	1. असंध	45
			2. अहर	47
			3. बापोली	53
			4. बल्लाह	36

			5. धरोंडा	51
			6. इन्दरी	57
			7. नींसिग	41
			8. नीलोखेडी	85
			9. संभालखा	67
9.	कुरुक्षेत्र	6	1. गुहला	63
			2. झांसा	53
			3. कौल	58
			4. पेहोवा	62
			5. रदौर	68
			6. सीवन	62
10.	महेन्द्रगढ़	8	1. अटेली	59
			2. बावल	65
			3. दोचाना	46
			4. गुरावड़ा	48

			5. कनीना	56
			6. खौल	57
			7. नगल चौधरी	50
			8. सलॉग	42
11.	सोनीपत	6	1. गोहाना	51
			2. गन्नौर	58
			3. हलालपुर	50
			4. जुआं	55
			5. खरखौदा	62
			6. मुडलाना	59
12.	रोहतक	10	1. बादली	50
			2. छारा	58
			3. चिड़ी	31
			4. ढाकला	36
			5. डीघल	55

			6. किलोई	50
			7. काहनौर	61
			8. मदीना	56
			9. नाहड़	43
			10. सांपला	53

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग

उपाध्यक्ष द्वारा 14-3-1980 को दी गई रूलिंग पर पुनः विचार

10.00 बजे

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल आप हाउस में मौजूद नहीं थे। डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी थी, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ:-

श्री अध्यक्ष: जो चेयर की तरफ से रूलिंग आ चुकी है, उस पर कोई बहस नहीं होगी।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम तो आपसे रि-कंसिड्रे इन के लिए रिकवैस्ट करना चाहते हैं.....(गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो चेयर की तरफ से रूलिंग आ चुकी है उस पर फरदर डिस्क इन नहीं होगी।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब मेरी प्रार्थना यह है कि कई रैलोल्यू इंज के संबंध में हमारे पास आपके लैटर आ रहे हैं कि आप कंसिडर करेगे। कोई आप अलाउ कर रहे हैं और कोई आप डिस—अलाउ कर रहे हैं.....(तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: At page 101 of the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul & Shakhdar, it is stated:-

“The Deputy Speaker has the same powers as the Speaker when presiding over a sitting of the House and all references to the Speaker in the Rules are deemed to be references to the Deputy Speaker when he so presides. It has been consistently held that no appeal lies to the Speaker against a ruling given by the Deputy Speaker or any other person presiding over a sitting of the House in the absence of the Speaker.....”

The ruling given by Deputy Speaker is final and there will be no discussion on the ruling given by the Chair.

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं भी रूलिंग ही कोट करना चाहता था आपने कहा है.....(तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: There can be no discussion on the ruling given by the Chair. I would request the Hon'ble member to please sit down.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हम रूलिंग को चैलेंज नहीं करना चाहते। हम तो बड़े अदब के साथ रिक्वेस्ट

करना चाहते हैं कि इसको रि-कंसिडर किया जाये। क्योंकि उसके अन्दर.....

Mr. Speaker: There can be no reconsideration of the ruling given by Chair.

चौधरी राम लाल वधवा: उनहोने जो दो-तीन प्वायंटस बताये थे.....

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग को चैलेंज किया.....

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने चैलेज नहीं किया हम तो रि-कंसिडरेशन के लिये कह रहे हैं। (गोर एवं वयवधान)

Shri Surrender Singh: Speaker Sahib, when they are not Challenging the ruling of the Chair at all, why are you then making observations without rhyme or reason? Your observations should have come if somebody was challenging the ruling.

Dr. Magal Sain: Mr. Speaker, sir, we have not challenged the ruling given by the Chair. I think he is challenging it.

Shri Surrender Singh: What I am submitting is that the hon'ble Speaker should have made the observations if the ruling given by the Chair Was challenged. As they have

said that they were not challenging the ruling given by the Chair, I think there is no need to give any reply.

Mr. Speaker: A definite proposal was made that the ruling of the Deputy Speaker should be reconsidered and I have over-ruled it.

Shri Surrender Singh: When they say that they do not challenge the ruling given by the Chair, then why should there be any further discussion on it? (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: Speaker shahib, the remarks against the Opposition in the ruling were not happily worded. (Interruption) स्पीकर साहब, हम तो चेयर का बडा अदब करते है। मुझे आ ता है कि आप मेरे `दोस्तों की बातों से प्रोवोक होने वाले नहीं है। आपके कार्यालय ने रूल कोट करते हुये मझे पत्र में कहा है “on reconsidering the matter, the hon’ble Speaker has disallowed the resolution”. (Interruptions) स्पीकर साहब, हमारी बात भी कंसिडर कर लीजिये।

Mr. Speaker: I have already told you that the ruling by the Deputy Speaker is the ruling of the Chair and there is no question of raising any point or discussion on that ruling. Please take you seat.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मै अब विभिन्न कार्यो संबंधी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किया गया टाइम टेबल रिपोर्ट करता हूं:-

समिति की बैठक भुक्रवार 14 मार्च, 1980 को 12:30 बजे मध्याह्न प चात् महोदय के चैम्बर में हुई।

कुछ चर्चा के प चात समिति ने सिफारि की कि 17, 18, 19 20 तथा 21 मार्च 1980 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाये:-

सोमवार, 17 मार्च, 1980 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)	1.	प्र नोतरकाल।
	2.	बजट पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर।
	3.	वेतन आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी तारांकित प्र न सं0 1417 के उत्तर से उत्पन्न हुये प्रस्ताव पर आधे घंटे की चर्चा (टिप्पणी: ऐसी चर्चा रोकने के समय के बाद या

		उस दिन के कार्य की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, होगी। सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न ही मतदान होगा।)
मंगलवार, 18 मार्च, 1980 (9.00 बजे प्रातः)	1	प्र नोत्तर काल।
	2.	बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (मांग सं० 1 से 13)।
बुधवार, 19 मार्च, 1980 (प्रातः 9.00 बजे)	1	प्र नोतर काल।
	2.	वीरवार, 20 मार्च 1980 को सरकारी कार्य करने के लिये गैर-सरकारी कार्य को निलम्बित करने के लिये नियम 30 के अधीन प्रस्ताव।
	3.	बजट पर अनुदानों की मांगों पर

		चर्चा तथा मतदान (मांग सं० 14 से 25)
वीरवार, 20 मार्च, 1980 (9.00 बजे प्रातः से 1.30 बजे मध्याह्न पचास तक (पहली बैठक)	1.	प्र नोतरकाल।
	2.	सभा की समितियों की रिपोर्ट पेश करना।
	3.	वर्ष 1980-81 के बजट पर विनियोग विधेयक।
(3.00 बजे मध्याह्न से 6.30 बजे सायं तक (दूसरी बैठक)	1.	विधान कार्य
	1.	हरियाणा विधान सभा (सदस्य-भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 1980
	2.	हरियाणा विधान सभा (सदस्य-भत्ता तथा पेंशन)द्वितीय

		सं गोधन विधेयक, 1980
	3.	हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष पें ान तथा चिकित्सा सुविधा (सं गोधन) विधेयक, 1980
	4.	हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (सं गोधन) विधेयक, 1980
	5.	पंजाब गौ-वध निशेध (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1980(अध्यादे ा के निरनुमोदन करने के संकल्प सहित।
	6.	पंजाब न्यायालय (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1980
	7.	हरियाणा चुंगी तथा अधिभार विधिमान्करण विधेयक, 1980
	8.	पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1980
2.		नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा
	1.	कि वर्ष 1978-79 (1-4-78 से 31-3-79 तक) के लिये हरियाणा

		लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो 3 मार्च 1980 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर चर्चा की जाये।
	2.	कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के 1979-80 के वार्षिक वित्त विवरण (बजट अनुमान) जो 3 मार्च 1980 को सदन की मेज पर रखे गये थे, पर चर्चा की जाये।
	3.	कि वर्ष 1977-78 के लिए हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार की वार्षिक आडिट रिपोर्ट, जो 3 मार्च 1980 को सदन की मेज पर रखे गये थे, पर चर्चा की जाये।
	4.	कि मैडिकल कालिज, हस्पताल तथा अन्य संलग्न संस्थाओं और महर्षि दयानन्द वि विद्यालय, रोहतक में हड़ताल तथा बेचैनी के संबंध में न्यायाधी 1, गुरनाम सिंह जांच आयोग द्वारा दी गई

		रिपोर्ट, जो 3 मार्च 1980 को सदन की मेज पर रखे गये थे, पर चर्चा की जाये। (इन रिपोर्ट्स पर आधा घंटा डिस्कशन होगी)
भुक्रवार 21 मार्च, 1980 (9.00 बजे प्रातः)	1.	प्रानोतरकाल।
	2.	निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
	3.	निश्चितकाल के लिये स्थगित रहने संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
	4.	सभा की समितियों की रिपोर्ट पेश करना।
5.	विधान कार्य	
	1.	हरियाणा नगरपालिका (संगोषण)विधेयक, 1980। (अध्योदय के निरनुमोदन करने के संकल्प सहित)

	2.	पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सं गेधन)विधेयक, 1980 ।
	3.	पंजाब कृशि उपज मंडी (हरियाणा सं गेधन)विधेयक, 1980।(अध्योद ा के निरनुमोदन करने के संकल्प सहित)
	4.	पंजाब सहकारी भूमि विकास बैंक(हरियाणा सं गेधन)विधेयक, 1980 ।
	5.	अन्य विधान कार्य यदि कोई हो

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि णें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि णें स्वीकार करता है ।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, यह जो आपने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें एक तरमीम

होनी चाहिए। जब पिछली बार बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें एक तरमीम होनी चाहिए। जब पिछली बार बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें फैसला हुआ कि भानिवार को सीटिंग होगी तो उस वक्त मैंने तो अर्ज की थी कि इसके बदले अगले सोमवार की छुट्टी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह तो इसलिए फैसला किया गया था क्योंकि आज राज्य सभा की सीट के लिए इलैक्शन होना है और सब मैम्बर साहेबान को प्रेजैन्ट होना था। इसके अलावा इससे मैम्बर साहेबान को बजट पर बोलने का भी और मौका मिलेगा।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, आज की जो सीटिंग हैं इसकी बजाय यदि हमें सोमवार की छुट्टी हो जाती तो हम घर चले जाते और बच्चों को सम्भाल आते। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख को हाउस की दो सीटिंग रखी है। एक सीटिंग तो सुबह नौ बजे से डेढ़ बजे तक चलेगी और दूसरी सीटिंग तीन बजे फिर दोबारा भुरु हो जाएगी। इसके बारे मेरी गुजारि है कि उस दिन के लिए लन्च के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, जिस दिन दो सीटिंगज होंगी, उस दिन लन्च मेरी तरफ से होगा।

चौधरी रिजक राम: स्पीकार साहब, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस दिन चार रिपोर्टों पर डिस्कशन

रखी है, उसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में मेरी गुजारि है कि उस पर आधे घंटे की बजाय एक घण्टे का टाईम दे दिया जाए क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर बहुत से मैम्बर बोलना चाहेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट के लिए कम से कम आधे घंटे का टाईम और बढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए मैं हाउस की सैंस लेना चाहता हूं। अगर हाउस चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): ठीक है जी, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्कान के लिए आप आधे घण्टे का टाईम बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्कान के लिए आधे घण्टे का टाईम बढ़ा दिया जाता है।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, 21 मार्च, 1980 को जो एजेण्डा है उसमें लास्ट आइटम यह दी हुई है कि 'Other legislative business, if any'. यह तो ठीक है कि अगर बहुत इम्पोर्टेंट या अरजेंट मैटर का बिल जिसके ऊपर लम्बी डिस्कान होनी हो, वह उसी दिन इंट्रोड्यूस न किया जाए क्योंकि ऐसा करने से उस पर बोलने के लिए मैम्बर साहेबान को टाईम नहीं मिलता है।

Mr. Speaker: I think, you can leave it to the discretion of the Speaker. I will only admit that Bill which I will consider to be important.

Chaudhri Birinder Singh: But it should not be such as it attracts much of discussion.

Mr. Speaker: I think, that you will have to leave to my discretion. If a spate of them comes, I will not accept. I will accept only one or two Bills which I consider important.

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, दूसरीबात में यह कहना चाहता हूँ कि जो सोमवार की छुट्टी के लिए बात कही गई है, यह बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन दो सीटिंग्स होनी हैं, इन दो सीटिंग्स की बजाय यदि एक सीटिंग 22 मार्च को हो जाये तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैम्बर साहेबान को बोलने का ज्यादा टाइम मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष 1980—81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: The House will now resume general discussion on the Budget for the year 1980-81.

Dr. Brij Mohan Gupta was on his legs when the House adjourned yesterday. He may please continue his speech and wind it up within five minutes.

डा० बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी): स्पीकर साहब, कल मैं एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड पर बोल रहा था। मार्किटिंग बोर्ड ने इस वर्ष 22 नई मंडियां बनाने का फैसला किया है और मुझे यह भी पता है कि इन 22 मंडियों में जगाधरी का नाम भी है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से सिफारिश करना चाहता हूँ कि जगाधरी में नई मंडी की बहुत सख्त जरूरत थी क्योंकि जो पुरानी मंडी है वह बहुत छोटी है और भाहर के बीच में आ गई है और उसके चारों तरफ आबादी भी फैल गई है इसलिए वहां पर जल्दी से जल्दी नई मंडी बनाने की कृपा करें। स्पीकर साहब, इस मार्किटिंग बोर्ड के बारे में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले मार्किटिंग बोर्ड ने तकरीबन 5 साल हुए जगाधरी म्यूनिसिपल कमिटी के एरिया में एक सड़क बनाने की तजवीज की थी और वह सड़क आधी बना दी और आधी कच्ची पड़ी है जो आधी बनी हुई है उस पर भी पत्थर टूटे हुए पड़े हैं और कुद भी काम नहीं हुआ है। लोगों को इस सड़क से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने पिछली बार यहां हाउस में मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन से बात भी की थी और उन्होंने मुझे आवासन भी दिलाया था कि उस सड़क का केस विजीलेंस के पास क्लियरेंस

के लिए भेजा हुआ है। ज्यों ही उसकी क्लीयरेंस आ जाएगी उस सड़क को मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन स्पीकर साहब, अभी तक उस सड़क की क्लीयरेंस विजीलेंस से नहीं आई है। मेरी सरकार से यह दरचवास्त है कि उस मामले का जल्दी से जल्दी फैसला करवाया जाये क्योंकि उस सड़क से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं जगाधरी की इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इंडस्ट्रीज के लिहाज से जगाधरी हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान भर में माना जाता है। स्पीकर साहब, जगाधरी में एक बर्तनों की इंडस्ट्री बहुत मशहूर है और उस इंडस्ट्री में जो बर्तन बनते हैं वे सिर्फ सारे भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी भेजे जाते हैं। इस इंडस्ट्री के अन्दर तकरीबन 15 हजार लेबर काम करती हैं लेकिन आजकल उस इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है क्योंकि उस इंडस्ट्री में 15 हजार लेबरर्स के काम करते हुए भी बिजली हफ्ते में दो दिन आती है और वह भी पूरी नहीं आती है। यदि आती भी है तो पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है बिजली वालों की तरफ से इंडस्ट्री वालों को डिड्यूल कुछ पहुंचता है और जब दिन में बिजली चलती है तो डिड्यूल कुछ और बन जाता है। लेबर बेचारी बैठी रहती है और दिन भर देखती रहती है। सारा दिन ऐसे ही गुजार कर अपने घर को वापिस चली जाती है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जगाधरी की इंडस्ट्री जिसने हरियाणा का नाम हरियाणा में ही नहीं भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि बाहर भी बुलंद किया है, इस इंडस्ट्री

के लिए बिजली का खास तौर पर ध्यान रखे ताकि जो 15 हजार लेबर वहां पर काम करती है उसका भी भला हो सके। सपीकर साहब, इसके बाद में रोड्ज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कन्हैया लाल पोसवाल पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, हाउस में यह आ वासन भी दिलाया गया है कि 1980 के आखिर तक गांव-गांव को लिंक रोड से जोड़ दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, मेरी कांस्टीच्युएंसी आपकी कांस्टीच्युएंसी के साथ लगती है। मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं कि हमारी कांस्टीच्युएंसी में सड़कें पूरी हो जाएंगी। जो सड़क 10-11 साल से अभी तक नहीं बनी वह कैसे एक ही साल में बन जाएगी? कुछ ऐसे केसिज भी है जो कि कोर्ट में चले गए है। क्या वे सड़कें 1980 के अन्त तक बन सकेंगी। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मैं यह कहना चाहता हूं कि खास तौर पर अम्बाला जिले में सड़कों के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। अम्बाला जिले में विशेषकर जगाधरी कांस्टीच्युएंसी, छछरौली और नारायणगढ़ का इलाका सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है और हरियाणा बनने के बाद ही नहीं बल्कि ज्वायंट पंजाब से ही निग्लैक्ट होता आया है। आपको मालूम है कि अम्बाला जिला में रैवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है इसलिए इसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और डिवैल्पमेंट के कामों में खास तौर पर प्रायोरिटी देनी चाहिए।

जहां तक ट्रांस्पोर्ट का संबंध है, सरकार ने जगाधरी में बस-स्टैंड बनाने के लिए लिखा है लेकिन अभी तक बस-स्टैंड नहीं बनाया गया। मैंने पहले भी कई बार मंत्री महोदय से बस-स्टैंड बनाने के लिए कहा था लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस-स्टैंड इसलिए जरूरी है क्योंकि जगाधरी इंडस्ट्रियल टाउन होने के नाते बाहर से बहुत बड़ी तादाद में लेबर-क्लास काम करने के लिए बसों में आती है। बस-स्टैंड की हालत खराब होने के कारण उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार से गुजारि है कि जल्दी से जल्दी बस-स्टैंड बनाया जाए।

जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, जगाधरी कांस्टीच्युएंसी में पिछले तीन सालों में दो स्कूल प्राइमरी से मिडल और दो स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड किए गए। पिछले साल एक भी हाई स्कूल और मिडल स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दो चार महीनों में बहुत जोर देने के बाद एक मिडल स्कूल हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया है। जो स्कूल सरकार ने अपग्रेड किए हैं, उन में ने कोई सामान है और न स्टाफ पूरा है और लोगों को डर है कि कहीं ये स्कूल सामान और स्टाफ पूरा न होने के कारण डाउन-ग्रेड न कर दिए जाए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन स्कूलों में सामान और स्टाफ जल्दी से जल्दी भिजवाने की कृपा करें। चैयरमैन साहब, स्कूलों के बारे में मैं एक जनरल सी बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे

हल्के मुस्तफाबाद में तीन स्कूल है एक मुस्तफाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, एक आर्य हाई स्कूल है और एक जनता हाई स्कूल है। मैट्रिक के इम्तिहान के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल को सैंटर बनाया था। एक तारीख को इस सैंटर में बच्चों का पेपर हुआ लेकिन पहली तारीख की भाम को यह सैंटर बदल दिया गया और तीन तारीख से जनता हाई स्कूल को सैंटर बना दिया गया और गवर्नमेंट हाई स्कूल पर यह एलीगे न लगाया गया कि वहां पर लड़के नकल करते हुए पकड़े गए पेपर बोर्ड पर लिखा हुआ पकड़ा गया। चेयरमैन साहब, यह खबर 11 तारीख की ट्रिब्यून अखबार में भी आई है जिसकी कटिंग मेरे पास है। जनता हाई स्कूल में, जहां पर यह सैंटर बदला गया है स्टाफ भी वही है और सुपरिन्टैंडेंट भी वही है। गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इस सैंटर को क्यों बदला गया है। बच्चों ने पहली तारीख को गवर्नमेंट हाई स्कूल में इम्तिहान दिया और तीन तारीख को जनता हाई स्कूल में दिया लेकिन यह कारण मालूम नहीं कि किस कारण ऐसा हुआ है, किस की रिपोर्ट पर किसने बदला, इसकी जांच-पड़ताल करवाई जानी चाहिए और बच्चों के साथ इस तरह का मजाक न किया जाए।

अब मैं थोड़ा सा हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। इस विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर्स काम करते हैं जिनकी कुछ मांगें थीं। सरकार ने इनकी मांगों के बारे में गौर करने का वायदा किया था। पता नहीं सरकार ने उनकी मांगों को माना है

या नहीं, लेकिन मैं उन मांगों में से एक ही मांग के बारे में बताना चाहता हूँ। मलेरिया इरैडिके इन स्कीम के तहत एक स्टैंसिल कटवाया जाता है जिसकी कापियां हर घर के बाहर चिपका दी जाती हैं। उस स्टैंसिल पर तारीख और दस्तखत करने के कालम बने होते हैं। जब मल्टी पर्पज वर्कज किसी घर में स्प्रे करने के लिए जाते हैं तो उस स्टैंसिल पर स्प्रे करने की तारीख और दस्तखत करने पड़ते हैं ताकि यह पता लग सके कि स्प्रे किया है या नहीं। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एम0एल0ए0 होस्टल में मच्छर बढ़ गए हैं, वहां भी स्प्रे करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कह रहा था कि उन वर्कज की एक डिमांड यह है कि इस स्टैंसिल को वहां से हटा देना चाहिए ताकि उनको वहां पर दस्तखत न करने पड़े। उनकी यह मांग बहुत जायज है। स्टैंसिल पर दस्तखत किए बगैर उनसे वैसे ही काम ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। जहां तक मलेरिया इरैडिके इन का सवाल है, मलेरिया खत्म होगा या नहीं, वह अलग बात है लेकिन नौर्दन स्टेट्स में जब मौसम एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो मच्छर अपने आप ही मर जाते हैं। इसके अलावा भी एंटी मलेरिया वैक्सीने इन की खोज हो रही है, भायद मलेरिया हमें ठीक के लिए खत्म हो जाए। चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं थोड़ा सा एम्पलाईज इन् गोरेंस स्कीम पर बोलना चाहूंगा। एम्पलाईज इन् गोरेंस स्कीम मजदूरों के लिए भु रू की गई है। इस स्कीम के तहत सारे मजदूर अपना कंट्रीब्यू इन पहले ही सरकार को भेज देते हैं और बाद में दवाईयां आती हैं। लेकिन

बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिस्पेंसरीज में दवाईयां मिलती ही नहीं। इस स्कीम के लिए बहुत सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, स्टेट का रूपया बहुत थोड़ा है और जहां तक मुझे मालूम है स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेन्स सिर्फ 16 परसेंट है, अब भायद थोड़ा बहुत बढ़ा दिया हो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्ज में दवाईयां मिलती ही नहीं ओर जो मिलती है और जो मिलती भी है वे इतने घटिया स्टैंडर्ड की है जैसे उसे यूज करने वाले मजदूर इन्सान ही नहीं। जब किसी डिस्पेंसरी में कोई मजदूर दवाई लेने जाता है तो पहले तो उसे दवाई मिलती ही नहीं अगर मिलती है तो वह बड़े घटिया स्टैंडर्ड की। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जगाधरी, पानीपत, फरीदाबाद और यमुनानगर इन बड़े सैन्टरों में जहां मजदूर बड़ी तादाद में काम करते हैं इनकी डिस्पेंसरियों में दवाईयों का इन्तजाम किया जाए और ई0एस0आई0 स्कीम के तहत जो डिस्पेंसरियां चल रही हैं उन का विशेष ध्यान रखा जाए। अब मैं थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में जिक्र करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, सब को पता है आबादी केवल हरियाणा में नहीं बढ़ी रही सारी दुनिया का मसला है। खास तौर पर मैडिकल प्रोफेशन वालों के लिए पापुलेशन की प्रोब्लम एक गम्भीर प्रोब्लम है। यह प्रोब्लम कैसे हल होगी, इसको समझना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि किसी वस्कोटौमी और ट्यूबोकटौमी के आपरेशन करने के लिए डाक्टरों पर कोई कम्पलशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस कम्पलशन से कई

खराबियां होने की सम्भावना है। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी भी डाक्टर के ऊपर इस प्रकार की कम्प्लेन नहीं होनी चाहिए। यह काम आप मैडिकल प्रोफैसन पर छोड़ दीजिए, डाक्टर ईमानदारी से काम करेंगे। अगर कम्प्लेन करेंगे तो कई बार अनवांटीज केसिज होने का खतरा रहता है। आप्रैसन करवाने के लिए लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है। जब लोग समझ जाएंगे कि उनका परिवार छोटा होना चाहिए छोटा करने के लिए योजना बनानी है तो वह खुदबखुद फैमिली प्लानिंग करवाने के लिए, आप्रैसन करवाने आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जनता को समझाना बहुत जरूरी है तभी फैमिली प्लानिंग ठीक तरह से लागू हो सकती है। मैं सरकार से गुजारिा करूंगा कि डाक्टरों पर कम्प्लेन लगाकर उनके इस प्रोफैसन को बदनाम न करें और जितना ज्यादा हो सके, लोगों को समझाने का प्रयत्न करें।

चेयरमैन साहब, कुछ बातें मैं ला एंड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूँ। टाईम कम है इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ला एंड आर्डर के बारे में मैं अपनी कांस्टीच्युएन्सी का किस्सा सुनाता हूँ। जगाधरी सब-डिविजल की बात है वहां दो हरिजनों का मर्डर हुआ है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। चेयरमैन साहब, एक गांव आपकी कांस्टीच्युएन्सी का है और एक गांव मेरी कांस्टीच्युएन्सी का है जहां ये दो मर्डर हुए हैं। एक केसा का तो बिल्कुल पता नहीं चला दूसरा अन-ट्रैस्टेड फाईल हो

गया है। रोहतक में एक हरिजन को जो केस हुआ है, वह तो आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा में ठीक नहीं हैं, इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से भी गुजारि करूंगा कि जगाधरी को जिला बनाया जाए। जगाधरी के बारे में कई दफा अखबारों में आया है कि इसको जिला बनाया जाएगा। चेयरमैन साहब, रैवेन्यू के मामले में जगाधरी नम्बर 1 पर है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जगाधरी को जिला बनाया जाए।

यह जो बजट आया है इसको इन्होंने टैक्सलैस बजट कहा है लेकिन यह केवल धोखा देने वाली बात है क्योंकि घाटा कहां से पूरा होगा? (विधन) सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी घाटा कैसे पूरा करेगी क्योंकि उनका भी घाटे का बजट है। मैं यह समझता हूँ कि आज तो यह बगैर टैक्स के है लेकिन इलैक्शन के बाद लगता है ऐसा हाल होगा भी भायद जनता ही मार्किट से गायब हो जाए जैसे कि 1975-76 में लोग ईखों में सोया करते थे। यह बात कह कर मैं बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी देस राज(इन्दरी): चेयरमैन साहब, जो सन् 1980-81 का बजट हमारे खजाना मंत्री श्री बलवंत राय तायल ने 10 मार्च को सदन में पेश किया है, मैं उसकी रिपोर्ट में कुछ

कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चेयरमैन साहब, 1980-81 का बजट 240 करोड़ रुपये का है जबकि पिछले साल श्री मूलचंद जैन जी ने जो बजट पेश किया था वह 227 करोड़ रुपये का था। उसमें भी टैक्सिज कितने थे, उसको सब जानते हैं। जब बजट पेश हुआ, जैन साहब जब उसे पढ़ रहे थे, इस सदन के कुछ मैम्बरान ने उसे फाड़ा था। (विधन) जैन साहब ने उन टैक्सिज को वापस ले लिया था तब कहीं वह उपस हुआ था लेकिन वापस क्यों लिया था यह सबको विदित है। उन्हीं दिनों करनाल लोक सभा का बाई-इलैक्शन होना था। हमारे साबका मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल के बड़े भाई साहब राम के दामाद वहां से इलैक्शन लड़ रहे थे। उस इलैक्शन को पेश करने पर नजर रखते हुए वे टैक्सिज वापस लिए गए थे।

श्री मूल चंद जैन: चेयरमैन साहब, इनकी बात ठीक नहीं है। वह बाई-इलैक्शन तो अप्रैल 1978 में हुआ था जबकि मैंने बजट मार्च, 1979 में पेश किया था लगभग 11 महीने का फर्क है। (विधन)

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब, इसी सदन में जो आज लोक दल के साथी बैठे हैं, उन्होंने पिछले साल और उससे पहले साल देहात में जाकर यह बात कही थी कि जो बजट चौधरी देवी लाल की सरकार ने पेश किया है उसका 66 फीसदी देहातों में खर्च होगा लेकिन लगता है कि इन्होंने इस बजट के आंकड़ों उठाकर नहीं देखें। अगर इस बजट को हम ध्यान से देखें तो

ऐग्रीकल्चर, कोआप्रे ान, वाटर एंड पावर डिवैल्पमेंट, ट्रांसपोर्ट और पंचायतों के ऊपर लगभग 82 परसेंट रूपया खर्च होगा। कहने का मतलब यह कि इतना पैसा देहातों में खर्च होगा। (विध्न) चेयरमैन साहब, यह बात बिल्कुल सही है कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने जो बजट बनाया है, वित्त मंत्री श्री बलवंत राय तायल जी ने जो बजट हाउस में पे ा किया है, उसके अनुसार पिछले दो सालों के बजट के बनिस्बत देहातों पर ज्यादा खर्च होगा। परसों आदरणीय डाक्टर मंगल सैन जी कह रहे थे कि यह डायरैक् ानलैस बजट है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं क्योंकि उनका लहजा खूब है, ऐक्टिंग भी खूब है लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि डायरैक् ान का जिसको पता नहीं उसको डायरैक् ान मिलती नहीं। (विध्न) इन्हें तो दिल्ली से डायरैक् ान आती है। अगर आदे ा आता है कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ गए और अगर आदे ा आता है कि पीछे हटना है तो पीछे हट गए। (ार व व्यवधान)

Mr. Chairman: No insterruption please.

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब, इनको तो दिल्ली से आदे ा की इन्तजार थी।(विध्न)

चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल मैं डाक्टर मंगल सैन पहल बार मी बने थे।(विध्न) अगर इनमें जुर्रत थी, अगर इन्होंने कोई डारैक् ान दिखानी थी, किसी बेसहारा को सहारा देना था तो इनको चाहिए था कि जब ये मंत्री बने थे तनख्वाह न लेते क्योंकि

अनमैरिड है और भाादी इन्होंने करानी नहीं है और तनख्वाह लेनी ही थी तो उसमें से किसी गरीब की इमदाद करते ।(विघ्न)

डा0 मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मेरी भाादी का इनको क्या फिक है । क्या यह मेरी भाादी का कहीं इन्तजाम करवा रहे है । मैंने भाादी नहीं करानी है और न ही मैं इनके नजदीक जाउंगा ।(विघ्न) मेरे पास वेयरहाउसिज नहीं है, मेर पास ने इनल परमिट्स नहीं है । (गोर)

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब, भाायद इन्हें पता नहीं कि मैं वेयरहाउसिंग कार्पोरे इन का चेयरमैन हूं लेकिन मैं तनख्वाह नहीं लेता, कोठी नहीं लेता ।(विघ्न) ये बात दे कि इन्होंने कौन सी ऐसी बात की है ।(गोर)

डा0 मंगल सैन: चेयरमैन साहब, ये बजट पर बिल्कुल नहीं बोल रहे है ।

श्री सभापति: यह मैंने देखना है या आपने देखना है कि बजट पर बोल रहे है या नहीं बोल रहे है?

Dr. Mangal Sein: My duty is also to draw your attention.

वित्त मंत्री(लाला बलवंत राय तायल): चेयरमैन साहब, कल जो डाक्टर साहब ने तकरीर दी है उससे यह मिलती जुलती है । (विघ्न)

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, तायल साहब कह रहे हैं कि मेरी तकरीर और इनकी तकरीर एक जैसी है। (विघ्न)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, न तो आप प्वायंट आफ आर्डर पर हैं और न ही मैंने आपको इजाजत दी है। अगर मैंने कुछ कहा तो आप नाराज हो जाएंगे। पहले आप स्पीकर साहब से नाराज हैं, आज मेरे से नाराज हो जाएंगे। (विघ्न)

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब, राम लाल वधवा जी मेरे बड़े भाई हैं।

श्री सभापति: मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप पर्सनल बात न करें। (विघ्न)

डा० मंगल सैन: इनकी यही ड्यंटी है।

चौधरी देस राज: वधवा साहब ने फरमाया था कि बलवंत राय तायल जी तो गांधीवादी हैं लेकिन प्रोहिबिशन के मामलों में लिबरल हो गए। वधवा साहब की तो वह बात है कि दूसरे को नसीहत खुद मियां फजीहत। वधवा साहब तो सुरा का लाईसैंस.....(गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। (गोर) यह इस बात को अगर साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना ये इस्तीफा दें। (गोर)

डा० मंगल सैन: ये करैक्टर असैसिने उन की बात करते हैं। (गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ।
(गोर)

श्री सभापति: आप बैठिए। यदि आप चाहेंगे तो आपको पर्सनल ऐक्सप्लेने उन का टाईम मिलेगा।

राजस्व मंत्री(चौधरी भोर सिंह): चेयरमैन साहब, ये तो लाईसैंस लेने की बात कर रहे थे। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, ये कसम उठाकर कहें कि मैं पीता हूँ। ***** (गोर)

लोक निर्माण मंत्री(कंवर राम पाल सिंह): चेयरमैन साहब, अभी तो सैन्टैन्स पूरा नहीं हुआ था। इन्होंने तो पहले ही अन्दाजा लगाना शुरू कर दिया।

श्री सभापति: क्या आपने किसी मैम्बर के खिलाफ भाराब पीने का ऐलीगे उन लगाया है? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी देस राज: जी नहीं।

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, सुरा भाब्द का मतलब ही भाराब होता है। यह भाब्द ऐक्सपंज होना चाहिए। (विघ्न)

अगर इस तरह की तकरीरें होनी है तो हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे। (गोर)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, आपने अपने आप ही अर्थ लगा लिया आखिर और लोग भी तो यहां बैठे है, मैं भी बैठा हूं। कौन कहता है कि सुरा का मतलब केवल भाराब ही होता है, कोई और मतलब भी तो हो सकता है। (विघ्न व भाोर)

चौधरी देस राज: जनता पार्टी के साथियों ने एक बात कही कि 31 करोड़ रूपए का घाटा है लेकिन मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि 17.2 करोड़ रूपए का घाटा इसमें पिछला भी शामिल है। चेयरमैन साहब यह घाटे का बजट होते हुए भी बहुत अच्छा बजट है।

चेयरमैन साहब, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जिन गांवों की आबादी प्लेन एरिया में 250 की होगी और पहाड़ी इलाके में 150 की होगी, उनको सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा। यह फैसला इस आधार पर लिया गया है कि सन् 1971 में जो मरदम जुमारी हुई थी उसके हिसाब से 250 और 150 की आबादी ली है लेकिन मैं सरकार से गुजारि करूंगा कि जो मौजूदा आबादी गांव की है उसके हिसाब से सड़कें बनाई जाएं क्योंकि सन् 1971 के बाद तो गांव में काफी आबादी बढ़ चुकी है।

चेयरमैन साहब, बैकवर्ड क्लासिज और रिड्यूल्ड कास्टस के बारे में जो फैसले किए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं,

उनको बड़ी अच्छी सहूलियतें दी गई है। मास्टर हुक्म सिंह जी कह रहे थे कि यह कैपिटेलिस्टस का बजट है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे कह रहे हैं कि यह कैपिटेलिस्ट का बजट है। मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ कि रिटायर्ड कास्टस के लिए जो यह निर्णय लिया गया है कि मैट्रिक तक के लड़कों को वजीफा 8 रूपए से 16 रूपए तक बढ़ाया है और मैट्रिक से ऊपर के लड़कों के लिए जो पहले 15 और 35 रूपए था उसको 30 और 70 रूपए कर दिया गया है। बैकवर्ड के लिए अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने अयोरेंस दी है कि उनको और भी अधिक सहूलियतें देंगे। बैकवर्ड क्लास के लोगों की रिजर्वेंशन पांच से दस परसेंट की है। चेयरमैन साहब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार ने बैकवर्ड क्लास के लिए वजीफा देने की जो लिमिट रखी है वह 3,600 रूपए आमदनी रखी है। आजकल की तन्खाह का हिसाब लगाया जाए तो क्लास फोर और सिपाही भी 3,600 रूपए से ज्यादा तन्खाह लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि बैकवर्ड क्लास के लोग तो यह फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बैकवर्ड क्लास के लोग फायदा उठा सकें।

दूसरी बात बैकवर्ड जाति के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे यहां कंबोज जाति सन् 1959 यानी सरदार प्रताप सिंह कैरों के टाईम से बैकवर्ड चली आ रही है परन्तु कभी पांच साल के लिए कभी तीन साल के लिए उसका टाईम बढ़ा देते हैं। इस

तरह से 22 साल हो गए हैं, उनको परमानेंट तौर पर बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको परमानेंट तौर पर बैकवर्ड करार दिया जाए।

चेयरमैन साहब, मेरे इन्दरी हल्के में सितम्बर सन् 1979 में सी0 एम0 साहब गए थे उन्होंने वहां यह कहा था कि इन्दरी में 25 बैड्ज का हास्पिटल और एक हैफेड की ओर से भौलर लगाया जाएगा परन्तु अभी तक वहां कोई भी चीज पूरी नहीं हुई। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि है कि दोनों मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं। (विघ्न)

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह** के बारे में जो कहा गया है। यह एक्सपंज कराया जाए। यह अनपार्लियामेंटरी है।

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब, मैं भौलर के बार में अर्ज कर रहा था। (विघ्न).....

डा0 मंगल सैन: चेयरमैन साहब, एक मैम्बर एकसी भाशा का प्रयोग करे, यह हाउस के लिए भाभा की बात नहीं है। ये भाब्द एक्सपंच होने चाहिए।

श्री सभापति: इन्दरी के बारे में जो अनपार्लियामेंटरी भाब्द प्रयोग किए गए है उनो एक्सपंच कर दिया जाए।

चौधरी देस राज: चेयरमैन साहब हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरे इन 66 सैन्टर्ज पर वेयर हाउसिज चला रही है लेकिन एफ0सी0आई0 भी लाखों टन कैपेसिटी अनाज स्टोर करने के लिए अपन वेयरहाउसिज बनाने जा रही है। हमारी स्टेट में जो वेयरहाउसिज चल रहे है वे सभी एफ0सी0आई0 पर डिपैन्ड करते है क्योंकि एफ0सी0आई0 का अनाज हम स्टाक करते है। अगर वह अपने ही वेयरहाउसिज बना लेंगे तो चार-पांच साल के अन्दर ही हमें वहां से माल स्टोर करने को नहीं मिलेगा और हमारी कार्पोरे इन को नुकसान होगा और इस कार्पोरे इन का चलना भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए उनको स्टेट में इतने वेयरहाउसिज बनाने की इजाजत न दी जाए।

चेयरमैन साहब, इन भाब्डों के साथ मैं इस बजट की तार्ईद करता हूं कि यह बहुत अच्छा बजट है और इससे गरीबों को राहत मिलेगी।

श्री हरफूल सिंह(फतेहाबाद): चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट हाउस के सामने पे र किया है, उस पर काफी बहस हो चुकी है। यह बजट तीन चार पार्टियों द्वारा बनाया गया है। कांग्रेस (आई) का ही बनाया हुआ बजट नहीं है।

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं इस बात पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या सुरा का अर्थ भाराब नहीं होता?

श्री सभापति: सुरा भाराब नहीं होती।

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, यह हमारी लायब्रेरी की इंग्लिश की डिक्शनरी के पेज 848 पर सुरा भाब्द का अर्थ वाईन लिखा हुआ है। इसलिए देस राज जी ने जो सुरा भाब्द का प्रयोग किया था वह गलत है। आपने जो अर्थ बताया वह अर्थ नहीं होता। सुरा का अर्थ भाराब ही होता है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी रामलाल वधवा द्वारा

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। चेयरमैन साहब, मैं सुरा यानी भाराब बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। यह इन्होंने गलत कहा है।

श्री सभापति: डा० साहब आपकी बात मान लेते हैं। वधवा साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करता। वैसे भी मैम्बर साहब ने सुरा के लाईसेंस की बात की थी।

डा० मंगल सैन: आप सुरा भाब्द का अर्थ भाराब नहीं मान रहे थे। मैं तो यही मनवाना चाहता था कि इसका अर्थ यही होता है।

वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री हरफूल सिंह: चेयरमैन साहब, इस हाउस में जो बजट पे 1 हुआ है इसके बारे ट्रेजरी बेंचिज की ओर से काफी अच्छी बातें कही गयी हैं। लेकिन मेर विचार के अनुसार इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। यह बजट जो इन्होंने पे 1 किया है यह धोखे का बजट है,** गलत है। (ओर व व्यवधान)

श्री सभापति: बोगस भाब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

कंवर राम पाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या चौधरी संत कंवर जी ने कोई लाइसेंस ले रखा है कि वे कहीं से भी बोलने लग जाएं, इनको अपनी ही सीट से बोलना चाहिए।

श्री हरफूल सिंह: चेयरमैन साहब, ये इस बजट के अन्दर बड़ी-बड़ी डींगे मार रहे है, जबकि इस बजट के अन्दर किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया। ये कह रहे है कि हम सेंटर से पैसा ले आएंगे, इंदिरा गांधी जी से पैसा ले आएंगे, ये यहां पर बैठे** बोल रहे है।

श्री सभापति: यहां हाउस में अन-पार्लियामेंट भाब्द न बोले। 'झूठ' भाब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

मैं हाउस को एक इन्फर्मे 1 न देना चाहता हूं। The Election Commission has fixed the hours from 11.00 A.M. to 3.00 P.M. as the hours during which the poll shall be taken for the election to the Council of State by the elected members of the Haryana Legislative Assembly to be held on Saturday,

the 15th March, 1980, in the Committee Room, Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan, Chandigarh.

श्री हरफूल सिंह: चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि यह बजट घाटे का बजट है। इनको टैक्स लगाने ही पड़ेंगे। यदि ये टैक्स नहीं लगायेंगे तो सरकार का काम नहीं चलेगा। चेयरमैन साहब, इन लोगों का तो वही हाल है नई-नई मुसलमाननी; अल्ला-अल्ला पुकारे। जो भाई ट्रेजरी बेंचिज की तरफ बैठे हुए है वे 3 दिन से चिल्ला रहें हैं और इन्दिरा गांधी की बातें कर रहे हैं। इन्दिरा इनको स्वर्ग में ले जाएगी और ऊपर उठा देगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये ऐसी बातें कैसे कह रहे हैं। यदि भारतवर्ष में 30 साल के अर्से में गरीबी नाम की कोई चीज आई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इंदिरा गांधी पर है। मेरे पास इसके उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। नेता तो हम उस को कहेंगे जिसकी नियत ठीक हो।*****इंदिरा गांधी नेता है। नेता इसलिए है कि वह स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू जी की बेटी है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि इंदिरा जिताओं, गरीबी हटाओ।

चेयरमैन साहब, इस बजट में गरीब लोगों के बारे में कोई बात नहीं कहीं गई है। जिस बजट को पास करने जा रहे हैं इस में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं कहा गया है। हमारे खजाना मंत्री श्री तायल साहब जिस पार्टी के तरफ से बजट पे आ कर रहे हैं, वे अभी उसी पार्टी के उम्मीदवार श्री बंसी लाल के

मुकाबले में कुछ दिन पहले हार कर आये है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के आदमी से हार कर आया हो वह इस हाउस में उसी पार्टी का बजट पे टा करे।

चेयरमैन साहब, यह इतना गंदा बजट पे टा हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापति: चौधरी साहब, आप इसमें कोई सुजै टान दीजिए।

स्वामी आदित्यवे टा: आन ए प्वायंट आर्डर सर। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लठ दल वाले भाई है क्या इनको सब कुछ कहने की इजाजत है?

चौधरी संत कंवर: जिस दिन भी लठ दल वालों लठ उठा लिया तो वे आपको हरियाणा से बाहर छोड़ आयेंगे।

कंवर राम पाल सिंह: चेयरमैन साहब, श्री संत कंवर जी ने अभी कहा है कि वे स्वामी जी को हरियाणा से बाहर छोड़ आयेगे, ऐसी बातें इनको नहीं कहनी चाहिए (व्यवधान व भाोर)

श्री हरफूल सिंह: चेयरमैन साहब, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे? स्वामी जी को चाहिए था कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले साल भाराब बंदी के बारे में भूख हड़ताल की थी, अगर वह ईमानदार है, और ईमानदारी की बात करना चाहते है तो आज भी इनको चाहिए था

कि वे भाराब बंदी के बारे में भूख हड़ताल करते। (व्यवधान व भाोर) चेयरमैन साहब, ये बीच में टोक रहे हैं। इनको इस प्रकार से बीच में नहीं बोलना चाहिए।

चेयरमैन साहब, यदि इस घाटे को यह सरकार पूरा करना चाहे तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं, तरीके हैं जिससे इस घाटे को पूरा किया जा सकता है। एक-एक महकमें के साथ 3-4 कार्पोरे इन को जोड़ दिया जाये तो यह घाटा पूरा किया जा सकता है। जिस प्रकार से एम0आई0टी0सी0 है। इस कार्पोरे इन में 17-18 एस0ई0 है, 300-400 के करीब एस0डी0ओ0 है और 60-70 के करीब एक्स0ई0एन0 है। यदि इस कार्पोरे इन को तोड़ दिया जाए और इस महकमें को नही के महकमे के साथ मिला दिया जाये तो करोड़ों रूपये का घाटा पूरा किया जा सकता है। चेयरमैन साहब, कई भाइयों ने टूरिजम कम्पलैक्स बनाये जाने की बात कही है। हमारे भारतवर्ष के अन्दर इतनी अधिक मात्रा में गरीबी है कि गरीब आदमी एक-एक चारपाई पर चार-चार आदमी एक ही रिजाई के अन्दर सोते हैं। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बजट गरीबों का बजट नहीं है। इस बजट में गरीब आदमी की भलाई के लिए कोई बात नहीं कही गई है। हमारे स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था और आज श्री चरण सिंह जी ने भी कहा है कि हर हाथ को काम दिए बगैर गरीबी नहीं मिटाई जा सकती लेकिन चेयरमैन साहब, आज ये बड़ी-बड़ी कार्पोरे ान्ज खोल कर और बड़ी-बड़ी कम्पनियां

खोल कर दे । के अन्दर घाटा बढ़ा रहे है । हरियाणा के इस बजट के अन्दर कहीं पर भी किसी भी वर्ग की भलाई के लिए कोई बात नहीं कही गई । न ही इन को किसी मदद का आ वासन इस बजट के अन्दर दिलाया गया है ।

श्री सभापति: चौधरी साहब, आप जल्दी खत्म कर ले अभी बहुत से मैम्बरों ने बोलना है ।

श्री हरफूल सिंह: आजकल गांवों में यह हालत हो गई है कि गांवों के पढ़े-लिखे नवयुवक लम्बे-लम्बे बाल रखकर तथा लम्बी-लम्बी दाड़ी रखकर रोजगार न मिलने के कारण घूमते फिर रहे है । इस बजट के अन्दर पढ़े-लिखे नवयुवकों को भी रोजगार देने की कोई बात नहीं कही गई । जो मेरे भाई दल-बदल करके चले गए है, वे करोड़ो रूपये खा गए है । चेयरमैन साहब, पिछले दिनों हमारी एक चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी के बारे में उसके पति की ओर से खबर अखबारों में छपी थी कि उसकी औरत को कहीं पर छुपाकर रखा गया है (व्यवधान व भाोर) मैं इन्हीं भाब्दों के साथ आपका भुक्तिया अदा करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

श्री लहरी सिंह मेहरा(रादौर-अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं आपका भुक्तिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया । चेयरमैन साहब, लाला बलवन्त राय तायल ने 1980-81 का जो बजट पे । किया है वह बहुत ही अच्छा बजट है हरियाणा की गरीब जनता के लिए यह एक बहुत

अच्छी देन है। चेयरमैन साहब, आपको दच्छी तरह याद होगा कि पिछली सरकार में जब बाबू मल चंद जैन ने बजट पे 1 किया था, इस सदन के सभी सदस्य इस बात के गवाह है कि उस बजट स्पीच की कापियां यहां पर काफी फाड़ी गईं और एक-एक पन्ना यहां पर फैंका गया था। आज ये ही भाई यहां पर टोंट कसते हैं कि यह बजट अच्छा नहीं है (व्यवधान व भाोर) मैं अपोजी उन के भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस समय आप लोग कहां गए थे जिस समय आप लोगों ने बजट की स्पीच को फाड़ा था। (व्यवधान व भाोर) चौधरी सतवीर सिंह ने बजट के पन्ने फाड़ कर सारे होउस में फैंक दिए थे। चेयरमैन साहब, आज जब इस बजट स्पीच पर डिस्क उन हो रहीं हैं तो इस समय तमाम लोगों के मुंह बंद है क्योंकि इस बजट के खिलाफ आप लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। चेयरमैन साहब, आज अपोजी उन के भाई आदरणीय चौधरी चांद राम का नाम बहुत लेते हैं और उनका बड़ा जिक्र अपनी स्पीचों में करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं, मेरे साथी और कांग्रेस के जितने दूसरे लोग हैं, चौधरी चांद राम उनके बाहिद लीडर हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। चेयरमैन साहब, वे जनता के लीडर हैं और जनता ने उनको लीडर माना है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता।

मास्टर विव प्रसाद: तभी वे रोहतक में हारे थे।

श्री लहरी सिंह मेहरा: वह आपकी करतूतो से हारे थे (व्यवधान)।

मास्टर िव प्रसाद: आपकी करतूतों से हारे थे हमारी से नहीं (व्यवधान)।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि आदरणीय चौधरी चांद राम हमारे लीडर है.....

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति: यह सारा रिकार्ड न किया जाये।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, यह बात मैंने उस समय भी कही थी कि वे मेरे नेता है और आज भी कहता हूं कि वे मेरे नेता है। मैंने कभी भी उसको नेता मानने से इन्कार नहीं किया है और न भविश्य में नेता मानने से इन्कार करूंगा। मैं उनकी देन हूं, मैं उनकी उपज हूं। मैं अपोजी उन के भाइयों की नेकनामी की दाद देता हूं, मैं लोकदल के भाइयों की नेकनामी की दाद देता हूं कि मेरे भोरों आप लोगों ने (व्यवधान व भोर)

श्री सभापति: भोर कहते है तब भी आप बुरा मानते है यदि गीदड़ कहेंगे फिर तो आप बुरा मानोगें ही।

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आर्डर। चेयरमैन साहब, इंसान को जानवर में तब्दील करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति: यह तो बहादुरी वाली बात है। बुराई की बात नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, मैं इस बात को मानता हूँ कि जनता पार्टी के बनाने में हमने पूरा योगदान दिया था। हम खुद जेल में गए थे और दूसरे साथी भी हमारे साथ थे (व्यवधान)।

श्री रघुनाथ गोयल: चेयरमैन साहब, एमरजेंसी के अन्दर इनके बाल काट कर और इनका सिर मुंडवा कर तहखाने में बंद कर दिया था। ये वे दिन भूल गए थे और आज ये उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। (व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि श्री रघुनाथ गोयल की आंखे मोम के कोटे की परत से बंद है (व्यवधान) सभापति महोदय, ये लोग जितना टाईम मेरा ले रहे हैं उतना टाईम मुझे मिलना चाहिए। मैं कह रहा था कि आदरणीय चौधरी चांद राम को लोकदल के भाइयों ने हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर.....(व्यवधान एवं भाोर)।

श्री जय नारायण वर्मा: चेयरमैन साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि ये चौधरी चांद राम पर बोल रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं (व्यवधान)।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, इस दुनिया में कोई वि वास नहीं कर सकता कि ऐसा वि वासघात भी किसी

आदमी के साथ किया जा सकता है। उनको घर पर बुलाकर मीठी-मीठी बातें करते रहे और पीछे से उनके घर पर रेड करवा दिया। घर का एक-एक कोना खुदवाया कि कुछ जमीन में तो नहीं दबाया हुआ। चेयरमैन साहब, उनके घर में कुछ नहीं निकला। इसनके लिए यह अच्छी बात नहीं है (व्यवधान व भाोर)। सभापति महोदय, मैंने तो इस बात का जिक्र इसलिए किया कि उनके साथ इन्होंने ऐसा बुरा व्यवहार किया। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी जय नारायण: चेयरमैन साहब, जिस वक्त छापा मारा गया था उस वक्त सारा माल इनके घर पर रखा हुआ था (व्यवधान)

श्री भले राम: चेयरमैन साहब, ये चौधरी चांद राम की इस वक्त तारीफ कर रहे हैं। हम एक बार भाकुन्तला के घर चाय पीने के लिए गए थे वहां पर इन्होंने चौधरी चांद राम को गालियां दी थी और आज तारीफ कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, इन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगाया है और इसका जवाब मैं एक मिनट में दे देता हूं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और चंडीगढ़ के अलावा सारे हरियाणा में कहीं भी मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। (व्यवधान) भले राम जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं कभी भी respectable words के बिना आदरणीय चौधरी चांद राम को सम्बोधित नहीं करता।

चौधरी संत कंवर: आपके बाप दादा भी कभी चंडीगढ़ में रहे हैं?

श्री सभापति: मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि यहां पर किसी मैम्बर के बारे में यह बात न करें कि आपके बाप दादा भी कभी चंडीगढ़ में रहे हैं। यहां पर एक मैम्बर को दूसरे मैम्बर की रिस्पैक्ट करनी चाहिए। मेरी रिक्वैस्ट है कि आनरेबल मैम्बर अपने भाब्द वापिस ले लें।

चौधरी संत कंवर: मैंने तो सरसरी तौर वर ये भाब्द कहे थे। आप कहते हैं तो मैं विदज्ञा कर लेता हूं। (व्यवधान)

Shri Baldev Tayal: Mr. Chairman, I draw your attention to sub-rule (2) of Rule 100 of the Assembly Rules which says-

“(2) A member which speaking shall not-

(i) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on substantive motion draw in proper terms;

(ii) use the name of persons in high authority for the purpose of influencing the debate;

श्री सभापति: तायल साहब, ऐसी बात नहीं है आप जो अभी पढ़ रहे हैं, वही मुझे दिखाया जा रहा था, आपकी जानकारी के लिये मैं बता देता हूं कि यहा काम उनकी ड्यूटी में आता है।

Shri Baldev Tayal: My humble submission to the Chair is that the hon. Member who is speaking may please be asked not to speak on a particular conduct or in praise of a

person, who is supposed to be a high dignitary. He should make his speech on the budgetary aspects and not on extraneous matters. If you think that he is speaking that way, it is for you to decide.

श्री सभापति: तायल साहब, आपकी बात ठीक है। मैं आनरेबल मैम्बर साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे बजट तक ही अपनी स्पीच को सीमित रखें।

Shri Baldev Tayal: Thank you for this, Mr. Chairman.

श्री लहरी सिंह मेहरा: बहुत अच्छा जी। सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोलता हूँ। पहले विपक्ष की तरफ से एक ऐसा आइटम सा खड़ा कर दिया गया था, जिस पर मुझ जवाब देना पड़ गया था। सभापति महोदय, इस बजट स्पीच के अन्दर जितने काम, लोगों की भलाई के लिए किये गये हैं, भायद ही जनता सरकार ने या किसी और सरकार ने किये होंगे। बाबू मूल चंद जैन जी ने भी जो बजट पे किया था, उससे कहीं बेहतर यह बजट है। पहले 227 करोड़ का बजट रखा गया था अग इस सरकार ने करोड़ रूपये का बजट रखा है और कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि जो इस सरकार ने 50 रूपये सफाई मजदूरों के लिए और 6 से 8 रूपये जो working labour के बढ़ाये हैं, ये जनता सरकार की देन थी, मैं इसको मानता हूँ कि वह जनता के भासन में बढ़ाये गये थे लेकिन यह सिर्फ चौधरी भजन लाल जी की वजह से ही बढ़ाये गये थे। इससे पहले चौधरी देवी लाल हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, वे कोई दो ढाई साल तक

राज्य करते रहे और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकें जिसकी वजह से लोगों की भलाई हो सके। उसका कारण यह था कि उनके चारो तरफ एक ऐसा वातावरण था कि उस वातावरण में और कोई आदमी किसी किस्म की सलाह देने के लिये आ ही नहीं सकता था। उस वक्त जो मीटिंगें हुआ करती थी, उनमें उस वक्त डाक्टर मंगल सैन जी भी हुआ करते थे। उनके बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे तो कभी हरिजनों का भला सोच नहीं नहीं सकते। (गोर एवं व्यवधान) आदरणीय डाक्टर साहब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको सच्चाई के साथ कहता हूँ कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को बदलवाने के लिए बड़ी कोशिश की लेकिन वह बदले नहीं जा सके। (गोर एवं व्यवधान) क्योंकि वे चाहते थे कि हरिजनों के लिए गांवों में रूलर इंडस्ट्रीलाइजेसन की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इस तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आरे में यहां पर यह कहना कि किसी मिनिस्टर ने किसी अफसर के साथ यह किया, वह किया, क्या ये आनरेबल मैम्बर बजट स्पीच पर बोलते हुए इस तरह के सवाल उठा सकते हैं? यह रैलवेन्ट नहीं बोल रहें हैं। (गोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, यह मंत्री महोदय पर एसपेक्टिव है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, ये रैलवेंट बोल रहे हैं। यह तो भलाई और बुराई की बात कर रहे हैं। यह किसी के ऊपर एसप नि नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

Shrimati Sushma Swaraj: Mr. Chairman, it is a reflection on the Minister that he did not like a particular person because he was a Harijan. It should be expunged from the record.

Dr. Mangal Sein: Mr. Chairman, it is absolutely wrong, Sir.

VOICES: Do not cast aspersions on anyone.

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, अब इस तरह की रूकावटें ये अपोजी इन के भाई डाल रहे हैं कि यह नहीं बोलना चाहिये, वह नहीं बोलना चाहिये। क्या कल डाक्टर मंगल सैन जी को यहां पर सब कुछ कहने का अधिकार था और किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है?

Shri Baldev Tayal: Mr. Chairman] he cannot cast aspersion like this. If the name of an officer is mentioned, the bureaucracy will be allowed to be dragged into discussion of this Hon. House and there will be no end to it and the high officers/bureaucracy and other people of the general administration will not be spared. Of course, one can say something about their conduct/authority and the way of working in general terms but nobody should be dragged into discussion by name. So, I would request the Chair to at least expunge the name of the officer about whom reference has been made.

श्री सभापति: मिस्टर पुनिया का नाम प्रोसीडिंग्स में से निकाल दीजिये।

श्री लहरी सिंह मेहरा: सभापति महोदय, मैं तो इस तरह के 20 उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण देते समय मैंने तो केवल सरसरी तौर पर नाम ले दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिये इन्होंने इतना भाोर डालना भुरू कर दिया। आप बे 1 कवह नाम एक्सपन्ज करवा दीजिये। मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे जो जो डायरेक्टर थे, मेरी उनसे कोई दु मनी नहीं थी। मैंने केवल इतना ही बताना था कि वे अफसर हरिजनों की रूलर इंडसिट्रयलाइजे ान की जो स्कीम है, उसको कामयाब करना चाहते थे मगर उस वक्त डाक्टर साहब, इस बात के विरुद्ध थे। (गोर एवं व्यवधान) (ेम— ेम की आवाजें)

मास्टर िव प्रसाद: आप भी तो.....काम करवाते थे।

श्री लहरी सिंह मेहरा: कौन लेता था? कौन काम करवाता था?

मास्टर िव प्रसाद: आप लेते थे।

श्री लहरी सिंह मेहरा: सभापति महोदय, यह गलत कह रहे हैं, ये इन एलीगे ान्ज को सिद्ध करें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: यह जो हरिजनों से पैसे ले ले कर वाला भाब्द है, इसको एक्सपन्ज कर दिया जाए।

श्री लहरी सिंह मेहरा: सीभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारा यह जो बजट है, यह बहुत अच्छा बजट है। अच्छे

ढंग से इसे बनाया गया है और उसमें गरीबों की भलाई के लिये काफी कुछ प्रोवीजन किया गया है।

अब मैं एग्रीकलचर के बारे में बताना चाहता हूँ। यह बजट किसान की भलाई वाला बजट है क्योंकि इसमें किसान के लिए बहुत भारी रकम रखी गई है। इसमें किसान की खालें पक्की करने के लिए और बीज पर सबसिडी देने के लिए पैसे रखे गए हैं। इसके साथ-साथ खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई साधनों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जहाँ.....
(व्यवधान)

चौधरी जय नारायण:

श्री सभापति महोदय: जो चौधरी जय नारायण ने कहा है, यह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी जगदी 1 कुमार बैनीवाल: चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर इतना पैसा खर्चा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का पैसा तो इन्होंने काट दिया है खेती बाड़ी से।

श्री सभापति: यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि किसान की सहूलियत के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन मैं फिर भी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ओलावृष्टि के कारण या सूखें के कारण जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें पिछले साल की तरह से उसी रे तो के

हिसाब से मदद दी जाए। इस मदद का हिस्सा किसानों के नौकरों और सीरियों को भी दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जगाधरी से लेकर एक आगमैंटे इन कैनल बनाई गई है और उस पर बुर्जिया लगी हुई है और ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं। इससे मेरे हल्के के चोओं के पानी का लेवल अढ़ाई तीन सौ फीट नीचे चला गया है। जिस समय ये ट्यूबवैल्ज नहीं लगे हुए थे उस तीस चालीस फीट से पानी निकलता था। इससे मेरे हल्के के गरीब किसान और मजदूर को बहुत नुकसान हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस आगमैंटे इन कैनल में अगर यमुना का पानी आ जाए, तो केवल मेरा ही हल्का नहीं बल्कि यमुना नगर, रादौर, इन्दरी, करनाल और धरौंडा तक के हल्कों को फायदा होगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि उन बुर्जियों को बंद किया जाए और यमुना नदी से उस आगमैंटे इन कैनल में पानी डाला जाए। ऐसा करने से यह पानी आगे टेल तक यानी महेंद्रगढ़ और भिवानी तक जा सकेगा। (घंटी) चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से सतलुत यमुना लिंक कैनल के मामले पर दो अढ़ाई साल से खींचातानी चल रही है अगर उसको जल्दी जल्दी से निपटा दिया जाए तो उससे मेरा हल्का भी बच जाएगा और अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले भी बच जाएंगे। इसके इलावा महेंद्रगढ़ की तरफ भी पानी चला जाएगा।

इसके बाद मैं असली प्वांयट पर आता हूं। वह है रिजर्वे इन का। जहां हमारी रिजर्वे इन 20 प्रति अत होनी

चाहिए वहां क्लास वन में 3 प्रति 1त है, क्लास दो में 3.5 प्रति 1त है, क्लास तीन में 6 प्रति 1त है और क्लास चार में 20 प्रति 1त है। क्लास चार में सफाई मजदूर आते है और आपको अच्छी तरह से पता है कि यह काम और कोई जाति का आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि रिजर्वे 1न का कोटा पूरा करने का प्रयत्न करें। हमारी सरकार ने एक हरिजन कल्याण निगम स्थापित की हुई है और अब की बार जो बजट हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज की भलाई के लिए रखा गया है, यह पिछले बजट से दोगुना जरूर है लेकिन बहुत कम है। इसलिए इसको ज्यादा किया जाए। इनके लिए जहां 1 करोड़ 54 लाख रूपए रखे गए है मैं चाहता हूं कि उसकी जगह कम से कम 10 करोड़ रूपए रखें जाएं ताकि हर हरिजन को कुछ ने कुछ फायदा हो सके। जो निगम सरकार की तरफ से स्थापित की गई है उसकी लिमिट दो करोड़ रूपए की है, मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा कर भी दस करोड़ किया जाए ताकि हर हरिजन को, हर गरीब आदमी को अच्छी से अच्छी ट्रेड सिखा कर ओर उनको कर्जे देकर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। (व्यवधान व भाोर) चेयरमैन साहब, उधर की तरफ से जो नुक्ताचीनी हो रही है मैं उसका आधे मिनट में जवाब दे रहा हूं। यू0 पी0 सरकार ने जाते-जाते हरिजनों की रिजर्वे 1न खत्म कर दी (ओर एवं व्यवधान) यह लोकदल तथा जनसंघ को हरिजनों के प्रति प्यार है। चेयरमैन साहब, सोनीपत में एक ज्योति स्टील कम्पनी है

वहां से पिछले साल डा0 मंगल सैन कन्यादान की तरह बर्तन लेकर आए.....(गोर)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

डा0 मंगल सैन द्वारा

डा0 मंगल सैन: चेयरमैन साहब, आन ए प्वांयट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। इन्होंने मेरे ऊपर एलीगेशन लगाया कि मैं कन्यादान में कुछ लेकर आया हूँ। जो कुछ चौधरी लहरी सिंह ने कहा है सरासर गलत कहा है। (गोर) मैं आपके द्वारा उनको चुनौती देता हूँ कि मैं इनको ऐसे अफसरों के नाम बता सकता हूँ जो कांग्रेस के राज में पीड़ित थे और मैंने उनके ग्रीवेंसिज को दूर किया है। (गोर व घंटी)

श्री लहरी सिंह मेहरा: मैंने तो कन्यादान की तरह से कहा है। धन्यवाद!

वर्ष 1980—81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक (नौलथा): चेयरमैन साहब, इस हाउस के अन्दर जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में मैंने मोटी-मोटी किताबों को पढ़ कर काफी कोशिश की कि भायद इसके अन्दर कोई नई चीज मिल जाए। लेकिन वित्त मंत्री की स्पीच में सिवाए इसके कुछ नहीं था कि जो कुछ जनता पार्टी की सरकार ने अपने पिछले बजट में नई प्लानिंग के मुताबिक स्कीम बनाई थी, सिर्फ वही उपलब्धियों और स्कीमों इस बजट के अन्दर दिखाई गई है। कोई और नई पालिसी नहीं दिखाई गई कि सरकार अगले साल क्या करने जा रही है। कोई नया प्लान

या नया प्रोग्राम इस बजट स्पीच के अन्दर नहीं है। वित्त मंत्री ने इसमें खास तौर पर एक बात रखी है। ट्रेजरी बेंचिज के मेरे साथियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कहा है कि यह टैक्स-लैस बजट है। लेकिन मे। यह कहता हूँ कि यह किसी वैलफेयर स्टेट के वित्त मंत्री द्वारा पे । किया गया बजट नहीं है। यह एक ऐसा बजट है जो मिस-लीडिंग और मिसचीवियस बजट है। यह बिल्कुल रूखा और सूखा बजट है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी राम कि ।न, पदासीन हुए) ऐसे मिसचिवियस बजट के अन्दर जो कोई डायरेक् ।न न दे सके, सरकार ने टैक्स न लगा कर इसका घाटा जो है वह बहुत ज्यादा द ार्या है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बजट के अन्दर सरकार ने किसानों और मजदूरों की बहतरी के लिए कोई नई स्कीम नहीं बनाई है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा जो घाटा वित्त मंत्री जी और सरकार की तरफ से माना गया है वह 31 करोड़ का है और 15 करोड़ इसमें पे-कमी ।न की रिपोर्ट की वजह से भामिल होने वाला है। इसके दो लोन सेंटर के भी है। एक 10 करोड़ रूपए का है और दूसरा 3 करोड़ का है। इस प्रकार से यह कुल घाटा लगभग 60 करोड़ रूपए का हो जाता है। चेयरमैन साहब, मैं जानता हूँ कि जिन अधिकारियों ने इस बजट के बनाने में वित्त मंत्री जी की सहायता की है, उन्होंने दो साल मेरे साथ भी काम किया है। ये अधिकारी बहुत ही इन्टैलीजेंट है और हरियाणा की कीम है। चेयरमैन साहब, फाईनैस मिनिस्टर साहब, ने कहा है कि हम को ि । । करेंगे कि

सैंटर इस लोन को लॉंग टर्म लोन में चेंज कर दे। चेयरमैन साहब, जो 13 करोड़ का घाटा इन्होंने अपने बजट में दिखाया यदि सैंट्रल गवर्नमेंट इस 13 करोड़ के लोन को लॉंग टर्म लोन में चेंज करने के लिए न माने तो क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि यह घाटा बढ़ेगा या घटेगा? चेयरमैन साहब, इस बजट के अन्दर तीन चीजें मैंने नई पाई है। एक तो इस सरकार ने मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया है। दूसरा चौधरी भजन लाल जी ने आदमपुर में एक नया अस्पताल बनाया है और तीसरे चौधरी भजन लाल जी ने डिफैक्ट इन की एक हिस्ट्री कायम की है। चेयरमैन साहब, मैं तो चाहता हूँ कि इनको किसी यूनिवर्सिटी से डाक्टरेट की डिग्री दिला दी जाये जो इन्होंने इतना लार्ज स्केल पर डिफैक्ट इन किया है। ये पार्टी के जनरल सैक्रेटरी, पार्टी के मिनिस्टर्स और पार्टी के मैम्बरों की टीम की टीम को ले कर दूसरी पार्टी में भामिल हो गये और उन्हें यह कहा कि अब हम आपके मेहमान है और आपके नाम पर कार्य करेंगे। ये तीन काम तो इन्होंने किये है। बाकी सारी की सारी स्कीमें पुरानी सरकार की हैं। जैसे हैल्थ की हैं, एग्रीकल्चर की है और इरीगे इन की हैं। ये सारी की सारी स्कीमें उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थीं। चेयरमैन साहब, आज जो यहां हाउस में सिद्धांत का नाम लेते है, उस सिद्धांत का रूप स्वामी जी बैठे है। ये सिद्धांत की बात करते है और कहते है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का िशय हूँ। वैसे तो मैं भी अपना नाम स्वामी जी के प्रथम श्रेणी के िशयों में गिनता हूँ। चेयरमैन साहब, जो

हमारे 'हू इज हू' की किताब छपी हुई है उसके अंदर एक स्पैसीमैन प्रोफार्मा है कि कौन कहां का है, कहां पैदा हुआ, किस गांव में पैदा हुआ, पिता का क्या नाम है और कहां से शिक्षा प्राप्त की। चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने उस किताब में अपने बाप का नाम नहीं लिखवाया बल्कि यह लिखवा दिया कि चेला स्वामी दयानंद सरस्वती क्योंकि इनको अपने बाप का नाम लिखने में भार्म आती है। चेयरमैन साहब, इनको भार्म आनी चाहिए कि उस किताब में इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं लिखवाया। इसके अलावा यहां हाउस में एक्साइज पालिसी के बारे में भी जिक्र आया। चेयरमैन साहब, मैं स्वामी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब उस समय की जनता पार्टी की सरकार में स्वामी जी होते थे तो इन्होंने भूख हड़ताल की थी और यह कहा था कि मैं पूर्ण न 11-बंदी कराने के लिए गांव-गांव में धरना दूंगा। चेयरमैन साहब, आज ये वही स्वामी जी है चाहे इनके सर पर भाराब की दोघड़ रख कर गांवों की गलियों में घुमा दो, फिर भी नहीं बोलेंगे। चौधरी भजन लाल जी ने इनके नाक में ऐसी नकेल डाल दी है कि ये कहते हैं कि भाराब की पालिसी बहुत अच्छी बनाई है (गोर एवं विघ्न).....

स्वामी आदित्यवे 1: चेयरमैन साहब, माननीय साथी
..... हम क्या करें?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, इसके अलावा स्वामी जी दूसरे एम0एल0एज0 के बारे में कहा करते थे कि एम0एल0ए0 को किसी कारपोरे 11 का चेयरमैन नहीं बनाना

चाहिए। ये खुद मुझे कहा करते थे कि इन चेयरमैनो को हटाओ। इनका बजट के पर बहुत बोझ बढ़ जाता है। चेयरमैन साहब, ये खुद अब एग्री-इंडस्ट्रीज कारपोरे इन के चेयरमैन बने हुए है और विदेशों की सैर करते है और कहते है कि मैं वहां से बड़े आर्डर लाया हूं। चेयरमैन साहब, मैं इनसे पूछता हूं कि कौन से आर्डर लाए है? स्वामी जी जिस कारपोरे इन के चेयरमैन हैं मैंने खुद उस कारपोरे इन का एक बार नहीं, दो-तीन बार हिसाब चैक किया है। वह बिल्कुल ही मरी हुई इंडस्ट्री है और उसके अन्दर घाटा ही घाटा है। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते है कि मैं आर्डर लाया हूं। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा फाईनैस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आपके पास आर्डर लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट आदमी आ गया है। इसलिए जितने बाहर के भाराब के आर्डर मांगने है, स्वामी जी के जिम्मे लगा दें। इनका आर्डर लाने का एक्सपीरियेंस भी है। चेयरमैन साहब, ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से कई सीनियर मैम्बर्ज जिनमें से मैं खास करके चौधरी भाम गोर सिंह सुरजेवाला जी का और भाई बीरेंद्र सिंह का नाम लूंगा क्योंकि बाकी तो उस वक्त भी हमारे साथ थे जिस वक्त ये स्कीमें पिछली गवर्नमेंट ने पास की थी और अब उन्हीं स्कीमों को पास किया जा रहा है, इन दो आदमियों ने खास तौर पर इस बजट की सराहना मेज थपथपा कर की है। लेकिन उस वक्त ये आदमी नो कहने वालों में से थे.....(गोर एवं विघ्न).....

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का.....करवाया जाए कि ये हाउस में..... बोल रहे हैं या वैसे ही बोल रहे हैं.....(गोर एवं विघ्न)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्वामी जी, मेरे कमरे में आ जाना आपको बता दूंगा.....(गोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हमारे स्वामी रामानंद जी ने कहा कि.....(गोर एवं विघ्न)

श्री सभापति: स्वामी रामानंद राम का हाउस में कोई मैम्बर नहीं है, इसलिए आप बैठिए दक मअमतल वदण उमउइमत वनसक इम ककतमैमक चतवचमतसलण (गोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, अभी स्वामी जी ने हमारे आनरेबल मैम्बर चौधरी सतबीर सिंह जी को कहा कि इनका.....कराया जाए कि ये.....बोल रहे हैं। यह कार्यवाही से एक्सपंज होना चाहिए.....(गोर एवं विघ्न)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, जो स्वामी रामानंद जी ने मेरे ऊपर ऐसा ऐलिंगे उन लगाया है..... (गोर एवं विघ्न)

स्वामी आदित्यवे I: सभापति महोदय, मैं यह सच कह रहा हूँ कि ये.....बोल रहे हैं क्योंकि इनको मेरे नाम का ही नहीं पता.....(गोर एवं विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, यह कहना कि.....करवाया जाए, यह बड़ी

अनपार्लियामेंटरी भाशा है, माननीय सदस्य पर एस्प नि है, इन भाब्दों को एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, मैं चौधरी भजन लाल जी से सिफारि करूंगा कि.....(व्यवधान) हां, मैं यह कह रहा था बजट के अन्दर 60 करोड़ का घाटा दिखाई देता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से 'फूड फार वर्क' स्कीम के तहत जो अनाज मिलता है वह कहीं भी दिखाया ही नहीं गया। यह अनाज पी0 डब्ल्यू0 डी0, पब्लिक हैल्थ और दूसरे डिपार्टसमेंट्स के लोगों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है। अगर किसी कारण यह अनाज बंद हो गया जिसकी आ ता सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाई हुई है, तो मुक्ति खड़ी हो जाएगी और जो बजट में पैसा है वह कहां-कहां खर्च करेंगे। अगर इस अनाज को इसमें शामिल किया जाए तो घाटा 70-75 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। यह अनकवर्ड घाटा है। हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है, इसमें 240 करोड़ रुपये की स्कीम बनी है। मैं मुख्य मंत्री साहब से पूछता हूं कि अगर आमदनी के रिसोर्सिज पैदा नहीं करेंगे तो बिना पैसे से डिवैल्पमेंट का क्या खाक करेंगे? 240 करोड़ में से अगर घाटे का रूपया निकाल दिया जाए तो भायद आपके पास डिवैल्पमेंट करने के लिए 60 करोड़ रूपया भी नहीं बचेगा। मैं पूछता हूं कि इस स्टेट का क्या होगा? जो योजनाएं हमने भुरु की थी, आप तो उनकी मुरम्मत भी नहीं करवा सकेंगे, घाटा पूरा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन साहब, इतना बड़ा डैफिसिट होने के कारण क्या है? वित्त मंत्री महोदय सुनने

की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए वे सदन से उठकर चले गये हैं और रामानंद जी को यहां पर छोड़ गए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप वाइड अप करें, आपका टाइम हो गया है। दो मिनट में खत्म करें।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि असल में घाटे का कारण क्या हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्साईज डियूटी की लीकेज होती है। चेयरमैन साहब, यह महकमा मेरे पास भी रहा है। उस वक्त जिस सरकार से हमने चार्ज लिया था उस वक्त एक्साईज डियूटी की कुलैव इन 106 करोड़ से बढ़ाकर साढ़े 119 करोड़ तक पहुंचाई। किसी भी सरकार ने इससे पहले इतनी बड़ी कुलैव इन नहीं की, आप ज्वायंट पंजाब की हिस्ट्री उठाकर देख लें, इतनी बड़ी रिकवरी, एक्साईज एंड टैक्सस इन डिपार्टमेंट की तरफ से कभी नहीं हुई जितनी मेरे टाइम में हुई है। फिनांस मिनिस्टर बैठे नहीं हैं, उठकर चले गये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ.....

औचित्य प्रश्न—

बजट पर आम चर्चा के समय वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री के सदन में उपस्थिति संबंधी

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि बजट पर बहस चल रही है लेकिन सदन में न वित्त मंत्री ह। और न मुख्य मंत्री बैठे हैं। बहस का जवाब वित्त मंत्री ने देना होता है लेकिन

वे सदन में नहीं है, यह सारे सदन का अपमान है। (व्यवधान)
मैं जानती हूँ कि केवल परिवहन मंत्री बैठे हैं लेकिन बहस का
जवाब तो वित्त मंत्री ने देना है, उनका होना जरूरी था। सदन में
मंत्रियों का न बैठना सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसी बात नहीं है। उनका हर समय
बैठना आवेक नहीं है। जो मंत्री बैठे हैं, ये काफी हैं और
उनको रैप्रेजेंट कर रहे हैं। (व्यवधान) Please take your seat.
(Interruption & Noise)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): आन ए प्वायंट आफ
आर्डर। चेयरमैन साहब, मैं और श्री रामपाल सिंह जी ने 1962 से
कई असैम्बलियां देखी हैं। ये नये हैं, इनको ज्ञान नहीं है, बुद्धि
नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि मंत्रियों में से एक मंत्री
जरूरी होता है। इसके बाद बहस का जवाब कोई भी दे सकता
है, चाहे कोई और दे। (व्यवधान)

वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सभापति: चौधरी सतबीर सिंह जी, आपको बोलते
हुए 18 मिनट हो गये हैं। एक-दो मिनट में आप वाइंड अप
करें।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: बहुत अच्छा जी।
चेयरमैन साहब, बजट के डैफिसिट को पूरा करने के लिए मैं वित्त
मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि
सेल्ज टैक्स और एक्ससाईज टैक्स की जो लीकेज होती है, चोरी
होती है उसको रोका जाए। अगर लीकेज बंद हो जाए तो लोगों

पर नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह बात तजुर्बे की बिनां पर कर रहा हूं। असलियत यह है कि रूपये में से 4 आने सेल्ज टैक्स हमें मिलता है, 12 आने की चोरी होती है। अगर सारे टैक्स की वसूली ईमानदारी से कर ली जाए तो मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने की आव यकता नहीं है। लेकिन दूध की बिल्ली रखवाली नहीं कर सकती। आप चोरी को नहीं रोक सकते क्योंकि चोरी भी इन्हीं के आदमी करते है। मुझे भाक है कि आप इस चोरी को नहीं रोक सकेंगे। डैफिसिट को पूरा करने के लिए आपको औस्टेरिटी मैयर्ज अपनाने चाहिए, सरकारी खर्चे को कम करे। ये जो लम्बी-लम्बी कारें चल रही है, यही घाटे के बजट के खास कारण है। चौधरी भजन लाल जी को कैलेंडरों पर फोटो खिंचवाने का बड़ भाोक है। मैं इनसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि फोटो वगैरा कम खिंचवाया करें, बार-बार फोटो खिंचवाकर कैलेंडर छपवाना ठीक नहीं, इससे खर्चा पड़ता है। पहले तो ये महात्मा गांधी के साथ थे, फिर श्री जय प्रका । नारायण के साथ रहे और अब इंदिरा गांधी के साथ रहकर फोटो खिंचवाते है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को डिवैल्पमेंट के कामों पर लगाएं, इस तरह से बरबाद नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति: आप खत्म करें। आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गये है। Plesase wind up now.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: अभी खत्म करता हूं। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, हमने योजना बनाई थी कि 1500 डैरी यूनिट्स लगाये जायेंगे और लड़को को डैरी की ट्रेनिंग भी

दिलाई थी। डेरी के लिए लोगों को बैंकों से पैसे नहीं मिलते थे, इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक केस चलाया था कि कोआप्रेटिव बैंक और मार्गेज बैंक को इकट्ठा किया जाए, पता नहीं यह केस अब किस स्टेज पर है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बैंक हैं, ये बड़े-बड़े आदमियों के लिए है, ये कभी नहीं चाहेगे कि देहात में इंडस्ट्रीज लगे, डेरी का विकास हो और गांव के लोग ऊपर उठें। उस केस का पतर नहीं कहां चला गया, मैं आपसे कहूंगा कि उस केस को निकलवाइए और देहातों के विकास के लिए देहाती डिवैल्पमेंट बैंक बनाये जाएं। (विघन एवं भाोर) इन भाब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

चौधरी ई वर सिंह(गुहला-अनुसूचित जाति): माननीय चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री जी ने 10.3.1980 को जो बजट सदन में पेश किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं इस बजट को गरीबों को हितकारी, पिछड़े वर्ग को हितकारी, कर्मचारियों के हित का बजट तथा छोटे वर्ग के हित का बजट समझता हूं। इस बजट में कोई टैक्स न लगा करके हिन्दुस्तान के अन्दर एक मिसाल कायम की गयी है। इससे पिछड़े वर्ग को खास तौर पर अनुसूचित जातियों को, जो राहत मिली है, वह एक मिसाल है। सभापति महोदय, मैट्रिक से नीचे स्तर के इस वर्ग के छात्रों की वजीफें की दरें आठ रूपये प्रति मास से बढ़ाकर सोलह रूपये प्रति मास कर दी गयी है और मैट्रिक के बाद के स्तर में 15 रूपये से 35 रूपये प्रति मास तक की दरें बढ़ा कर 30 रूपये से 70 रूपये तक प्रतिमास कर दी गयी है। कितनी प्रगति की

बात है? किसान, किसान का नाम लेने से उसके हित की बात नहीं होती। चौधरी चरण सिंह जी प्रधान मंत्री रहे, चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री रहे। उन्होंने अपने समय में किसानों के लिए क्या कुछ कर दिया? क्या उनके पास पावर नहीं थी? सूखी नारेबाजी से किसान की भलाई नहीं हो सकती। इसक अलावा, चेयरमैन साहब, असली किसान वह है जो खेत में काम करता है। क्या मैं बूरा साहब से पूछ सकता हूँ कि उन्होंने कितने दिन खेत में काम किया है? चेयरमैन साहब, असली तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्योंकि खेतों में काम वे करते हैं, फसल वे पकाते हैं, खलिहानों के अन्दर वे काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब अनाज किसान के घर के अन्दर चला जाता है तो उसे अच्छूत समझते हैं, उसे उसका सही हिस्सा नहीं देते। आज वह कर्जदार है, परे ान है और मुसीबतों का सामना कर रहा है। (व्यवधान) बाल्मीकि वे इन्सान हैं, जो सवेरे उठ कर लोगों का गंद उठाते हैं, उनके घरों को साफ-सुथरा रखते हैं। चौधरी देवी लाल जी से हम बार-बार प्रार्थना करते रहे कि आप ग्रामवासी हो, गांवों की समस्याओं को समझते हो, इसलिये कृपा करके पिछड़े वर्ग के ऊपर रहम करो और उनकी इमदाद करो। कई बार वे किसी बात को मान भी जाते थे परन्तु यह चंडाल चौकड़ी जो उनके पीछे लगी रहती थी उन्हें कोई भलाई का काम करने नहीं देती थी। (व्यवधान) बाल्मिकियों को राहत देकर इस सरकार ने हिन्दुस्तान के अन्दर एक मिसाल कायम कर दी है। किसी कर्मचारी की साल के बाद अगर 5 या 10 रूपये की

इंक्लीमेंट लगती है तो वह बहुत बड़ी चीज मानी जाती है लेकिन हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने उन्हें 50 रुपये महीने की राहत देकर के उनके परिवारों की बहुत इमदाद की है। ऐसे वर्ग को, जिसे लताड़ा जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, आर्थिक रूप से सहायता देकर के मुख्य मंत्री जी ने प्रोत्साहनीय काम किया है। सामाजिक रूप से भी उनकी भलाई करने की इस सरकार की नीति है।

चेयरमैन साहब, मुख्य मंत्री जी की नेक नीयती की एक मिसाल में और देना चाहता हूँ। गांव का सबसे छोटा कर्मचारी चौकीदार होता है। वह हर वक्त गांव वालों की सेवा करता रहता है। उसकी भी इन्होंने 100 रुपये तनख्वाह कर दी है। क्या इस तरह की कहीं कोई मिसाल मिल सकती है?

सभापति महोदय, एक बात के बारे में मैं सरकार से जरूर प्रार्थना करूंगा। सरप्लस भूमि को हरिजनों में बांटने का सरकार ने जो कानून बनाया है, उसे ये अवयव इम्पलीमेंट करें। अगर ऐसा सम्भव न हो तो उस कानून को वापिस ले लें ताकि झगड़ेबाजी खत्म हो जाए। हरिजन निगम के बारे में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उसमें विशेष रूप से एक कर्मचारी ऐसा लगाया जाए जो लोगों को यह समझा सके कि कर्जा कैसे लेना चाहिए।

शिक्षा के बारे में भी मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि जिन जे०बी०टी० टीचर्स को एडहाक बेसिज पर काम करते हुए 2 वर्ष से ज्यादा हो गए

है, उन्हें सरकार ने रैगुलर कर दिया है। लेकिन मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि बी०ए०बी०एड० टीचर्स की भर्ती पर जो बैन लगा हुआ है उसे समाप्त करने की कृपा की जाए ताकि हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

चेयरमैन साहब, यह भी खुशखबरी की बात है कि 191 प्राइमरी स्कूल और 158 मिडल स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। लेकिन इसके बारे में भी मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे हल्के का भी विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि वहां अभी केवल दो स्कूल और वे भी लड़कियों के अपग्रेड हुए हैं जबकि दूसरे हल्कों में 14-14, 15-15 स्कूल अपग्रेड हो गए हैं (व्यवधान) चेयरमैन साहब, स्कूलों की बिल्डिंगों पी०डब्ल्यू०डी० को देकर सरकार ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। परन्तु मैं चाहूंगा कि जिन स्कूलों की छतें टूटी हुई हैं, बच्चों को बाहर मैदान में बैठना पड़ता है, बरसात में जो बुरी तरह से टपकती है और जिनसे जान और माल की हानि होने का खतरा है, उनकी छतें जल्दी से जल्दी डलवाई जाएं।

इसके बाद चेयरमैन साहब, मैं परिवहन मंत्री चौधरी जगन्नाथ जी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इनसे मुझे बड़ा गिला है क्योंकि इन्होंने मेरे हल्के के लिए जितनी बसें चलती थी, उनके बोर्ड बदलवा दिए हैं। गुहला नाम की अब कोई बस नहीं चलती। (व्यवधान) मैं बड़े अदब के साथ इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस साल जो 200 नई बसों को खरीदने का प्रावधान किया गया है, उनमें से ज्यादा से ज्यादा बसें मेरे इलाके के लिए दी

जाएं क्योंकि वह एक बोर्डर एरिया है, उम्मीद है कि नया बस अड्डा भी वहां भीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने यह वि वास दिलाया था कि वहां नया बस अड्डा बना दिया जाएगा।

चेयरमैन साहब, कृशि के बारे में भी मैं कुछेक बातें जरूर कहूंगा। मेरा इलाका बोर्डर का इलाका है। सारी जीरी वहां से बाहर जाती है क्योंकि एफ0सी0आई0 उसे लेने के लिए तैयार नहीं होती। चौधरी चरण सिंह जी के टाईम में यह बात हुई। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) सारी की सारी जीरी को चोरी से पंजाब के अन्दर जा कर बेचा गया है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि यह जीरी हरियाणा की मंडियों में बिके।

12.00 बजे अब मैं ला एंड आर्डर के बारे भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे लोकदल के साथी ला एंड आर्डर के बारे में बड़े नारे लगाते हैं। मैं वि वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि भजन लाल की सरकार न होती तो इस लोक सभा के आम इलैक् ान में हरिजनों और बैकवर्ड जातियों के लोगों को बिल्कुल वोट नहीं डालने दी जाती। जबरदस्ती लोगों के वोट डाले गये हैं। लड़को ने लड़कियों के ओढ़ने ओढ़ कर वोट डाले हैं। अगर भजन लाल की सरकार न होती तो घरों से पर्चियां छीन कर वोट डाले जाते।

स्पीकर साहब, यहां ला एंड आर्डर के बारे में बड़े बड़े लम्बे भाशण देते हैं कि उस टाईम पर बड़ी अच्छी हालत थी।

जब देवी लाल जी की गवर्नमेंट होती थी, उस टाइम पर हरियाणा में आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 हरिजन अफसरों में से किसी को न तो डी0सी0 लगाया और न ही एस0पी0 लगाया। हमारी एक भी बात नहीं सुनी। इस प्रकार सारी चीजों की अवहेलना की कि जैसे हरियाणा प्रान्त में कोई भी अन्य जाति के लोग नहीं रहते हैं।

स्पीकर साहब, मेरा अपना क्षेत्र बार्डर का है। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जितनी भी वहां पर माईनर्ज है वे सभी पंजाब के बार्डर से आती हैं जिसके कारण हरियाणा के मेरे इलाके में पानी कम हो जाता है। जब बरसात के मौसम में हमें पानी की आव यकता नहीं होती है तो सारा पानी हरियाणा में छोड़ दिया जाता है। हमें आव यकता होती है तो बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसलिए इस पानी का सही रूप से बंटवारा होना चाहिए।

मेरे एरिया में सड़कों और यातायात के साधनों की भी बड़ी दिक्कत है। बार्डर के एरिया में 37 गांव लगते हैं। वहां पर जो भी पुल बने हुए हैं पंजाब वाले अपने कलेम करते हैं और हरियाणा वाले अपने कलेम करते हैं। पंजाब वाले अपने एरिया में सड़कें बना लेते हैं और बनाई हुई हैं और हरियाणा वाले अपने इलाके में बना लेते हैं लेकिन जो बीच में लिंक है वे वैसे ही पड़े हैं कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं है इससे गांवों के लोगों को बड़ी परे ानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लिंक केवल एक या दो मील के होते हैं। यह बहुत जरूरी चीज है, इस ओर

जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाये। इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): आदरणीय स्पीकर साहब, आज बजट पर बहस चल रहीं है और मैं विरोध पक्ष की ओर से इसका विरोध करते हुए आपके सामने कुछ भाब्द कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, केंद्र में इस वक्त मौजूदा सरकार कांग्रेस आई0 की है उसकी नीति और उसके इ तारे पर ही यहां पर यह घाटे को बजट पे ा किया गया है। जिस तरह से हरियाणा में घाटा दिखाया गया है इसी प्रकार से केंद्र में घाटा दिखाया गया है। जो भी बजट बनाया गया है वह श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच के अनुसार बनाया गया है। कुछ महीनों के प चात इलैक् ान आ रहे है ऐसा इ तारा इस बजट से लगता है कि हरियाणा में भी इलैक् ान आयेंगे मैं आपके जरिए हाउस को बताना चाहता हूं कि बजट के अन्दर बहुत सी चीजे नहीं है जैसे भाहर के नौ किलोमीटर एरिया के अन्दर किसान अगर हरा चारा पैदा करता है तो उस पर टैक्स लगता है। मैंने पिछली बार भी इस बात की प्रार्थना की थी कि यह टैक्स नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत किस्म का टैक्स है। अगर कोई गरीब आदमी आधा एकड़ में भी का त करता है तो उस पर भी यह टैक्स लगता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस टैक्स को खत्म किया जाये।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि बहुत सारे फूड इंस्पैक्टर ऐसे है जो साबत माल के भी सैम्पल भरते है। साबत हल्दी,

धनिया आदि का सैम्पल भर लेते जो कि भरना नहीं चाहिए। पब्लिक जनसे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था और अखबारों में व रेडियो में भी आया था कि साबत चीजों के सैम्पल नहीं भरे जायेंगे, केवल कुटी हुई चीजों के सैम्पल भरे जायेंगे। लेकिन सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। दूसरी बात मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि सिरसा जिले के अन्दर घग्घर नदी है, उससे बाढ़ आती है। उसको रोकने के लिए सरकार ने बांध बांधें है। 15-16 गांवों में रिंग बांध भी बांधे है, वे तो ठीक बांधे गये है लेकिन मेरे अपने हल्के में 15-16 गांव ऐसे भी है जिनको नुकसान से बचाने के लिए नहीं बांधे। अगर इस दफा बड़े जोरों से नाली का पानी आया तो लोगों के लाखों रूपये के अनाज का नुकसान होगा। घग्घर की बाढ़ से बचाने के लिए ये बांध अब य बांधें जाने चाहिए। फसल को बचाने के लिए गांवों में बांध बांधें गये है उनमें दो-अढ़ाई एकड़ जमीन आती है। मेरा कहना यह है कि जितनी जरूरत है उतनी ली जाये उससे ज्यादा न ली जाये ताकि किसानों को नुकसान न हो।

हरियाणा के कर्मचारियों के वेतन के लिए जो आयोग बैठाया गया था अब उसकी रिपोर्ट छप चुकी है। उस रिपोर्ट के अन्दर हरियाणा सरकार के चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पंजाब सरकार या सैंटर सरकार के कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा गया। इस रिपोर्ट में उन कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरता गया है। कई बार चीफ मिनिस्टर ने आम जलसों में, पब्लिक मीटिंगों में यह कहा था कि कर्मचारियों को पूरा न्याय

दिया जायेगा। लेकिन इस रिपोर्ट के देखने से पता लगता है कि इन कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको पंजाब सरकार और सैंटर सरकार के कर्मचारियों के बराबर स्केल दिया जाये।

मेरी आपसे एक अर्ज यह भी है कि हरियाणा के अन्दर जो एम.आई.टी.सी. का महकमा है यह बहुत बड़ा है। एम.आई.टी.सी. की तरफ से अढ़ाई हैक्टोर अगर किसी जमींदार की जमीन हो और उसकी जमीन में खाल बनना हो तो उससे कोई पैसा वसूल नहीं किया जायेगा और अगर उससे ज्यादा किसी की जमीन है तो उससे आधा पैसा वसूल किया जायेगा। इस सरकार ने इस बात का तो एलान कर दिया मगर इसको अभी तक लागू नहीं किया। मेरा यह भी ख्याल है कि जिले के डिप्टी कमि नर को या किसी दूसरे आफिसर को पैसे वसूल ने करने के लिए कोई हिदायत नहीं भेजी गई है। पटवारी, नम्बरदार गांवों के लोगों पर उनसे पैसे वसूल करने के लिए बराबर दबाव डाल रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कई पब्लिक जलसों में कहा था कि जहां पर 50 फीसदी कहत पड़ा है, वहां पर हम इस साल वसूली नहीं करेंगे। तमाम वसूली को मुलतवी कर देंगे। मगर यह वसूली बड़े जोरों से की जा रही हैं। जब हम डिप्टी कमि नर या किसी अन्य अधिकारी को पैसे वसूल न करने के लिए कहते हैं तो अधिकारी हम को कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई कि पैसे वसूल न किए जाए। इतना ही नहीं इसके साथ वहां पर दूसरे कर्जों की भी जोरों से वसूली

की जा रही है। चीफ मिनिस्टर साहब ने रेडियों पर और पब्लिक जलसों में यह कहा था कि वसूली नहीं की जाएगी। मगर जिस व्यक्ति ने को-आप्रेटिव सोसायटी का कर्जा या किसी अन्य किस्म का सरकारी कर्जा लिया हुआ है और वह किसानों की तरफ बकाया है, तो उसे वसूल किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जहां पर कहत पड़ा हुआ है वहां पर हरेक किस्म के कर्जों की वसूली न की जाये।

इस साल भिवानी जिले के अन्दर अकाल पड़ने के कारण कुछ चारा बांटा गया। मुझे मालूम हुआ है कि वह चारा जो बांटा गया है, वह ठीक नहीं था, गलत बांटा गया और वह भी काफी खराब चारा बांटा गया था। लेकिन इसके विपरीत हमारे सिरसा जिले के अन्दर अकाल पड़ने के बावजूद भी वहां पर कोई चारा नहीं बांटा गया। सिरसा जिले के साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। वहां पर गरीब किसानों और देहाती भाइयों को चारा नहीं दिया गया। कई स्कीमें जिला सिरसा के अन्दर चालू करने के लिए पिछली सरकार ने घोशणा की थी। उन स्कीमों को चलाने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल ने एलान किया था। लेकिन अब कुछ स्कीमों पर काम तो चल रहा है, लेकिन काम बड़ी मध्यम गति से चल रहा है। कई स्कीमों पर तो काम अभी तक भी चालू नहीं किया गया है। सिरसा जिले के अन्दर एक दूध का प्लांट बनाया जाना था। लेकिन इस प्लांट को बनाये जाने के लिए अभी तक भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इसी तरह से सिरसा के अन्दर एक बस अड्डा बनाये

जाने के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने ऐलान भी किया था लेकिन अब उसको बनाये जाने के बारे में कोई चर्चा इस बजट के अन्दर नहीं की गई। वहां पर जो बस अड्डा इस वक्त है वह बहुत ही गंदी जगह पर बना हुआ है और रद्दी किस्म का बना हुआ है।

इसी प्रकार से वहां पर एक वाटर वर्कस है। जिस समय सिरसा की आबादी 25 हजार के करीब थी वह उस समय बनाया गया था। अब जब कि वहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है उस वाटर वर्कस से लोगों को पानी की काफी किल्लत रहती है। सी०एम० साहब ने यह एलान किया था कि इस वाटर वर्कस की कैपेसिटी को या तो बढ़ा दिया जाएगा या नया बना दिया जायेगा मगर इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मुख्य मंत्री महोदय, जिला सिरसा के अन्दर गए थे और उन्होंने पब्लिक जलसे में यह एलान किया था कि सिरसा की जितनी भी गंदी बस्तियां हैं, उन सभी का सुधार कर दिया जाएगा। इन बस्तियों के अन्दर कई प्रकार की विभिन्न जातियां रहती हैं। धक्का बस्ती, बंद दरवाजा, हिसार रोड और इस प्रकार कई और जगहों पर ऐसी गंदी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में धानक, बालमिकि तथा और कई निम्न वर्ग की जातियां रहती हैं। परन्तु अब यह पता लगा है कि उन लोगों को 10 रूपये से लेकर 200 रूपये गज में वही बस्तियों की जमीन अलाट की जा रही है। यदि इन निम्न वर्गों की जातियों के साथ न्याय नहीं किया गया तो वे भाहर छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगे।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन जातियों का ध्यान रखा जाये और जिला सिरसा के साथ भेद-भाव की नीति न बरती जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों के साथ-साथ एक बात यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हरियाणा के अन्दर दल-बदली बहुत हो रही है। मैं यह बात कह कर किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। क्योंकि यह तो सारे हिन्दुस्तान में दल-बदली चल रही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। दल-बदली का नाम लेने से बहुत से भाई बिगड़ते हैं। मैं इनकी परिभाशा क्या करूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में कभी भी दल-बदल नहीं किया। इस हाउस के अन्दर भी बहुत से लोग दल-बदलू बैठे हैं। यदि मैं इन सभी के आंकड़ें हाउस को बताऊँ तो हाउस के 88 सदस्यों में से मेरे ख्याल में 7-8 आदमी ही ऐसे बचते हैं जिन्होंने दल न बदला हो। दल-बदल करना तो सारे दे 1 का ही काम हो गया है।

स्पीकर साहब, अब मैं रोड़वेज के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। श्री जगन्नाथ जी ने सवेरे मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि 300 से ज्यादा एडहाक कर्मचारी रोड़वेज से निकाले हुए हैं वे आजकल रोजगार की तला 1 में भटकते फिर रहे हैं। बेकार फिर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से फिर रहे हैं। अभी इन्होंने मार्किट कमेटियों के दो सौ से ज्यादा कर्मचारी निकाल दिए हैं और वे रो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,

हरियाणा के तमाम मास्टर जिनकी डिमाण्ड है कि उनको पंजाब के बराबर तनखाह दी जानी चाहिए, वे आज अपनी मीटिंग करके सरकार को एक मेमोरेण्डम देने जा रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के अन्दर सरकार एक मिनी सेक्रेटेरिएट यानी जिला दफ्तर बना रही है लेकिन उस जिला दफ्तर का काम बहुत धीमा चल रहा है पता नहीं कब बनेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी से पूरा किया जाए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी बहुत जरूरत है। वे सड़कें हैं—फूलकां से कंवरपुरा, हिसार रोड़ से रसूलपुर थौड़ी, सुचान से जोदकां और बैदवाला से बरनाला रोड़। इसके अलावा मेरे हल्के में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक अधूरी पड़ी हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और जो अधूरी सड़कें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में तीन स्कूलों को डिग्रेड कर दिया गया है (व्यवधान)। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको फिर से अपग्रेड किया जाए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए.....

श्री अध्यक्ष: कामरेड साहब, अब आपका टाइम हो गया है। आप खत्म करें।

परिवहन मंत्री(श्री जगन नाथ): अध्यक्ष महोदय क्या कोई ऐसा तरीका है कि सुशमा जी इस घटक से निकलकर इधर आ जाएं (व्यवधान)।

डाक्टर मंगल सैन: एक ही तरीका है कि श्री जगन नाथ असैम्बली ही छोड़ जाएं (व्यवधान)।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, इस सरकार ने इस बजट के अन्दर जो उपलब्धियां दिखाई है.....

श्री अध्यक्ष: भांकर लाल जी अब आप बैठ जाएं। आपका टाईम पूरा हो गया है। (व्यवधान)

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि इस बजट के अन्दर जो उपलब्धियां दिखाई गयी है ये जनता सरकार की उपलब्धियां हैं या कांग्रेस (आई0) की सरकार की है। मैं आखिर में यह कहकर बैठता हूं कि यह जो बजट है यह लोगों को भ्रमित करने वाला है और गरीब लोगों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

चौधरी राजेंद्र सिंह(बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष वर्ष 1980-81 का बजट अनुमान वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है और उस पर हमारे माननीय सदस्य विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बजट सै। न में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्क। न होती है। सदन के हर सदस्य से यह आ।। की जाती है कि वह इस डिस्क। न में अपनी तरफ से बहुत ही सोच विचार कर और ऊंची सूझबूझ के विचार सदन के सम्मुख रखे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट डिस्क। न का सवाल है इसको बहुत ही रचनात्मक रूप में पूरा करने के लिए हमें अपने दे।। की और हरियाणा राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं

कि पिछले वर्ष हमारे हरियाणा प्रदेश में ओला वृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है और करोड़ों रूपए की फसल किसान की नष्ट हो गई। उसके बाद हमारे प्रदेश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर हमारे माननीय सदस्य इस डिस्कशन में हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका जो डिस्कशन होगा वह बड़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय सदस्य डाक्टर मंगल सैन जी और श्री मूलचंद जैन, जो हमारे बड़े पुराने और तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन हैं और जिनके डिस्कशन को और स्टेटमेंट्स को हमारे प्रदेश में बड़े ध्यानपूर्वक देखा जाता है और सुना जाता है इन दोनों ने अपना डिस्कशन केवल दलबदल भाव तक ही सीमित रखा और कुछ देर बोलने के बाद एकदम छलांग मारकर मोरनी हिल पर चढ़ गए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहाँ एक वित्त मंत्री द्वारा इन बजट अनुमानों को सदन के सामने रखने का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी बहुत ही ऊंची सूझबूझ का परिचय दिया है। अध्यक्ष महोदय, किसान के नाम पर, गरीब और मजदूर के नाम पर नारा लगाया जा रहा है। बड़े-बड़े पम्फलेट्स छापे जा रहे हैं और स्टेजों पर भाषण दिए जा रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव रूप से इन पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर अस्सी प्रतिशत लोगों का निर्वाह कृषि से जुड़ा हुआ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि

हमारे प्रदेश में पानी और बिजली का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस बजट के अन्दर, मैं कह सकता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने और मुख्य मंत्री महोदय ने सिंचाई और बिजली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सिंचाई के लिए इस बजट के अन्दर 52 करोड़ 58 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है और बिजली के लिए 71 करोड़ 66 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि किसान की तरक्की के लिए जितना सिंचाई और बिजली के लिए प्रावधान किया गया है उतना इससे पहले नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ जहां तक एस0वाई0एल0 प्रोजैक्ट का सवाल है इसके लिए भी छः करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि एस0वाई0एल0 प्रोजैक्ट पर हमारे हरियाणा निवासियों की आंखें लगी हुई हैं। एस0वाई0एल0 प्रोजैक्ट के साथ हरेक हरियाणवी के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। हरियाणा के लोग पहले से ही आशा रखते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार इस प्रोजैक्ट को पूरा करेगी। मैं समझता हूँ कि चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एस0वाई0एल0 प्रोजैक्ट बहुत जल्दी पूरा होगा और इसका लाभ हमारे सारे हरियाणा निवासियों को मिलेगा।

स्पीकर साहब, इस बजट में बाइस मंडियां बनवाने का जिक्र किया गया है। किसान के रोजाना के जीवन में अनाज मंडियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा के अन्दर जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, बहुत अच्छा उत्पादन है और इसलिए किसान को मंडी के अन्दर अपने अनाज को ले जाने

की सुविधा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। मुझे आता है कि आगे आने वाले समय में यह जो बाइस अनाज की मंडियां हरियाणा प्रदेश में बननी हैं, ये भीघ्र ही पूरी होंगी और हरियाणा के किसान को इनका लाभ भीघ्र ही मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने एक ऐसा सराहनीय काम किया है जो आज से काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सारे हरियाणा के अन्दर कोई सबसे ज्यादा बैकवर्ड और सब से ज्यादा गरीब और कंगाल एरिया है तो उसे मेवात का एरिया कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि हरियाणा के अन्दर अगर कोई सब से मेहनती लोग हैं, मेहनत करके पेट पालने वाले लोग हैं, तो वे हमारे मेवात के इलाके के हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हमारे उस इलाके का सुचारु रूप से कोई डिवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार ने एक मेवात डिवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की है और यह बड़ा ही सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है, इससे हमारे मेवात के इलाके का काफी विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ अब मैं अपने वित्त मंत्री महोदय व अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। ऐसा हमने अनुभव किया है कि हरियाणा सरकार के जितने बड़े-बड़े दफ्तर, कारपोरेट्स चंडीगढ़ में हैं, वहां पर आप जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा कि बड़ी लैंग्वेज मैनटीनैन्स वहां पर कर

रखी है। अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह की डैकोरे इन और मेनटीनैन्स में लाखों रूपया का खर्चा हो रहा है जो बिल्कुल फिजूल है। मैं आपको एक सच्चाई की बात बताता हूँ मेरे साथ मेरे हल्के के कुछ लोग यहां चंडीगढ़ में आए उनको हैफैड के कार्यालय में कुछ काम था। जब वह मेरे साथ यहां पर गये तो उस दफ्तर के अन्दर जाने के वक्त उन्होंने अपनी जूतियां बाहद उतार दीं, मैंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अन्दर आ जाओ, पर वे बेचारे सीधे-साधे किसान यहां की डैकोरे इन और मेनटीनैन्स को देखकर हैरान हो गए। अध्यक्ष महोदय, यही पैसा जोकि यहां खर्च किया जा रहा है, इससे कई गरीब लोगों का भला हो सकता है। इसलिये मेरी अपनी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरह की डैकोरे इन और मेनटीनैन्स पर इतना ज्यादा खर्चा न किया जाए। मैं मानता हूँ कि यहां पर बढ़िया सोफा-सैट अधिकारियों के लिये होना चाहिए परन्तु वे सोफा-सैट 10-10 हजार रूपये की जगह 1-1 हजार रूपये का भी हो सकता है। इस तरह से पैसे की जो बचत होगी, वह स्टेट के गरीब भाईयों, हरिजनों और इस प्रदेश की डिवैल्पमेंट के ऊपर खर्च हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते हुए मेरे माननीय सदस्यों चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और श्री प्रताप सिंह ठाकरान साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा कि हरियाणा रोड़वेज की जो बसिज की बाडीज बिल्डिंग का काम है, उसको बाहर से न करवा करके हमारी हरियाणा सरकार की गुड़गावं में जो वर्क गप है,

उसको कमि यिल बेसिज पर चलाया जाए और इससे हमारी स्टेट का जो लाखों करोड़ों रूपया बाहर जाता है वह हमारे हरियाणा के अन्दर ही रहेगा और उस पैसे से हरियाणा प्रान्त की डिवैल्पमेंट भी होगी। ऐसा करने से हजारों आदमियों को रोजगार मुहैया किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसको सभी लोग महसूस भी करते हैं कि जो एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्राली और कल्टवेटर्ज उन सब की कीमतें काफी बढ़ गई है, जिससे लोग बड़े परे ान है और एक ट्रैक्टर की कीमत बढ़ कर 80 हजार रूपए तक चली गई है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे किसान मेंहनती और ईमानदार है लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त 90 प्रति ात किसान कर्जे के नीचे दबे हुए है। मैं सरकार से व अपने वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे वर्ग पर, जो कि गरीब वर्ग है, जिनपर अब कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, आगे के लिए भी उन पर किसी किस्म का कोई टैक्स न लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बारे में कई भाईयों ने बोलते हुए, कई तरह के एडजेक्टिवज और वि लेशण लगाकर कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर कहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि सेल्ज टैक्स की चोरी जो होती है, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं जब तक कि इस चोरी को नहीं रोका जाएगा, तब तक हमारी स्टेट की डिवैल्पमेंट का काम नहीं हो सकेगा

क्योंकि टैक्सों की चोरी रोकने से स्टेट को काफी फायदा होगा। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कंवल सिंह(धिराये): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री श्री तायल जी ने यह कुछ कागज पढ़े थे, जिनको बजट कहते हैं.....
.....(विध्वन व भाोर).....

वित्त मंत्री(लाला बलवंतराय तायल): कागजों को बजट कह रहे हो भाई? (गोर)

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बजट स्पीच के पेज 11 पर लिखा है कि Agriculture and foodgrains production being the mainstay of Haryana's economy. इरिगे ान, पावर एंड एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी जा रही है। कोई नई चीज इन्होंने नहीं जोड़ी है। जो पिछले साल का बजट था, वह यूहीं का यूही उन्होंने रख दिया है। अलबता मेरे पास फिगरज है जो मैं अभी यहां हाउस के सामने पे ा करता हूँ जो कि इरिगे ान, पावर और एग्रीकल्चर से संबंधित है। इस सरकार ने उन कामों पर, जिन पर पहले ज्यादा पैसा रखा गया था, वह अब घटाया हैं, बढ़ाया नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इरीगे ान के लिये पहले 18 करोड़ राि ा निि चत थी अब वह घटाकर इस सरकार ने 1980-81 में 17.50 करोड़ कर दी है। वाटर कोर्सिज पर एम0आई0टी0सी0 वालों ने 19.23 की जगह 18 करोड़ रूपये की राि ा रखी है और फ्लड कंट्रोल के ऊपर 20 करोड़ की बजाय

19.90 करोड़ की राशि रखी गई है। (व्यवधान) एग्रीकल्चर के लिये 17.48 करोड़ रूपया जो पहले रखा गया था, अब घटा कर 17.46 करोड़ कर दिया गया है। इन्हीं फिगरज से आपको इस सरकार की कारगुजारी का पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, टैक्सिज के बारे में यहां पर जो जिकर नहीं किया गया है कि क्या-क्या टैक्स लगेंगे? लगाने के लिये केवल एक इतारा मात्र सा ही दिया गया है। अगर ये टैक्स लगाएंगे तो मुझे सन्देह है कि ये फारमिंग सैक्टर के ऊपर ही लगाएंगे जिन पर पहले ही टैक्स ज्यादा है। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस प्रदेश को उन्नति के पग पर ले जाना चाहती है तो सबसे पहले हमें अपने फाइनेंसिज की तरफ ध्यान देना होगा और मैं मानता हूं कि प्रदेश के फाइनेंसिज तभी बढ़ेंगे जबकि टैक्स लगाये जाएंगे। यही एक तरीका फाइनेंसिज बढ़ाने का है। लेकिन इस सरकार ने कहीं पर भी अपनी इस के बारे में नीति का कोई जिकर नहीं किया है कि किन-किन व्यक्तियों पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जब से चौधरी भजन लाल जी की हकूमत आयी है, इन्होंने एक तो अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स माफ किया है। (व्यवधान व भाोर) रिपील तो आपके वक्त में हुआ है। हमारे समय में तो यह फैसला हुआ था कि इसकी कुलैवतान की जाएगी। सस्पेंड जरूर किया गया था। एक लाला और बनारसीदास गुप्ता पहले बैठे थे जब उनकी हकूमत टूटन लगी, भागने लगे तो इसको सस्पेंड करके चले गये थे, दूसरा टैक्स उन्होंने सस्पेंड किया था प्रोफैशनल टैक्स। अगर आप ठीक

समझते हों तो आप दोनों को रिवाईव कर दो यह दोनों टैक्सिज अमरी आदमी पर ही लगते हैं। अरबन प्रोपर्टी टैक्स जो है यह अरबन रिच पर है। अगर हमारे वित्त मंत्री महोदय जी की यह कन्टैन्स है कि यह अरबन रिच पर नहीं तो हमें समझा दें। हम समझने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से प्रोफै नल टैक्स के बारे में है। हमारे तायल साहब की एक और होठियायी नजर आयी है। पता नहीं उन्होंने खुद की है, या डिपार्टमेंट वालों से करवायी है। इन्होंने भी इलैक्शन लड़ा है। इनकी पार्टी ने भी इलैक्शन लड़ा है। इलैक्शन में बड़ा पैसा खर्च होता है। तायल साहब ने तो एम0 पी0 का इलैक्शन भी लड़ लिया और साथ ही और भी काफी कुछ कमाई कर ली है। मेरे पास एक किताब है। यह बतलाती है कि टैक्सिज में काफी हेराफेरी हुई है। सेल्ज टैक्स में रिकवरी कम हुई है। यह किताब बतलाती है।

स्पीकर महोदय, स्टेट सेल्ज टैक्स के 49.76 करोड़ के एस्टीमेटस के मुकाबिले मैं रिवाइज्ड एस्टीमेटस 48.11 करोड़ रूपये खर्च हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए।) इसमें 1.65 करोड़ रूपये की तो वैसे ही कमी है और बजट यह दिखाता है कि सेल्ज टैक्स की रियलाइजेशन इसलिये कम हुई है कि स्टेट के अन्दर ड्राउट पड़ गया। अब कई दफा जब सेल्ज टैक्स बढ़ता है तो जायल साहब या वह वर्ग जिसको ये रिप्रजेंट करते हैं कहता है कि हम मारे गये। इन्होंने यह कहा है कि ड्राउट की

वजह से सेल्ज टैक्स की रियलाइजे इन कम हुई है लेकिन ड्राउट की वजह नहीं है। ड्राउट से तो किसान का नुकसान होता है या उससे संबंधित जो कारोबार है उनको नुकसान होता है क्योंकि उनकी पैदावार नहीं होती और मजदूरों की मजदूरी नहीं मिलती। अगर मान लें ड्राउट की वजह से सेल्ज टैक्स की रियलाइजे इन कम हुई है तो सेंट्रल सेल्ज टैक्स की भी रियलाइजे इन कम होनी चाहिए थी। सेंट्रल सेल्ज टैक्स रियलाइजे इन 33.85 करोड़ रुपये होनी थी इतनी एस्टीमेटिड थी लेकिन इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 34.98 करोड़ रुपये है लिहाजा 1.13 करोड़ रुपया फालतू हुआ है। अगर ड्राउट का ही रीजन था तो यह फालतू कैसे हो गया। क्योंकि अगर एक टैक्स की रिकवरी कम हो तो दूसरे की भी कम होगी। इन बातों से तो ऐसा लगता है कि सेल्ज टैक्स में हेराफेरी हुई है। जो 33.85 करोड़ और 34.98 करोड़ रुपये की रे गें बनती है उस हिसाब से अगर 49.76 करोड़ रुपये की रे गें निकाली जाए तो वह 3.28 करोड़ रुपये फालतू यानि 51.40 करोड़ की रिकवरी आनी चाहिए थी लेकिन यह क्यों नहीं आई। यह बात मैं इस किताब से साबित कर चुका हूँ। अगर कोई और बात है तो ये हमें समझा दें। इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि खातों में गड़बड़ करवाई गई है। कन्ज्यूमर्ज से तो सेल्ज टैक्स वसूल हुआ है लेकिन खातों में गड़बड़ हुई है। इसमें किस का हिस्सा था, उसके बारे में तो ये खुद जानते हैं (व्यवधान) इलैव इन फंड की भी बहुत जरूरत

होती है ।.....
(व्यवधान एवं भाोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी मेरे दोस्त सेल्ज टैक्स और सी0एस0टी0 के बारे में फिगर्ज दे रहे थे। मैं अपने साथी को एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि खातों में गड़बड़ की है। मैं इनको बताता हूँ कि जिस आईटम पर सेल्ज टैक्स लगता है उसी आईटम पर सी0एस0टी0 लगता है। अगर सेल्ज टैक्स में गड़बड़ होती है तो सी0एस0टी0 में भी होगी.....(व्यवधान व भाोर)

श्री कंवल सिंह: चेयरमैन साहब, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेरी बात का जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो दे नहीं सके दूसरा आदमी दे रहा है ।.....(व्यवधान व भाोर)

Smt. Sushma Swaraj: On a point of order, Chairman Sahib. I do not know how is he answering? Does he conted that the Finance Minister is inefficient to answer? Kanwal Singh ji has asked the Finance Minister to answer and not Shri Mange Ram Gupta. (Interruptions and Noise)

Mr. Chairman: Mange Ram ji, please take your seat.

श्री कंवल सिंह: चेयरमैन साहब, एम0आई0टी0एस0 जो वाटर कोर्सिज बना रही है उस पर 50 प्रति ात सबसिडी देने का वायदा किया गया था। इन्होंने पब्लिक प्लेटफार्म पर कहा था कि देवीलाल सरकार ने तो यह सबसिडी 30 प्रति ात दी है, हम 50

प्रति त दंगे। लेकिन दिया कुछ नहीं और किसानों से रियलाइजे तन हो रही है और जो अढाई एकड़ पर लगान माफ किया था उसकी भी रियलाइजे तन हो रही है। इन्होंने कहा कि जो वाटर कोर्सिज पक्के करने के लिये रूपया खर्च होगा, उससे 1.37 लाख हैक्टेयर भूमि में इरीगे तन बढ़ेगी। लाइनिंग करने से पानी की अवेलेबिल्टी भी बढ़ जाएगी और इसका नतीजा यह होगा कि सरकार को ज्यादा खेती होने की वजह से रैवैन्यू भी ज्यादा आएगा और ज्यादा रैवैन्यू आने से सरकार की इन्कम बढ़ेगी। इसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सबसिडी दी भी जाती है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पिछले चार सालों में एम0आई0टी0सी0 ने 63.54 करोड़ रूपए खर्च किये तो यह सारा पैसा किसानों से ही आना है क्योंकि इससे जो 20 प्रति त एडी तनल पानी की वजह से रैवैन्यू आएगा वह सरकार को किसान के पैसे से ही आएगा। पैसा किसान का और एडी तनल रैवैन्यू सरकार को आ रहा है। इसलिए अगर सरकार किसान को इस मामले में कुछ राहत दे भी देती तो वह बड़ी मेहरबानी वाली बात नहीं है। इसलिए इनको यह राहत देनी चाहिए लेकिनये इससे भी बैंक आउट कर गये (विघ्न) मंत्री महोदय यह कहते है कि एक साल के लिए हम उनसे यह पैसे नहीं लेंगे (विघ्न) चौधरी देवीलाल ने अगर कुछ नहीं किया तो अब आप कर दो। चेयरमैन साहब, यह जो साल गुजर रहा है इसमें 165 करोड़ रूपए का तो खाली खरीफ का ही हरियाणा के किसान को नुकसान हुआ है। किसान को इतना ज्यादा नुकसान बर्दा त करना पड़ा है और

इसके बावजूद अगर किसी साल अच्छी फसल हो जाती है तो उसको भाव पूरा नहीं मिलता। भाव दिलाने के लिए जितनी कोशिशें की जायें, वे कर सकते हैं ये उतनी भी नहीं करते। अभी पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि गेहूं पर 125 रूपए क्विंटल के हिसाब से खर्च आता है (व्यवधान) चेयरमैन साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो भजन लाल सरकार है और इसके जो वित्त मंत्री तायल साहब हैं ये प्रूव कर चुके हैं कि ये बाई कनविक्ट इन किसानों के खिलाफ हैं। जब पिछले साल हमने वाटर रेट्स में इन्कीज के खिलाफ एजीटेट किया था तो तायल साहब यह कह चुके हैं कि यह जरूर लगना चाहिए। इन्होंने कहा था कि क्योंकि बजट का ज्यादातर पैसा इरीगेशन और इन मामलों पर खर्च होता है इसलिए यह किसानों को ही देना चाहिए। अगर आप इरीगेशन के मामले में एक बार खर्च कर देते हैं तो आगे दासौ साल तक आपका कोई खर्च नहीं होगा और आप दासौ साल तक उससे वाटर रेट रियलाईजेशन कर रहे होंगे। अगर हरियाणा के किसानों के ऊपर नाजायज टैक्स लगाया जाये तो वह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। सरकार अगर कोई टैक्स किसानों के ऊपर लगाना चाहती है तो हम उसे वार्न कर देना चाहते हैं कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं डैफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मांगे राम जी ने कहा कि तरक्की का वही बजट होता है जिसमें डैफिसिट हो। डैफिसिट बजट दिखाने या न दिखाने से फर्क तो तब पड़ता है जब यह यकीन हो कि सेंटर से पैसा मिल जाएगा। लेकिन सेंटर

से तो जितना पैसा मिलना था वह पहले ही इस बजट में शामिल है। इसलिये स्टेट गवर्नमेंट इस डैफिसिट को पूरा करने के लिए या तो स्टेट में टैक्स बढ़ाएगी या और लगाएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोन इस सरकार को मिलने वाला है वह तो सारे का सार इस बजट में आ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे ज्यादा प्रॉमिस हम नहीं कर सकते हैं। अगर वह ज्यादा प्रॉमिस करती है तो उसे भी ऐडिड सरकुलेटन करना पड़ेगा, अपने मीन्स बढ़ाने पड़ेंगे। चेयरमैन साहब, इससे साफ जाहिर होता है कि अपने डैफिसिट बजट को स्टेट गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसलिये या तो वह प्लान को चेंज करेंगे या फिर जनता पर टैक्स लगाएंगे। इसलिये मेरी फाईनैस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि ये हमें जरूर बतायें कि हम कब और किन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं इस सरकार की इन-एफींशियेंस के बारे में कहना चाहता हूँ। एक दिन यहां हाउस में भूगर के बारे में सवाल पूछा गया कि हरियाणा में भूगर की कंजम्पशन कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। चेयरमैन साहब, दूसरे देशों के लोग 100-100 और 200-200 साल आगे तक की प्रोजेक्शन कर लेते हैं और आज जबकि लोग चांद पर भी पहुंच चुके हैं, हमारे नागर साहब, को यह नहीं पता कि हरियाणा में भूगर की कंजम्पशन कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। (विध्वन) चेयरमैन साहब यह रिकार्ड की बात है। नागर साहब ने यह कहा था कि कोई आदमी एक कप

चाय में एक चम्मच चीनी डालता है और कोई दो चम्मच डालता है। इस तरह चीनी की रिक्वायरमेंट का पता नहीं चल सकता। ये इस गवर्नमेंट की आरगुमेंट है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैंने यहां हाउस में एक सवाल एजुके इन डिपार्टमेंट के प्राविं गियलाइज्ड काडर के कलर्कस के बारे में पूछा था तो चौधरी खुर गीद अहमद ने उसके जवाब में कहा कि 1957 से पहले का रिकार्ड हमारे पास नहीं है जबकि वह रिकार्ड उन क्लर्कों के पास था जो उन्होंने इस सरकार को लाकर दे दिया है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि ला-एंड-आर्डर के बारे में यह सरकार कहती है कि उस समय की पहले वाली सरकार के समय में हरिजनों पर जुल्म और अत्याचार हुए हैं। चेयरमैन साहब, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब से हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी की सरकार बनी है और खास करके जब से ये श्रीमती इंदिरा गांधी की भारण में चले गये है, उसके बाद हरियाणा में हरिजनों पर जुल्मों के कम से कम 10 बड़े वाक्यात हो चुके हैं (व्यवधान) चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के अपने हल्के में एक हरिजन बच्चे को उसके घर से बुला कर मार दिया गया। इनके धर्म भाई का नाम लिखने से इन्कार कर दिया गया जिसका कि उस इलाके के सदर थाने में काफी रिकार्ड है और जब वे हरिजन एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के लिए थाने में गए तो उनको एक रात हवालात के अन्दर रखा गया और उस लड़के की डैड बाडी उन हरिजनों को नहीं दी गई। फिर यह सरकार एम0एल0एज0

को कहती है कि आप इन बातों की इनक्वायरी करे। (व्यवधान व भाोर) (घांटी) चेयरमैन साहब, ला एंड आर्डर के बारे में मैं एक बात और कहता हूँ कि फतेहाबाद में एक भागी राम नाम का आदमी था। चौधरी भजन लाल जी के चीफ मिनिस्टर बनते ही उस आदमी ने प्राईम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को एक रजिस्टर्ड लैटर भेजा था कि मुझे इस आदमी से खतरा है। उस समय हरियाणा के राज्यपाल सरदार हरचरण सिंह बराड़ होते थे। जिस दिन उस आदमी का मर्डर किया गया था उस दिन वे फतेहाबाद के अन्दर से गुजर रहे थे और उन्होंने गोली की आवाज सुनी थी। इस आदमी का दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया गया।

आदमपुर हल्के का एक मनफूल सिंह नाम का एक आदमी ट्रक युनियन का प्रैजिडेंट होता था उसको मिस्टीरिया सरकमस्टांसिज में मृत्यु हो गई। इसी तरह से बड़ोपल गांव के सरपंच का भी एक महीने पहले मर्डर हुआ। चेयरमैन साहब, एक मोख राम खीचड़ जो कि 70 साल का बूढ़ा आदमी है उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई और पुनिस वालों ने उसकी कोई सुनाई नहीं की। बाद में रोला मचने पर उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज कर ली गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। चेयरमैन साहब, तायल साहब ऐसे-ऐसे काम चौधरी भजन लाल जी की सरकार में हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, तायल साहब, के हिसार मैं एक बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा था लेकिन कहीं उसको हाई कोर्ट में जाने के लिए ही समय न मिल जाए।

पिछले दिनों भानिवार को हिसार में पुलिस के हजारों सिपाही और बुलडोजर भेज कर एक स्कूल की बिल्डिंग को साफ करवा दिया गया फिर ये कहते हैं कि ला एंड आर्डर की हालत ठीक है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा रही डिफैक्टु इन की बात। डिफैक्टु इन अगर किसी ने किया तो सबसे पहले 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम ने किया जोकि हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुका है। चेयरमैन साहब, आज जो हमारे राष्ट्रपति हैं 1969 के अन्दर उनका नोमिनेट इन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से फाईल किया था। (विधन व भाोर) और उसी आदमी के खिलाफ उन्होंने कनवेंसिंग की और उसको हटवाया। यह सबसे बड़ी डिफैक्टु इन थी। इन भावों के साथ मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट पे किया है उसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बोलने के लिए समय दिया।

श्री इंद्रजीत सिंह(जाटूसाना): चेयरमैन साहब, जो 10 मार्च 1980 को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस हाउस में हरियाणा प्रान्त का बजट पे किया उसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैबिनेट के समय में जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया। यह डैफिसिट बजट जरूर है लेकिन यह प्रूव जरूर करता है कि हमारी सरकार ने डिवलपमेंट के काम किए हैं। डैफिसिट के बारे में इसमें बताया गया है कि इस को किस तरह से पूरा किया जाएगा? चेयरमैन साहब मैं समझता हूँ कि सरकार को डैफिसिट को इकोनोमी बरत कर पूरा

करना चाहिए। इस समय जो कांग्रेस (आई) पार्टी है, यह यूनाइटेड है। इस पार्टी के अन्दर कोई घटकवाद नहीं है। यह पार्टी एक ही नीति और एक ही पालिसी के अन्दर इकट्ठी मिल कर चल रही है। चेयरमैन साहब, उस समय की जनता पार्टी की सरकार में अलग-अलग घटक थे और वे पार्टी को अलग-अलग खींचा करते थे। वह पार्टी इकट्ठी मिलकर नहीं चलती थी। डेफिसिट बजट तो उस पार्टी की सरकार के समय भी होता था और वे कहते थे कि हम इस डेफिसिट को पूरा कर लेंगे। क्योंकि उस पार्टी में अलग-अलग भाखाएं थी, घटकवाद था इसलिए वह सरकार को एक रास्ते पर चलने नहीं देते थे। चेयरमैन साहब, इस वक्त यह सरकार कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार है। सब एक साथ मिलकर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी के नेतृत्व में एक ही लाईन चल रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी की यह सरकार इकोनोमी बरत सकेगी और इस डेफिसिट को पूरा भी कर सकेगी। चेयरमैन साहब, कई बड़े-बड़े साहब, कई बड़े-बड़े लोग हैं उनका अपना विजन है और उनका विजन इनको भी अपनाना चाहिए। चेयरमैन साहब, आप यह जानते हैं कि हरियाणा के अन्दर कई एरियाज ऐस हैं जोकि दूसरों के मुकाबले में बेहतरीन हैं और कई ऐसे हैं जोकि पिछड़े हुए हैं। (व्यवधान व भाोर)

13.00 बजे: चेयरमैन साहब, इस बजट में मेवात इलाके की डिवैल्पमेंट करने के लिए एक मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह बहुत ही अच्छी चीज है। मेवात

का इलाका बहुत ही बैकवर्ड है, इस प्रकार का बोर्ड जरूर बनना चाहिए। लेकिन मेवात के इलाके के अलावा जिला महेंद्रगढ़ के और बैकवर्ड एरियाज है, जिला अम्बाला में नारायणगढ़ तहसील भी बैकवर्ड है, इसी तरह से दूसरे जिलों में और भी इलाके बैकवर्ड है, इन सब के लिए बैकवर्ड डिवैल्पमेंट बोर्ड कायम करना चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के सारे बैकवर्ड एरियाज के लिए, रोडज बनाने के लिए, पानी का इन्तजाम करने के लिए, दूसरे डिवैल्पड इलाकों को निस्बत टाप प्रिआरिटी देनी चाहिए और यह टाप प्रिआरिटी तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक ये इलाके डिवैल्पड इलाकों के बराबर न आ जाए। इसके अलावा एक बात और महेंद्रगढ़ जिले के बारे में सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। महेंद्रगढ़ में 1978 में ओले पड़े थे उस वक्त चौधरी देवीलाल की सरकार थी। चौधरी देवीलाल की सरकार ने ओले से इफैक्टिव किसानों को 100 रूपए फी एकड़ लोन के तौर पर दिए थे। अगले साल 1979 में जब हिसार में ओले पड़े तो चौधरी देवीलाल ने हिसार के किसानों को 300 रूपए फी एकड़ ग्रांट के तौर पर दे दिए थे। आप देखें एक तरफ महेंद्रगढ़ जिले में 100 रूपए लोन और दूसरी तरफ हिसार जिले में 300 रूपए ग्रांट दी गई। इस तरह महेंद्रगढ़ जिले के किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में जो 100 रूपए लोन दिया है इसको वसूल किया न जाए और हिसार जिले की तरह 300 रूपए की ग्रांट दी जाए ताकि दोनों इलाके बराबर आ सकें। दूसरा तरीका यह है कि 100

रूपए को ग्रांट समझा जाए और 200 रूपए और ग्रांट दी जाएं ताकि महेंद्रगढ़ जिले के साथ किया गया भेदभाव दूर किया जा सके।

अब मैं पे-कमी इन के बारे में अर्ज करता हूँ। चेरमैन साहब, कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जिनकी पे बहुत कम थी, सरकार ने पे-कमी इन बैठा कर बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं सरकार को भुकगुजार हूँ लेकिन कमी इन की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही पे-कमी इन की रिपोर्ट को लागू करेगी। इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जुडिरी के बारे में अब य कहना चाहूंगा। अगर डेमोक्रेसी को ठीक तरह से कामयाब करना है तो जुडिरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो लोगों को जस्टिस मिल सकता है। लोगों के सब मामले ईमानदारी से हल होंगे। जुडिरी को इम्पार्ल रखने के लिए दोभांत की पालिसी खत्म करनी चाहिए। पे-कमी इन ने जुडिरी के बारे में जो रिपोर्ट दी हैं, मैं उस पर अपनी बात कह रहा हूँ। अब तक एग्जैक्टिव के एच0सी0एस0 आफिसरज को और जुडिरी को बराबर के पे-स्केल मिलते रहे हैं लेकिन इस पे-कमी इन की रिपोर्ट में एग्जैक्टिव को सिलैव इन ग्रेड दिया गया है लेकिन जुडिरी के पे-स्केल में फर्क डाल दिया है। जहां तक मैं समझता हूँ, जुडिरी को एग्जैक्टिव से ज्यादा पे दी जानी चाहिए क्योंकि एच0सी0एस0 आफिसरज के पास टेलीफोन है, कारें है, मोटर-कार अलाउंसिज मिलते हैं लेकिन

इसके मुकाबले में जुडि ारी के पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुडि ारी इम्पा र्श ल होती है। वह इम्पा र्श ल तभी रह सकती है जब उनको फाइनें ियल सिक्योरिटी हो। पे—कमी ान ने एग्जैक्टिव को जो सिलैक् ान ग्रेड दिया है, वही जुडि ारी का यह हक है और यह तभी इंडिपेंडेंट रह सकती है जब इनका हक बराबर मिलता रहेगा। वैसे तो जुडि ारी के पे—स्केल एग्जैक्टिव से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर सरकार ज्यादा नहीं कर सकती तो कम से कम एग्जैक्टिव के बराबर तो कर दें ताकि ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा सकें।

अब मैं एनिमल हस्बेंडरी के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार को ि ा कर रही है कि ि ाड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कुछ ऐसे काम—धंधों दिए जाएं ताकि वे अपना जीवन आराम से बिता सकें और फाइनें ियल पोजि ान को बेहतरीन बना सकें। पिगरी के काम को ऐसे लोग करते आए हैं जिनको समाज में नीच समझा जाता है। चेयरमैन साहब, एक तरफ हम चाहते हैं कि हरिजन लोग दूसरी जातियों के बराबर आ जाएं और दूसरी तरफ पिगरी के विकास के लिए उन लोगों को ही लोन दे रहे हैं जो सिर्फ या तो ि ाड्यूल्ड कास्टस हैं या बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों पर यह एक स्टिगमा है। पिगरी का काम भुरु से ही ऐसे लोग करते आए हैं जो ि ाड्यूल्ड कास्टस हैं। खास तौर पर बाल्मीकि हरिजन यह काम करते आए हैं। जब तक सरकार दूसरी हाई क्लासिज में पिगरी का काम प्रोमोट नहीं करती तब तक यह स्टिगमा बाल्मिकियों के साथ

चिपका ही रहेगा। पिगरी की डिवैल्पमेंट का काम सिर्फ बालमिकियों में ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में चालू किया जाए और पिगरी के लिए जो लोन सरकार देती है वह सब वर्गों को मिलना चाहिए। पिगरी की डिवैल्पमेंट के लिए सरकार जो लोन देती है उससे तो चार-पांच पिग ही आ सकते हैं। मेरी सरकार से गुजारि है कि कम से कम 12-15 हजार रूपए लोन दिया जाए। (व्यवधान एवं भाोर) जो लोन सरकार देती है उससे चार-पांच पिग आते हैं। बड़े लोग तो यह काम करते ही नहीं छोटे लोग करते हैं। क्योंकि इनके साथ स्टिगमा अटैच है इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस काम को हाई क्लासिज में प्रोमोट किया जाए, लोन की तादाद बढ़ाई जाए ताकि केवल बाल्मीकि ही नहीं, बल्कि हर वर्ग यह काम कर सकें, तभी यह स्टिगमा हट सकता है।

चेयरमैन साहब, महेंद्रगढ़ जिला, इंडस्ट्रीज के लिहाज से काफी बैकवर्ड है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि इस एरिया में हैवी इंडस्ट्रीज सेट-अप की जा सकें। महेंद्रगढ़ में पानी की बहुत कमी है। एस0वाई0एल0 नहर बन जाए फिर तो पानी मिल सकता है लेकिन यह नहर पहले पंजाब के एरिये में बननी है, फिर पानी आएगा और इस काम को कम्प्लीट होते-होते पांच-दस साल लग सकते हैं। यह सही बात है कि जब तक पंजाब नहर नहीं बनाएगा तब तक पानी नहीं आएगा। इसके अलावा जो जवाहर लाल नेहरू कैनल है इसमें पानी नहीं है। चेयरमैन साहब, इस वक्त कहत पड़ा हुआ है। किसानों की

पानी के बिना बुरी हालत है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर पानी नहीं मिलता तो इसका आल्टरनेटिव इन्तजाम यह हो सकता है कि महेंद्रगढ़ जिले में बिजली की कमी को दूर करने के लिए एक थर्मल प्लांट लगाया जाए। इस वक्त वहां पर न पानी है न बिजली है और न ही डीजल है, बिना इन चीजों के कैसे जमींदार गुजारा करेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर थर्मल प्लांट जरूर लगाया जाए ताकि इस पिछड़े हुए इलाके को हरियाणा के डिवैल्पमेंट इलाकों के बराबर लाया जा सके।

चेयरमैन साहब, मैं एक और बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। हमारे इलाके में कैनल खोदी जा रही है। जिन जमींदारों की जमीन उस कैनल में आ गई है उनको सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। एक करोड़ के करीब पैसा है जो अभी तक लोगों को नहीं मिला है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि यह पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए क्योंकि पहले ही कहत पड़ रहा है और जमींदारों की बुरी हालत है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जितने भी दफ्तर हैं—एल0ओ0, एस0सी0, एक्स0ई0एन0 वगैरह के, ये सब रोहतक के अन्दर हैं लोगों को मुआवजा लेने के लिए रोहतक जाना पड़ता है। जब रोहतक जाते हैं तो पहले दफ्तर ही नहीं मिलता और अगर मिल जाता है तो कंसर्ड आफिसर टूर पर होता है। सारा दिन खराब करके वापिस आना पड़ता है, लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार से मेरी दरखास्त है कि एल0ओ0, एस0सी0, एक्स0ई0एन0 वगैरह के सब दफ्तर

चाहे करनाल डिफ्ट कर दिए जाएं और चाहे रिवाड़ी डिफ्ट कर दिए जाए। जिस जिले में कैनाल बन रही है, ये दफ्तर उसी जिले के अन्दर होने चाहिए ताकि लोगों को दूसरे जिलों में जाकर समय बरबाद न करना पड़े। चेयरमैन साहब, इन सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, वर्ष 1980-81 के बजट पर तीन रोज से सदन में चर्चा चल रही है। सत्ताधारी दल की तरफ से बहस के दौरान बार-बार यह बात आई है कि यह कर-विहीन बजट है, इसलिए अपोजिशन के लोग क्या चर्चा करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं सत्ताधारी दल के साथियों से एक बात की गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर वे ऐसा समझते हैं कि इसमें चर्चा के लिए कुछ नहीं है तो रूलिंग पार्टी के केवल दस व्यक्ति अपने समय में से सिर्फ दो-दो मिनट मुझे दे दें ताकि मेरे समय में बीस मिनट और बढ़ जाएं। फिर मैं बताऊंगी कि इसमें बोलने के लिए कितना मसाला है। (विधन) सभापति महोदय, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या बजट की बहस केवल मात्र नए करों तक ही सीमित रहनी चाहिए? सभापति महोदय, क्या हमारे इस प्रदेश के अन्दर अगले साल के लिए बनाई गई योजनाओं से कोई सरोकार नहीं है? क्या उन योजनाओं को बनाते समय उनमें जो-जो खामियां रह गई हैं, उनकी तरफ इतना ध्यान देना, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कौन सी दिक्कत आएगी

उनसे सरकार को आगाह करना, उन योजनाओं को किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में सुझाव देना या उन योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के समय कौन कौन सी माल प्रैक्टिसिज सामने आने का डर है, उनके बारे में सरकार को चेतावनी देना, इस प्रदेश के विधायकों का फर्ज नहीं बनता? क्या ये बातें उनके फर्ज के दायरे में नहीं आती? (विधन) सभापति महोदय, अगर सत्ताधारी दल के सदस्य यह समझते हैं कि इन बातों को प्रदेश के विधायकों के फर्ज के दायरे में न रखकर केवल मात्र जी हजुरी से यह प्रदेश चल सकता है, तो भविष्य की कल्पना करते हुए भी डर लगता है। (व्यवधान व भाोर) सभापति जी अगर मैं यह कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक भी हरियाणा में आ जाए तो उसे भी खुदा के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तो कोई अति योक्ति नहीं होगी क्योंकि जहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं वहां प्रदेश चल रहा है। (विधन व भाोर) इस मैस आफ अफेयर्ज मैं यह कहना पड़ता है कि इसे वाक्या ही खुदा चला रहा है, कोई सरकार नहीं चला रही है। (व्यवधान व भाोर) सभापति महोदय, यह इस बात का नमूना है कि कैसे यह प्रदेश चल रहा है? (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापति: भांति तो अंति में कन्वर्ट हो गई है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: ये तो मेरी बातों को सबटां पिएट कर रहे हैं ताकि लोग ये समझ जाएं कि यह प्रदेश कैसे चल रहा है। (विधन) सभापति महोदय, इस बजट में 31 करोड़ 14 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसके अलावा

पे कमी इन की रिपोर्ट के फलस्वरूप 15 करोड़ रुपये का और घाटा होने की सम्भावना ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से होना बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 14 करोड़ रुपये के घाटे को डाल कर कुल 46.14 करोड़ रुपये का घाटा हो जाएगा लेकिन वित्त मंत्री महोदय 47 पृष्ठों का भाषण पढ़ने के बाद पृष्ठ 47 पर केवल 15 लाईनों के अन्दर बता रहे हैं कि इस घाटे को पूरा करने के उपाय क्या है। यहां भी अगर ठोस सुझाव होते और दृढ़ रूप से यह कहा गया होता कि ये ये मैयर्ज हम लेने जा रहे हैं तो मैं इस सदन में इनको लाखों बधाई देती कि कर भी नहीं लगाए और घाटे को पूरा करने के लिए ठोस सुझाव भी दिए हैं। (विघ्न व भाोर)

श्री सभापति: सुशामा जी, आज एक बात यहां साबित हो गई कि जी, जी का बैरी है।

श्रीमती सुशामा स्वराज: सभापति महोदय, वे तो खुश हो रही हैं। (विघ्न व भाोर) सभापति महोदय, मैं तो कुछ ऐसी बातें कहूंगी कि स्वयं भांति जी डैस्क थपथपाएंगी। मेरी ये दोनों बहिनें बहुत अच्छी हैं। इनकी तो जितनी बढ़ाई की जाए उतनी थोड़ी है। यह तो पार्टी की कुछ मजबूरी है वरना आज मेरे साथ ये इधर बैठी होती। (हंसी)

सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि उन पंद्रह लाईनों में भी घाटे को पूरा करने के लिए जा उपाय बताये हैं, वे भी सुनने योग्य हैं। कहते हैं कि 13 करोड़ रुपये के ऋण जो केंद्र सरकार के लिए हुए हैं उनके बारे में केंद्र सरकार के पास

जाकर हाथ पसारेंगे कि उनकी वसूली मत करो। सभापति महोदय, मुझे यह पूछते हुए हैरानी होती है कि क्या यह वित्त मंत्री का भाषण है या पब्लिक स्टेज पर आम आदमी की कन्वरसेशन है? अच्छा होता अगर वित्त मंत्री महोदय यहां कुछ ठोस बातें लेकर आते कि अपनी कर उगाहने की प्रणाली में फलां चीजें में इम्प्रूव करने जा रहा हूं और सदन को राजया का राजस्व दुगुना करके दिखाऊंगा। सभापति महोदय, हमें 11 घाटे का बजट तैयार करना बड़ी गम्भीर समस्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या 46 करोड़ का घाटा इस तरह की भाब्दावली से पूरा हो सकता है? (विधन व भाोर) मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि कर लगाना अच्छी बात नहीं है। जब मार्च महीना आता है तो लोग कांपना भुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि केंद्र सरकार के बजट में और राज्य सरकार के बजट में करों का प्रावधान होगा। पिछले तीस वर्ष से वे इस तरह के बोझ से दबते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इन हालात में और कर लगाएं जाएं। आवयकता इस बात की है कि उत्पादन बढ़ा कर यथासम्भव वितीय साधन जुटाने पर विचार किया जाए। सभापति महोदय, जहां मैं यह बात कह रही हूं वहां मेरा यह फर्ज भी बन जाता है कि मैं यह बताऊं कि इस घाटे को किस तरह पूरा किया जाए।

एक सदस्य: तायल साहब नोट कर लो।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आपने अच्छा किया जो उन्हें याद दिला दीं मुझे उनसे यह आकायत है कि वे नोट नहीं करते।

श्री सभापति: ये दिल में नोट करते हैं। (हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, अगर ये नोट करते तो सदन में उसका जवाब तो दें। सप्लीमेंटरी बजट पर बोलते हुए मैंने कुछ ठोस बातें सदन के सामने रखी थी लेकिन जवाब देते वक्त जायल साहब ने महज एक बात कहकर कि सुशमा जी ने भावुकतामय तकरीर दी, उन बातों को टाल दिया। इन्होंने यह भी मजाक किया कि सुशमा जी ने जब कभी घर का बजट नहीं बनाया तो राज्य के बजट के बारे में वे क्या कहेंगी? उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुल्कराज आनंद एक माने हुए आर्ट क्रिटिक हैं लेकिन वे एक सीधी रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि पहले कोई घर का बजट बनाए, फिर सरकार के बजट की आलोचना करे। तो मैं वित्त मंत्री जी से इल्तजा करूंगी कि जो सुझाव मैं दे रही हूँ उन्हें वे कृपया नोट करें और अपनी तकरीर में उनका जवाब दें। सभापति महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि चार मोटी-मोटी बातें भी अगर ये मेरी मान लें तो कर लगाएं बिना यह घाटा पूरा हो सकता है। पहली बात है कि सरकार खर्च में कमी करे। सभापति महोदय, सरकारी खर्च बजट भाषण की बढ़िया भाब्दावली से कम नहीं होगा। इसके लिए तो बड़ी कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, कैबिनेट का आकार छोटा करना पड़ेगा। 45 की स्ट्रैन्थ

में से 23 यदि मंत्री हों और उनकी कोठियों, कारों, सैलरी और टी0 ए0, डी0 ए0 आदि पर करोड़ों रूपया खर्च किया जाए तो यह पब्लिक ऐक्सचैकर के ऊपर बड़ा भारी बोझ हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से चाहूंगी कि वे मुख्य मंत्री जी से गुजारि 1 करें कि कैबिनेट का आकार छोटा किजिए, जो मंत्रीगण आज अपने सरकारी बंगले छोड़कर 2,200-2,200 रूपए महीने की कोठियों में रह रहे हैं, उनको उनके लिए बनी उन कोठियों में लाया जाए जहां आज अधिकारी रह रहे हैं, उनके टैलिफोन यात्रा भत्तें आदि के खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जाए क्योंकि charity beings at home. अगर स्वयं मंत्रीगण अपना खर्चा कम करेंगे तभी वे अधिकारियों से कह सकेंगे कि सादगी बरतें।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारी राजस्व उगाहने की प्रणाली दोशपूर्ण है यानि टैक्स रिकवर करने की प्रणाली दोशपूर्ण है। मुझे इस बारे में उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तायल साहब स्वयं ऐसे वर्ग से संबंध रखते हैं कि उन खामियों का पता है। जब इन्सान को किसी चीज की खामियों का पता होता है तो उसको उनको दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। कहते ही हैं कि पहले रोग की नब्ज पकड़ो, डायगनोज हो जाएगा। डायगनोज तो इनका किया हुआ है। इन्हे पता है कि कौन कहां-कहां चोरी करता है। कुछ कानून में खामियां हैं। (विघ्न व भाोर) सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कानून में खामियां न हों। कई बार कर चोरी भी लीगेलाइजड होती हैं। इसलिए मेरी गुजारि 1 यह है कि

हमारे कानून में जो खामियां हैं उनको दूर करके ये एक लक्ष्य निर्धारित करें और राजस्व उगाही को दुगुना करके दिखाएं।

तीसरी बात यह है कि हमारी स्टेट में बड़ी भारी पब्लिक अंडरटेकिंगज चल रही है। पब्लिक सैक्टर में कम्पनियां अगर घाटे में चल रही हैं तो उसके विषय में मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री महोदय उन्हें एग्जामीन करा के एक सैल बनाये ताकि उनको घाटे से उभार कर मुनाफे में लाए जायें अगर सरकार इनके घाटे को बराबर कर दें और आगे से यह मुनाफा लायें तो सरकार को जो घाटा सहन करना पड़ा है उसको पूरा किया जा सकता है।

चौथा सुझाव जिसकी तरफ बाबू मूलचंद जैन ने भी सरकार का ध्यान दिलाया था। फरीदाबाद के अन्दर बहुत सी ऐसी फैक्टरियां हैं जिनके मुख्यालय हरियाणा स्टेट से बाहर हैं। मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 12 हजार 212 फैक्टरियां हैं जिनमें से 335 फैक्टरीज के मुख्यालय बाहर हैं। जब ये आंकड़े आते हैं तो सदन में ऐसा लगता है कि समस्या को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं। हमारे हरियाणा में 22 हजार 212 फैक्टरियों में से केवल सैकड़ों फैक्टरीज के मुख्यालय बाहर हो उनको यहां पर कायम करना सरकार के लिए कोई जटिल समस्या नहीं है। जब सरकार से यह पूछा गया कि वे कौन सी फैक्टरियां हैं तो पता चला कि वे सबसे ज्यादा सैलज टैक्स देने वाली फैक्टरीज हैं, जिनसे सबसे ज्यादा रैवेन्यू सरकार को आ सकता है। लेकिन सभापति जी, बड़ा खेद होता है जब बाबू मूलचंद जैन जी ने यह सुझाव दिया कि इनके दफ्तर यहां

क्यों नहीं बनवाते तो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि केंद्रीय सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बारे में संविधान में संशोधन करें ताकि वे उनके मुख्यालय हरियाणा के अन्दर बनाये जा सकें। चैयरमैन साहब, हमारे पास तो ऐसे साधन हैं जिनकी वजह से हम उनको कह सकते हैं कि आप अपने मुख्यालय यहाँ बनाओ। जब उनकी चीजें व सहूलियतें देते हैं तो उनके माध्यम से उनको कह सकते हैं। लेकिन इस बात पर अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि यह ब्लैकमेल होगा। मुझे खेद है कि जो व्यापारी हमारी स्टेट का लाइसेंस लेता है, कोटा लेता है, हम सबसिडी देते हैं, लोन देते हैं तो हमारी सरकार उनको यह नहीं कह सकती कि आप अपने मुख्यालय हरियाणा में ले आओ। हम उनको कह सकते हैं और उनको लाने चाहिए। जो यह कहा जाता है कि यह ब्लैकमेल होगा, क्या सरकार ने ब्लैकमेल नहीं किया है क्या सारी राजनीति में ब्लैकमेल नहीं हुआ है? ज्यों ही इंदिरा गांधी लोक सभा में चुन कर आयी तो चौधरी भजन लाल को बुला कर कहा कि चौधरी साहब अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो हमारा बन कर रहना होगा वरना आपका बोरियां बिस्तरा बांध दिया जाएगा। सभापति जी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया?

आवाजें: यह कौन कहता है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैंने तो सुना यह है कि उन्होंने यह कहा है अगर आप ने रहना है तो कांग्रेस (आई) का बन कर रहना पड़ेगा वरना आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। सात

तारीख को चुनाव के रिजल्ट आये 15 दिन के ही पचास 22 तारीख को 37 एम0एल0एज0 के साथ मुख्य मंत्री जी ने इंदिरा गांधी जी को समर्पण कर दिया। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो ये फैक्टोरियां तो इनकी इनायत पर हैं। जब एक राजनैतिक दल ने ऐसा किया तो क्या वहां पर संविधान की कोई बात नहीं थी। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस तरह से किसी अन्य दल की सरकार को बदला जायें। अगर केंद्र में कोई अन्य पार्टी की सरकार हो तो प्रदेशों में दूसरी पार्टी की सरकार भी रह सकती हैं। लेकिन उनका यह कहना कि ब्लैकमेल होगा तो क्या यह सरकार ब्लैकमेलिंग की विचार नहीं हुई? जब सारी सुविधाएँ हमारी राज्य सरकार दे रही हैं तो क्या राज्य सरकार का यह हक नहीं बनता कि जो मुनाफा बाहर जा रहा है वह हमें मिले। यह कहां कि इंसानियत है कि सारी सुविधाएँ हमारे से लें और फायदा किसी अन्य को पहुंचाये। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि उनके मुख्यालय यहां होने ही चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को मैंने पिछले तीन वर्षों से देखा है कि उनके अन्दर तो बहुत इच्छा भावित है लेकिन पता नहीं आजकल वे किस मजबूरी में फंसे हैं। वे अपनी मजबूरी से उभरें और अपनी इच्छा भावित का फायदा उठायें। ये बहुत पुराने लीडर हैं। इनके लिए तो यह कहा जाता है कि सारी दुनिया का बाजू एक तरफ है और तायल साहब का बाजू अकेला एक तरफ। पता नहीं उनको भी क्या सता का लालच आ गया या उनको किसी ने जादू टोना कर दिया।

इसलिए मैं गुजारि । करूंगी कि वित्त मंत्री महोदय अपनी इच्छा भावित का फायदा उठा कर सारी की सारी इंडस्ट्रीज के मालिकों को बुला कर कह दें कि या तो अपने मुख्यालय यहां पर ले आओ वरना आपकी छुट्टी कर दी जायेगी। चेयरमैन साहब, हमारी सरकार को 46 करोड़ का घाटा है, इस घाटे को अकेला फरीदाबाद पूरा कर देगा। फरीदाबाद से हमारी स्टेट को 50 करोड़ का रैवैन्यू आ सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जनता वाह-वह करेगी।

चेयरमैन साहब, ये जो चार सुझाव मैंने आज दिये हैं इनकी ओर सरकार ध्यान दें। बहिन भांति जी चाहती है कि मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहूं। चेयरमैन साहब, मुझे समय देंगे तो जरूर कहूंगी। पहले मैं सरकारी कर्मचारियों के विशय में अर्ज करना चाहती हूं। इस बजट स्पीच के पृष्ठ 42 पर सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधायें और राहत दी गई है उनके बारे में सरकार से पूछना चाहती हूं केवल मात्र कुछ व्यक्तियों का राहत दे कर सरकार संतुष्ट करना चाहती है या और कुछ चीजें भी देना चाहती है? एक बात मैं और आपके जरिये अर्ज करना चाहती हूं। वह उदाहरण के रूप में कहना चाहती हूं.....

.(ेम- ेम की आवाजें) क्या इस तरह से प्रदे । की सर्विसिज डिमोरेलाइज नहीं होगी? क्या इस तरह से हमारी पुलिस नौकर ाही का मनोबल नहीं गिरा है? सभापति महोदय मैं केवल मात्र इतना ही कहना चाहती हूं कि.....(विघ्न व भाोर)

श्री सभापति: यह सब—जुडिस केस है इसलिए इसके बारे में कुछ न कहें। ये रिमाक्स एक्सपंज कर दिये जायें।

चौधरी राम लाल वधवा: यह केस सब—जुडिस नहीं है। इसकी इन्वैस्टीगेशन चल रही है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, मैं आपके जरिये पूछना चाहती हूँ कि क्या ईमानदार अफसर को जीने की भी मनाही है, क्या इस प्रदेश की सरकार ईमानदार अफसर को जीने नहीं देगी? मेरी यह बात समझ नहीं आती कि आजकल के मुख्य मंत्री अपनी वफादारी दो दिन में बदल लेते हैं लेकिन सरकारी अधिकारी कैसे इतनी जल्दी अपना चोला बदलें। सभापति महोदय, पिछली सरकार के आदेश पर एक अधिकारी एक केस की ईमानदारी से तफ्ती कर रहा है लेकिन सरकार बदलते ही उसको बेहूदा ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सरकार के मुख्य मंत्री प्रैस कांफ्रेंस में दावा करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

Mr. Chairman: Now the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th March, 1980.

13.30 Hours.

(The Sabha then *adjourned till 14.00 hours on Monday, the 17th March, 1980.)